महानगर नई दिल्ली बुधवार 25 मार्च, 2020, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

आयकर और जीएसटी रिटर्न भरने का समय बढ़ाया गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 मार्च।

कोरोना संक्रमण के कारण लगाई गई पूर्णबंदी से अपने घरों में बंद आम लोगों और उद्योग धंधों के लिए सरकार ने कई तरह के आर्थिक राहत का ऐलान किया है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। दिवाला कानून के तहत कंपनियों को ऋण शोधन कार्यवाही से बचने के लिए आइबीसी नियमों में भी कुछ राहत दी गई है।

लोगों को उनके घर के पास स्थित एटीएम से नकद निकासी की सुविधा देने के लिए दूसरे बैंकों के एटीएम से नकद निकासी पर लगने वाले शुल्क को 30 जून तक के लिए खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी डेबिट कार्ड धारक किसी भी बैंक के एटीएम से कितनी भी बार नकदी की निकासी बिना शुल्क दिए कर सकता है। यह सुविधा 30 जून तक दी गई है। बैंक बचत खातों में न्यूनतम शेष की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है। लोगों को तीन माह के लिए किसी भी बैंक के एटीएम से निशुल्क निकासी की सुविधा दी गई है। अब तक दूसरे बैंक के एटीएम से तय संख्या के बाद लेनदेन करने पर शुल्क काट लिया जाता है।

बैंक बचत खातों में न्यूनतम शेष की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इन राहतों की घोषणा की। स्थानीय खाता संख्या (पैन) को बायोमेट्रिक पहचान संख्या 'आधार' के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष के लिए माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम बाकी पेज 8 पर

कोरोना के कहर की काट के लिए घर की चौखट पर 21 दिन की

मोदी ने खींची लक्ष्मण रेखा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 मार्च।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से कोरोना विषाणु की गंभीरता को समझने और घरों में रहने की अपील करते हुए मंगलवार को 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी पूर्ण बंदी की घोषणा की। यह 15 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्ण बंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जरूरी हर संभव कदम उठा रही हैं। यह पूर्ण बंदी मंगलवार रात 12 बजे से प्रभावी हो गई।

कोरोना विषाणु के प्रकोप को लेकर राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, 'मंगलवार रात12 बजे से पूरे देश में पूर्ण बंदी होने जा रही है।' उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से, घरों से बाहर निकलने पर, पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली-मोहल्ले में अब पूर्ण बंदी (लॉक डाउन) की जा रही है।' उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस पूर्ण बंदी की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी। मोदी ने कहा, 'लेकिन एक-एक भारतीय के जीवन को बचाना इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की, सबसे बड़ी प्राथमिकता है।'

मोदी ने कहा, 'हमें कोरोना विषाणु के फैलने की शृंखला को तोड़ना है। आज के फैसले ने, देशव्यापी पूर्ण बंदी ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी देशों के दो महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है, और विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है- सामाजिक दूरी।

उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है, तो इसके संक्रमण के चक्र को तोड़ना ही होगा। मोदी ने कहा कि कुछ लोग इस गलतफहमी बाकी पेज 8 पर

राष्ट्र के नाम संबोधन की प्रमुख बातें

राष्ट्रव्यापी पूर्ण बंदी 21 दिन की होगी, जो मंगलवार की मध्य रात्रि से लागू हो गई।

केंद्र ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम।

यह पूर्ण बंदी एक तरह का कर्फ्यू है और यह जनता कर्फ्यू के मुकाबले कठोर होगा

प्रधानमंत्री ने एक पोस्टर दिखाते हुए कहा कि 'कोरोना' का मतलब है, 'कोई रोड पर ना निकले।'

देश में रेल सेवाएं अब 14 अप्रैल तक बंद

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली, 24 मार्च।

देश भर में मंगलवार मध्य रात्रि से 21 दिनों के 'लॉकडाउन' की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद भारतीय रेल ने कहा कि उसकी सभी यात्री सेवाएं अब 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी। हालांकि, देश भर में आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए माल ढुलाई जारी रहेगी।

रेलवे ने रविवार को घोषणा की थी कि 22 मार्च से 31 मार्च तक इसकी सभी यात्री सेवाएं बंद रहेंगी और सिर्फ मालगाड़ियां ही इस दौरान चलेंगी। इस निलंबन में सभी उपनगरीय ट्रेन सेवाएं भी शामिल बाकी पेज 8 पर

दिल्ली में दूसरी मौत, देश में संक्रमित लोगों की संख्या 500 पार

मंगलवार को प्रयागराज का सूना संगम।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 मार्च।

भारत में कोरोना विषाणु संक्रमण के मंगलवार को 51 नए मामले सामने आने के बाद अब तक 519 लोग संक्रमित हो गए हैं, जिनमें 43 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक देश 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को दूसरी मौत हुई। स्वास्थ्य बाकी पेज 8 पर

गृह मंत्रालय के कड़े दिशा निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकहाउन को लागू कराने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया है जिसके तहत किसी भी उल्लंघन के लिए दो साल तक की कैद हो सकती है। मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के कार्यालय, स्वायत्त संस्थान, सार्वजनिक निगम, वाणिज्यिक, निजी, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक, बीमा कार्यालय, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे। सभी परिवहन सेवाएं - हवाई, रेल और रोडवेज सेवाएं - तीन सप्ताह की अवधि के दौरान स्थगित रहेंगी।

भारत के पास है संक्रमण पर काबू पाने की क्षमता : डब्लूएचओ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 मार्च।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने कहा है कि चेचक और पोलियो के उन्मूलन में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भारत के पास कोरोना वायरस संक्रमण से पैदा हुई घातक वैश्विक महामारी से पार पाने की भी जबरदस्त क्षमता है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दुनियाभर में लगभग 15,000 लोगों की जान जा चुकी है।

माइकल रेयान

डब्लूएचओ के कार्यकारी निदेशक माइकल रेयान ने कहा कि दुनिया का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत कोरोना वायरस महामारी से निपटने की जबरदस्त क्षमता रखता है, क्योंकि उसे लक्षित वर्ग को लेकर किए गए प्रयासों के जरिए चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन करने का अनुभव है।

वैश्विक महामारी कोविड-19 पर सोमवार को जिनेवा में उन्होंने कहा, 'इन दो रोगों के उन्मूलन में भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया और देश से उनका खात्मा किया।' उन्होंने कहा, 'लक्षित वर्ग को लेकर किए गए प्रयासों के साथ भारत ने चेचक को बाकी पेज 8 पर

तोक्यो ओलंपिक

अगले साल गर्मियों तक के लिए स्थगित

तोक्यो, 24 मार्च (एएफपी)।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि विश्व भर में फैली कोरोना वायरस महामारी के कारण तोक्यो ओलंपिक खेल 2020 को अगले साल गर्मियों तक के लिये स्थगित कर दिया गया है।

पूर्व कार्यक्रम के अनुसार इन खेलों का आयोजन 24 जुलाई से नौ अगस्त के बीच होना था लेकिन आइओसी अध्यक्ष थामस बाक और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच टेलीफोन पर बाकी पेज 8 पर

शिंजो आबे

खिलाड़ियों, ओलंपिक खेलों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया निर्णय।

तोक्यो ने खेलों की मेजबानी पर 12 अरब 60 करोड़ डॉलर खर्च किया है और इसके ताजा बजट को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि खेलों को स्थगित करने से छह अरब डॉलर का अतिरिक्त खर्चा होगा।

इन खेलों का आयोजन 24 जुलाई से नौ अगस्त के बीच होना था।

खबर पेज 3 पर

प्रदर्शन शाहीन बाग में प्रदर्शन को समाप्त कराती पुलिस।

उमर अब्दुल्ला आठ महीने बाद हिरासत से रिहा

श्रीनगर, 24 मार्च (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लगभग आठ महीने बाद मंगलवार को हिरासत से रिहा कर दिया गया। जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत लगाए गए आरोप हटाए जाने के बाद उनकी रिहाई का आदेश जारी किया गया था। उनकी रिहाई के बाद उनके आवास के बाहर मास्क लगाए मीडियाकर्मी और समर्थक उनका इंतजार करते दिखे।

गत 10 मार्च को 50 साल के हुए अब्दुल्ला ने पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद 232 दिन हिरासत में गुजारे। नेशनल कांफ्रेंस के नेता को पूर्व में एहतियातन हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में पांच फरवरी को उन पर पीएसए लगा दिया गया था।

उमर पर पीएसए के तहत लगाए गए आरोप हटाने का आदेश गृह सचिव शालीन काबरा की ओर से जारी किया गया। आदेश में कहा बाकी पेज 8 पर

शिवराज चौहान सरकार ने विश्वास मत हासिल किया

भोपाल, 24 मार्च (भाषा)।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विश्वास मत हासिल किया।

विधानसभा में भाजपा सरकार ने विश्वास मत ध्वनिमत के जरिए हासिल किया। हालांकि इस दौरान सदन में विपक्षी दल कांग्रेस का कोई विधायक उपस्थित नहीं था।

सदन की संक्षिप्त बैठक में चौहान ने एक पंक्ति का विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन में मौजूद सत्तापक्ष भाजपा, निर्दलीय व अन्य विधायकों ने ध्वनिमत से अपना समर्थन दिया। स्पीकर की जिम्मेदारी संभाल रहे वरिष्ठ विधायक जगदीश देवड़ा ने सरकार द्वारा विश्वास मत हासिल किए जाने की घोषणा की और इसके बाद सदन की कार्यवाही 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, मंगलवार सुबह भाजपा ने अपने विधायकों को विप जारी कर विश्वास मत के पक्ष में मत देने को कहा था। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा बाकी पेज 8 पर

सीआरपीएफ शिविर में दो जवानों ने एक-दूसरे को गोली मारी, मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 मार्च।

श्रीनगर स्थित सीआरपीएफ के वाटर विंग शिविर में 114 वीं बटालियन के दो जवानों ने एक-दूसरे पर रंजिशन गोलियां बरसाईं। इस वारदात में दोनों की मौत हो गई है। श्रीनगर में डल झील के पास बने सीआरपीएफ कैंप में दोनों जवान ड्यूटी पर थे। दोनों में मंगलवार दोपहर को विवाद शुरू हुआ, जो झगड़े में बदल गया

इस विवाद में एक जवान ने अपने साथी गोलियां दाग दीं। दूसरे ने भी जवाबी हमला किया। दोनों की मौत हो गई। फिलहाल, पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, श्रीनगर में डल झील के पास सीआरपीएफ का वाटर विंग कैंप है। यहां तैनात दो जवानों के बीच मंगलवार दोपहर को किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। इसके बाद विवाद बढ़ने पर एक जवान ने दूसरे पर गोलीबारी कर दी। दोनों जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मारे गए जवानों के नाम सिजू और जय विजय हैं। दोनों ही सीआरपीएफ में कॉन्स्टेबल थे। सीआरपीएफ के एक अधिकारी बताया कि मारे गए दोनों जवान एक साथ ड्यूटी पर तैनात थे।

दरअसल

अमेरिका में एक ही दिन में 10 हजार से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए | विषाणु का कहर | चीन की स्थानीय आबादी में सिर्फ चार नए मामले सामने आए

अब कोरोना का अमेरिका पर धावा, चीन में काबू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 मार्च।

कोरोना विषाणु का प्रकोप अमेरिका बढ़ रहा है। दूसरी ओर, चीन में संक्रमण के काबू में आने के संकेत मिल रहे हैं। मंगलवार को अमेरिका में एक ही दिन में 10 हजार से ज्यादा पुष्ट मामले सामने आए। दूसरी ओर, चीन की स्थानीय आबादी में कोरोना संक्रमण के सिर्फ चार नए मामले सामने आए। हालांकि, चार के अलावा 74 और मामले ऐसे सामने आए, जो विदेशों से संक्रमण लेकर पहुंचे हैं।

अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 43,734 हो गई है। अमेरिका में पहली बार कोरोना वायरस के कारण एक दिन में 130 से अधिक मौतें हुईं, जिससे सोमवार रात तक इस घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 550 हो गई। विश्व में कोविड-19 मामलों को संकलित करने वाली वेबसाइट 'वर्ल्डोमीटर' के अनुसार सोमवार तक अमेरिका में 10,000 से अधिक एक दिन में बढ़े। दूसरी ओर, चीन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 से सात और लोगों की मौत की बाद मृतकों की संख्या 3,277 हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) ने मंगलवार को बताया कि बाकी पेज 8 पर

अमेरिका में क्या हालात

- सोमवार को 130 से ज्यादा मौतें
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण चिकित्सा सामान की आपूर्ति और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की जमाखोरी रोकने के लिए आदेश जारी किए
- ट्रंप ने मौजूदा दवाओं के लिए नैदानिक परीक्षण न्यूयॉर्क में शुरू होने का ऐलान किया

चीन में क्या हालात

- चार के अलावा 74 और मामले ऐसे सामने आए, जो विदेशों से संक्रमण लेकर पहुंचे हैं।
- चीन में से सात और लोगों की मौत की बाद मृतकों की संख्या 3,277 पहुंची
- प्रतिबंधों में ढील, वुहान समेत पूरे चीन में विषाणु के प्रसार पर नियंत्रण का दावा
- ह्युवेई प्रांत में पांच करोड़ से ज्यादा आबादी पर लागू पूर्ण बंदी को बुधवार को खत्म होगी
- वुहान में आठ अप्रैल को खत्म होगी पूर्ण बंदी

चीन में हंता विषाणु से व्यक्ति की मौत

बेजिंग, 24 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी का रूप अख्तियार करने के बीच चीन के दक्षिण पश्चिम युन्नान प्रांत में चूहों से फैलने वाली बीमारी हंता वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया है कि सोमवार को एक चार्टर्ड बस से पूर्वी शानडोंग प्रांत से लौटते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई।

www.readwhere.com

कोरोना बंदी के दौरान मंगलवार को सूना पड़ा पटना रेलवे स्टेशन।

महबूबा सहित हिरासत में रखे गए अन्य लोगों को रिहा किया जाए : उमर

फिलहाल कोरोना से लड़ाई पर ध्यान, राजनीतिक घटनाक्रमों पर बाद में बात होगी

श्रीनगर, 24 मार्च (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय हिरासत में लिए गए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को रिहा होने के बाद कहा कि इस केंद्रशासित प्रदेश के भीतर एवं बाहर हिरासत में रखे गए लोगों की रिहाई के साथ ही हाईस्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की जाए।

हिरासत से बाहर आए अपने आवास के बाहर उमर ने संवाददाताओं से कहा कहा, करीब आठ महीनों के बाद मैंने अपने माता-पिता के साथ दोपहर का खाना खाया। मुझे इससे बेहतर खाना याद नहीं आ रहा। उमर ने यह भी कहा कि उनके लिए यह एक अलग दुनिया है तथा फिलहाल कोरोना विषाणु के संकट से लड़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है और राजनीतिक घटनाक्रमों पर बाद में बात हो सकती है। उन्होंने अपने आवास के बाहर संवाददाताओं से कहा, पिछले साल पांच अगस्त को जो हुआ और यहां के राजनीति एवं हालात पर विस्तार से बात करूंगा। परंतु पहले कोरोना से निपटने दीजिए। हमें खुद को, परिवार एवं दोस्तों को बचाना है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता ने कहा, मैं चाहता हूं कि राज्य के भीतर एवं बाहर हिरासत में रखे गए लोगों पर केंद्र दया दिखाए और उन्हें रिहा करे। उमर ने कहा कि कोरोना विषाणु के संकट से पैदा हुए हालात के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित हिरासत में मौजूद सभी लोगों को रिहा किया जाना चाहिए।

उनके मुताबिक पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन फिलहाल इस बारे में बात करना ठीक नहीं है क्योंकि लोग कोरोना की वजह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारे बच्चे कई महीनों तक स्कूल नहीं जा सके। दुकानदारों की महीनों से कमाई नहीं हुई। मैंने सोचा था कि इस बारे में बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन लगा कि हम एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। यह जिंदगी और मौत की जंग है। उमर ने सरकार से आग्रह किया कि जम्मू-कश्मीर में हाईस्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की जाए।

जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए गए उमर को करीब आठ महीने बाद मंगलवार को रिहा किया गया। उनके पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को गत 13 मार्च को रिहा किया गया था।

शैक्षणिक संस्थानों के खाली भवनों को पृथक केंद्र में तब्दील करने का आग्रह

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर कक्षाएं व परीक्षाएं स्थगित होने के बीच राज्यों के प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे अपने खाली छात्रावासों को पृथक केंद्र के तौर पर उपयोग करने की अनुमति दें। प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) बम्बई ऐसा पहला संस्थान है जिसने इस आग्रह को स्वीकार किया है और इसके चार छात्रावासों व गेस्ट हाउस को पृथक केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

आइआइटी बम्बई की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, 'कार्यकारी आदेश के माध्यम से कलेक्टर ने परिसर की कई इमारतों को 'सी' श्रेणी के संदिग्ध अर्थात जो संक्रमित नहीं हैं और विदेश से लौटे हैं, के लिए अधिग्रहित किया है।' इसमें कहा गया कि इन अधिग्रहित इमारतों में वन विहार गेस्ट हाउस, एच-18 के साथ एच-8 (बी विंग) और एमटीएनएल गेस्ट रूम हैं। हालांकि, दिल्ली प्राधिकार की ओर से किए गए इसी प्रकार के आग्रह को आइआइटी दिल्ली ने अस्वीकार कर दियाा था और कहा था कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के छात्र अपने घरों को चले गए हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय छात्र छात्रावास में मौजूद हैं।

बहरहाल, तेलंगाना के मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में छात्रों व शिक्षकों के विरोध के बावजूद पृथक केंद्र स्थापित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्विवद्यालय ने कोविड-19 के संदिग्ध व पुष्ट मामलों के लिए पृथक केंद्र खोले हैं, जहां 150 लोगों को रखा जा सकता है। इसी प्रकार से डॉ. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद ने भी इसी प्रकार का सुविधा केंद्र खोला है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता संजा शिंदे ने कहा, 'जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के मद्देनजर विश्वविद्यालय के छात्रावास को पृथक केंद्र के रूप में उपयोग करने के बारे में संपर्क किया था और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं।' कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं व परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित हैं। इससे पहले सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नवोदय विद्यालयों को निर्देश दिया था कि वे अपने खाली छात्रावासों को चिकित्सा सुविधा उपयोग के लिए स्थानीय प्रशासन को दें।

कमलनाथ मिले मुख्यमंत्री चौहान से, विकास के लिए सहयोग का आश्वासन

भोपाल, 24 मार्च (भाषा)।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को यहां अपने उत्तराधिकारी शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश के विकास के लिए विपक्षी दल कांग्रेस के सहयोग का आश्वासन दिया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चौहान से उनके निवास पर मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, 'मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिह चौहान से मिला। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि प्रदेश के विकास के लिए हम उनके साथ हैं।' मंगलवार को चौहान के विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के वक्त कांग्रेस सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि उन्हें सत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, 'विश्वास मत औपचारिकता थी जिसे पूरा करने की जरुरत थी।'

एनबीएफ की केंद्र से डीडी फ्री डिश पर समाचार चैनलों के शुल्क माफ करने की अपील

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ) ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार से डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर समाचार चैनलों के लिए मार्च और अप्रैल का शुल्क माफ करने की अपील की है। एनबीएफ ने कहा कि बंद संबंधी उपायों के चलते भुगतान कम जुटने से नकदी का प्रवाह प्रभावित हुआ है क्योंकि ग्राहकों ने अपने कारोबार में कमी की है।

इसने कहा, 'ठीक उसी वक्त, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लॉकडाउन के चलते संपर्क व संचार पर प्रचालन लागत बहुत बढ़ गया है।' आर्थिक असर से पार पाने के लिए एनबीएफ ने सरकार से जीएसटी दर और दाखिल करने की तिथि समेत अन्य कर छूट देने, टीडीएस भुगतान की अंतिम तिथि कम से कम तीन महीने यानि 30 जून तक टालने का अनुरोध किया है।

फेडरेशन ने डीडी फ्री डिश मंच पर उपलब्ध सामाचार चैनलों का मार्च और अप्रैल के लिए शुक्ल माफ करने को भी कहा है। डीडी फ्री डिश डीटीएच मंच का स्वामित्व व प्रचालन अधिकार प्रसार भारती (दूरदर्शन) को प्राप्त है और भारत में तीन करोड़ घरों में इसकी सेवा ली जाती है।

एनबीएफ ने अनुपालन संबंधी विषयों के लिए भी समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया है क्योंकि नियामक मुद्दों को देख रहे कर्मचारी वर्तमान में घर से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, वित्त मंत्रालय, जीएसटी परिषद, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और दूरसंचार विभाग को सौंपे ज्ञापन में एनबीएफ ने समाचार प्रसारण क्षेत्र पर पड़े रहे आर्थिक व कारोबारी प्रभाव से निपटने के लिए सरकार के हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।

लोग अगर अनावश्यक बाहर आएंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी : येदियुरप्पा

बंगलुरु/अमरावती, 24 मार्च (भाषा)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मंगलवार को चेतावनी दी कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए निर्देशों का उल्लंघन कर अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमने और कानून का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

येदियुरप्पा ने कहा कि अगर वे कानून का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोमवार की रात पूरे राज्य में इस महीने के अंत तक पूर्ण बंद की घोषणा की थी।

इस बीच तेलुगुदेशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने मांग की कि केंद्र सरकार को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक मॉस्क और सेनिटाइजर जैसे आवश्यक उत्पादों पर कर को माफ करना चाहिए। उन्होंने केरल सरकार की तरह एक विशेष पैकेज की भी मांग की। उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत श्रमिकों के लिए मुआवजे की भी मांग की।

केरल सरकार पहले ही 20 करोड़ रुपए के पैकेज और लाभार्थियों को दो महीने की पेंशन देने की घोषणा कर चुकी है।

इस बीच महाराष्ट्र के पुणे से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को पुणे शहर में पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री को रोकने का फैसला किया है। जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने जिला पेट्रोल/डीजल पंप एसोसिएशन को संबोधित महामारी रोग अधिनियम के तहत इस आशय की एक अधिसूचना जारी की। आदेश में यह नहीं बताया गया है कि प्रतिबंध कितने समय तक लागू रहेगा।

चाय नहीं मिलने पर पृथक रखे गए व्यक्ति ने नर्स पर किया हमला

तिरुवनंतपुरम, 24 मार्च (भाषा)।

केरल में चाय नहीं मिलने पर खाड़ी देश से लौटे एक व्यक्ति ने पृथक वार्ड में एक नर्स पर हमला कर दिया। वहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जब एक व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की सूचना अधिकारी को दी, तब उसने कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने इन दोनों अलग-अलग घटनाओं में मामले दर्ज किए हैं।

खाड़ी देश से लौटे व्यक्ति को कोल्लम के एक अस्पताल में पृथक वार्ड में रखा गया है, उसने एक कप चाय के लिए अपना आपा खो दिया। वह चाय पीना चाहता था, लेकिन उसकी देखभाल करने वाली नर्सों ने उसके परिवार को फोन पर इस बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक उसके परिवार के सदस्य जब चाय लेकर नहीं आए, तब यह युवक कथित तौर पर गुस्से में आ गया और एक स्वास्थ्यकर्मी व नर्स पर हमला कर दिया।

मस्कट से लौटे इस व्यक्ति को रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि घर में पृथक रखा गया यह व्यक्ति बाहर घूमता पाया गया है। इस व्यक्ति को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है।

वहीं, एक अन्य मामले में खाड़ी देश से लौटा 27 वर्षीय व्यक्ति एक आशा कार्यकर्ता के घर में घुस गया और उसे थप्पड़ मारा और उस पर हमला किया। व्यक्ति का यह कहना था कि आशा कार्यकर्ता ने उसके बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी दी है। महिला को काफी चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस के फैलने के बाद से महिला पिछले दो हफ्ते से बगैर किसी छुट्टी के काम पर थी। वहीं, नौ मई को केरल लौटा यह व्यक्ति 14 दिनों के स्व-पृथक नियम का पालन किए बगैर बाहर घूम रहा था।

कोरोना : जम्मू में ओपीडी सेवाएं आज से निलंबित

जम्मू, 24 मार्च (भाषा)।

कोरोना विषाणु के संकट के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) और इससे संबद्ध अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवा को 25 मार्च से अगले आदेश तक निलंबित करने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। उधर जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिसकर्मियों को कोरोना विषाणु के प्रसार से उत्पन्न ताजा हालात को संभालने में बेहद सावधान रहने की सलाह दी है।

विज्ञप्ति में कहा गया, कोरोना विषाणु के कारण मौजूदा स्थिति और इसके प्रसार को रोकने के मद्देनजर उपलब्ध कर्मियों और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल तथा संदिग्ध या पुष्ट मरीजों के इलाज के लिए फैसला किया गया है कि जीएमसी और इससे जुड़े अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं 25 मार्च से अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी। जीएमसी प्रशासन ने जम्मू खंड के आम लोगों से जीएमसी और इससे संबद्ध अस्पताल की ओपीडी में नहीं जाने और वेबसाइट पर उपलब्ध सूचीबद्ध डॉक्टरों से फोन पर सलाह लेने के लिए कहा है।

वहीं जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, ह्यजम्मू और कश्मीर पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कठिन परिस्थितियों को संभालने में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है, लोगों के सहयोग से हम इस बीमारी के प्रसार को रोकने के मिशन में भी सफल होंगे। वह यहां पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। डीजीपी ने उन अधिकारियों और जवानों की भूमिका की सराहना की जिन्हें जमीनी स्तर पर कोरोना विषाणु से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति से निपटने के दौरान सभी कर्मियों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है।

प्रियंका ने यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शहर एवं जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे कोरोना विषाणु के संकट को देखते हुए लोगों की मदद करें तथा इस संदर्भ में लोगों को सावधानी बरतने के लिए सतर्क करें।

जिला एवं शहर कांग्रेस अध्यक्षों को लिखे पत्र में प्रियंका ने कहा, कोरोना विषाणु एक वैश्विक महामारी है। हमारा देश भी इसकी चपेट में आ गया है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस विषाणु से लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब बहुत सतर्क और जागरूक रहें तथा इस विपत्ति से निपटने में एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने कहा, अपने हर ब्लाक/वार्ड के चुनिंदा कार्यकर्ताओं को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें ताकि हर ब्लाक/वार्ड की स्थितियों की जानकारी मिलती रहे। किसी व्यक्ति में बीमारी के लक्षण दिखते ही उसे जांच करवाने के लिए प्रेरित करें।

कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका ने कहा, किसी भी पीड़ित की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें ताकि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद की जा सके। पीड़ित और उसके परिवार को कोरोना विषाणु के संक्रमण के बारे में सही जानकारी और इससे बचने के नियमों की जानकारी व्हाट्सएप या फोन कॉल द्वारा पहुंचाएं। ब्लॉक/वार्ड के बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों की लिस्ट बनाएं और उनकी खास मदद करें। उन्होंने पत्र में कहा है कि सरकार द्वारा घोषित पूर्णबंदी, कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिग और अन्य निर्देशों का सख्ती से पालन करें और इसे लागू करवाने में प्रशासन की पूरी मदद करें।

प्रियंका ने कहा, यह हमारे देश के लिए अभूतपूर्व संकट का समय है। ऐसे समय में हम सब को अपने-अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर, समस्त समाज की भलाई के लिए, विभाजनों और राजनीतिक मतभिन्नता को पीछे छोड़ कर हर एक देशवासी की सहायता और रखवाली करने की आवश्यकता है। यह समय मानवता की सेवा और राष्ट्रभक्ति की सच्ची और सर्वोच्च भावना को जीवन में उतारने का है।

कोरोना के इलाज का खर्च आयुष्मान योजना में संभव

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

कोरोना के संक्रमण के परीक्षण और इलाज के खर्च को सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के दायरे में लाने की जल्द ही घोषणा की जा सकती है।

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का संचालन करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कोरोना के संक्रमण के परीक्षण और इलाज के खर्च को इस योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है। अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण की नियामक इकाई से इस फैसले को लागू करने की अनुमति मांगी गई है।

उन्होंने बताया कि इसकी मंजूरी मिलने और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की सरकार से अनुमति मिलने के बाद इसके परीक्षण और इलाज के खर्च को आयुष्मान भारत योजना के स्वास्थ्य बीमा पैकेज में शामिल कर दिया जाएगा।

पूर्ण बंदी से बेपरवाह शराब के लिए दुकानों के आगे जुटी भीड़

कोच्चि, 24 मार्च (भाषा)।

● विपक्षी कांग्रेस ने केरल राज्य पेय पदार्थ निगम की दुकानों के सामने भीड़ को रोकने के लिए कदम नहीं उठाने पर एलडीएफ सरकार की आलोचना की।

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केरल में पूर्ण बंदी के बावजूद मंगलवार को राज्य बेवरेज निगम की दुकानों के आगे लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं। पूर्ण बंदी से बेपरवाह लोग दुकानों के आगे इकट्ठा हुए। अधिकारियों ने संक्रमण की रोकथाम के लिए एक मीटर की दूरी पर खड़े होने को कहा है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए शराब बिक्री केंद्रों पर ऐहतियाती कदम उठाए गए हैं। केवल मास्क लगाए हुए लोगों को कतार में खड़े होने की इजाजत दी जा रही है। पुलिस भी यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात है कि लोग कतार में एक मीटर की दूरी पर ही खड़े हों।

विपक्षी कांग्रेस ने केरल राज्य पेय पदार्थ निगम (बेवको) की दुकानों के सामने भीड़ को रोकने के लिए कदम नहीं उठाने पर माकपा नीत एलडीएफ सरकार की आलोचना की। एर्नाकुलम जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव शेरीन वर्गीज ने दावा किया कि अगर सरकार केरल हाई कोर्ट के 2017 के आदेश को लागू करती तो दुकानों के सामने इतनी लंबी कतारें नहीं लगतीं और ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती।

बहरहाल, राज्य सरकार ने कतार में खड़े लोगों के बीच उचित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में मौजूदा विशेष हालात का हवाला देते हुए शराब दुकानें खुला रखने के फैसले को सोमवार को उचित ठहराया। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केरल में सोमवार से ही 31 मार्च तक के लिए पूर्ण बंदी है।

मध्य प्रदेश के जनादेश को नीलाम कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया : दिग्विजय

भोपाल, 24 मार्च (भाषा)।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत सरकार के गिरने एवं उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की अगुआई में भाजपा नीत सरकार आने से तिलमिलाए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया है कि वह (सिंधिया) मध्य प्रदेश के जनादेश को नीलाम कर गए। दिग्विजय ने यह आरोप चौहान के मुख्यमंत्री बनने के एक दिन बाद मध्य प्रदेश की जनता के नाम खुले पत्र में लगाया है।

दिग्विजय ने इस पत्र में लिखा, पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ी, और कांग्रेस की सरकार गिर गई। यह बेहद दुखद घटनाक्रम है जिसने न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं बल्कि उन सभी नागरिकों की आशाओं और संघर्ष पर पानी फेर दिया, जो कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखते हैं।

दिग्विजय ने आगे कहा कि ये कहना गलत है कि पार्टी सिंधिया को राज्य सभा का टिकट नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वह भाजपा में चले गए। जहां तक मेरी जानकारी है, किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास दो राज्य सभा सीट जीतने के लिए जरूरी विधायक संख्या थी। इसलिए मुद्दा सिर्फ सीट का नहीं था। मुद्दा केंद्र सरकार में मंत्री पद का था, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही दे सकते थे।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में उचित पद और सम्मान मिलने की संभावना समाप्त हो गई थी, इसलिए वह भाजपा में चले गए। लेकिन ये गलत है। यदि वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, तो ए पद उन्हें 2013 में ही ऑफर हुआ था और तब उन्होंने केंद्र में मंत्री बने रहना पसंद किया था।

दिग्विजय ने कहा कि यही नहीं, 2018 में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश का उपमुख्यमंत्री पद संभालने का न्योता भी दिया था। लेकिन उन्होंने स्वयं इसे अस्वीकार कर अपने समर्थक तुलसी सिलावट को उपमुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर दी थी। कमलनाथ तुलसी सिलावट को उपमुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हुए और हाल के घटनाक्रम ने ये साबित भी कर दिया है कि वे सही थे। तुलसी सिलावट न सिर्फ भाजपा में गए, बल्कि ऐसे वक्त में गए, जब राज्य में कोरोना की महामारी से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी (तत्कालीन) स्वास्थ्य मंत्री के नाते उन्हीं की थी। सिंधिया ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस सरकार का उपमुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जो न सिर्फ कांग्रेस विचारधारा के प्रति बेईमान निकला, बल्कि पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदार भी साबित हुआ है।

विदेशों से लौटे लोगों के परिवार के सदस्यों में फैल रहा है कोरोना : गृह राज्य मंत्री

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए वे सरकार के निर्देशों का पालन करें क्योंकि यह बीमारी अब विदेश से लौटे लोगों के परिवार के सदस्यों में फैल रही है। रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि लोगों को इस बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि संसाधनों व प्रौद्योगिकी के होने के बावजूद अमेरिका जैसा विकसित देश भी इसके फैलाव को नहीं रोक सका है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अब तक विभिन्न हवाई अड्डों पर 15.24 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और 69,436 लोगों को घर में ही पृथक रहने (क्वारंटाइन) की सलाह दी गई है जिनका मेडिकल व अर्द्ध चिकित्सा कर्मी उपचार कर रहे हैं। रेड्डी ने कहा, 'अभी तक विदेश से लौटे ज्यादातर लोग वायरस से संक्रमित हैं।

www.readwhere.com

मुख्यमंत्री बोले, तीसरे चरण के लिए तैयार रहेंगे

40 घंटों में एक भी नया मरीज नहीं, सतर्कता बरतें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 मार्च।

कोरोना संक्रमण से पिछले 40 घंटे में एक भी कोरोना संक्रमण का मरीज सामने नहीं आया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता में कहा कि यह राहत की खबर है। संक्रमण के मामले नहीं बढ़े इसके लिए सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन करें।

दिल्ली सरकार ने मजदूरों की वित्तीय हालत सुधारने के लिए पांच हजार रुपए की आर्थिक मदद और रैन बसेरों की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा की है। इसके अतिरिक्त दिल्ली को तीसरी श्रेणी के खतरे से बचाव के सुझाव के लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया है।

मजदूरों की वित्तीय हालत सुधारने के लिए पांच हजार रुपए की आर्थिक मदद और रैन बसेरों की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा *कसम* खाओ कि अब इन लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि कल को मान लो आपके परिवार में किसी को कोरोना हो गया तो आप इन्हीं डॉक्टर और नर्स के पास ही तो जाओगे। इस तरह का भेदभाव और व्यवहार सही नहीं है। कसम खाओ कि अब इन लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करोगे।

मजदूरों को पांच हजार रुपए और रैन बसेरे बढ़ेंगे

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पांच हजार रुपए देगी। उन्होंने कहा कि बहुत से मकान मालिकों के फोन और मैसेज आए हैं जो बता रहे हैं कि हम मार्च का किराया नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक सज्जन कह रहे हैं कि मैं अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दूंगा। सरकार रैन बसेरे में खाना बांटने का काम कर रही है। रैन बसेरे में भीड़ काफी होने लगी है इसलिए रैन बसेरों की संख्या बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील कि किसी को भी दिल्ली में भूखा नही रहने दें , मदद के लिए आगे आएं।

'किसी से भेदभाव न करें'

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपने खिड़की दरवाजे बालकनी पर आकर थाली, ताली बजाई थी। क्योंकि हम अपने डॉक्टर, नर्सेस, पॉयलट आदि के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में काम किया। लेकिन अब यह सुनने को मिल रहा है कि मकान मालिक अपने किराएदार नर्स, पायलट को निकाल रहे हैं क्योंकि वो कोरोना के मरीजों के उपचार में लगे थे।

डॉक्टरों की टीम देगी तीसरी श्रेणी की रिपोर्ट

कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली को तीसरे स्तर की हालात के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सरीन की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की है। यह टीम 24 घंटे में कोरोना विषाणु की स्टेज तीन में जाने की जरूरतों व तैयारियों पर रपट देगी। रपट में बताया जाएगा कि संक्रमण की स्थिति में सरकार को किस प्रकार की तैयारियों की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी स्टेज दो पर है। भगवान से दुआ है कि ये स्टेज 3 पर न पहुंचे लेकिन ऐसा होता है तो हमारी तैयारियों में कमी नहीं रहनी चाहिए।

पांच सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित *टीम* 24 घंटे में कोरोना विषाणु की स्टेज तीन की तैयारियों पर रपट देगी

पुलिस ने शाहीनबाग प्रदर्शन बंद कराया, विरोध के लिए आई भीड़ को लौटाया

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 24 मार्च।

दक्षिण दिल्ली के शाहीनबाग में सौ दिनों से चल रहा धरना–प्रदर्शन खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी योजना के साथ सोमवार रात को ही आपरेशन शाहीनबाग चलाया। महिलाओं, बुजूर्गो और बच्चे–बच्चियों को साथ लेकर और दो दिनों से तख्त पर जूते जप्पल रखकर प्रदर्शन करने वालों को रातों–रात हटा दिया गया। पुलिस ने आपरेशन शाहीनबाग में इस बात का खास ध्यान रखा कि किसी को कोई चोटें नहीं पहुंचे और रास्ता खाली हो जाए। दिन में योजना को इसलिए अंजाम नहीं दिया गया ताकि किसी भी प्रकार का हंगामा न खड़ा हो जाए।

बताया जा रहा है कि सोमवार दिनभर पूर्ण बंदी के बावजूद लोगों की लापरवाही को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के प्रधान एसएन श्रीवास्तव ने कहा था कि अब नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कोरोना और धारा 144 के नाम पर दक्षिणी क्षेत्र के संयुक्त आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव की अगुवाई में पुलिस देर रात करीब दो बजे धरना खत्म करवाने के लिए शाहीन बाग पहुंची। कुछ लोग धरनास्थल पर बैठे थे। पुलिस ने पहले माइक से उद्घोषणा कर वहां बैठे लोगों से हटने की अपील की। इससे पहले पूरे इलाके के हर गली मुहल्ले में पीसीआर और स्थानीय पुलिस की गाड़ियां अवरोधक लगाकर लोगों को बाहर निकलने से पूरी तरह से मना कर दिया। बावजूद इसके आसपास के लोगों को जब पुलिस के आने की सूचना मिली तो आनन–फानन में कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचने लगे। देखते ही देखते कुछ सौ लोग पुलिस का विरोध करने के लिए मौके पर पहुंच गए। जब पुलिस को लगा कि उसकी योजना सफल नहीं हो पाएगी तो उसने धारा 144 का हवाला देते हुए भीड़ पर हल्का बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसके बाद तय योजना के मुताबिक पहले से तैनात दर्जन भर बड़े ट्रकों को प्रदर्शन स्थल के पास लगाया गया और टेंट उखाड़कर और तख्त उठाकर सभी को ट्रक में भर दिया गया। पुलिसिया कार्रवाई से प्रदर्शनकारी भी डर गए और फिर मंगलवार जब स्थानीय लोगों की नींद टूटी तो सुबह होते होते पूरे इलाके को खाली करा दिया गया। शाहीनबाग के इस धरना को खत्म करने में करीब पांच घंटे लगे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर विरोध के स्वर को कोरोना के नाम पर खाली करा दिया गया।

धारा 141 का हवाला दिया

ट्रकों में भरकर सामान हटवाया

पुलिस का कहना है कि प्रतीकात्मक रूप में बैठे पांच लोगों को उठाने में पुलिस को उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी जितनी वहां स्थाई तौर पर लाइन में लगाए गए लकड़ी के तख्त और लोहे की छड़ से बांधकर टेंट हो हटाने में लग गए। वहां पर रखे सामान की संख्या का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है इसके लिए कई ट्रकों को लाना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान लोगों ने बस स्टाप पर स्थाई निर्माण करके पक्का कमरा जैसे बना लिया था। पुलिस को इस स्थाई निर्माण को हटाने में बुलडोकर बुलानी पड़ी।

नवरात्र में होगा भाजपा के नए अध्यक्ष का फैसला

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 24 मार्च।

दिल्ली प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि नवरात्र में पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। इस बार नए अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी व चुनौती मार्च 2022 में होने वाले निगम चुनाव है। वर्तमान में सभी निगमों पर भाजपा का कब्जा है। नए अध्यक्ष के चुनाव में देरी यह भी एक बड़ा कारण है केंद्रीय नेतृत्व ने इस काम का जिम्मा राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव व राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष विजया राहटकर को सौंपा को था।

इस टीम ने पार्टी के विभिन्न मोर्चा अध्यक्षों और पदाधिकारियों से ली गई रपट भेजी जा चुकी है। तय नियम व प्रावधान के तहत वर्तमान अध्यक्ष मनोज तिवारी अपना कार्यकाल दिसंबर में ही पूरा कर लिया है। दिल्ली में लोकसभा व विधानसभा चुनाव की वजह से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। विधानसभा चुनाव में पूरा दमखम लगाने के बाद पार्टी सीट में बढ़त तो प्राप्त कर चुकी है लेकिन 22 साल बाद भी दिल्ली की सत्ता से दूर ही है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। इस कार्यकाल के बाग भाजपा नियम प्रकिया के तहत नए अध्यक्ष का चुनाव करती है।

खाने को लंगर, सोने को रैन बसेरों का सहारा

प्रियरंजन
नई दिल्ली, 24 मार्च।

दिल्ली में पूर्णबंदी की सबसे ज्यादा मार उन बेघरों पर पड़ी है जो दिहाड़ी मजदूर हैं और कहीं काम न करने वाले हैं। सामाजिक दूरी बना चुकी दिल्ली की आम जनता अपने घरों में एकांतवास में है। लेकिन जिनके घर ही नहीं वे कहां जाएं। अभी तक जो दिन में दिहाड़ी या भीख मांग कर पेट भरते और फुटपाथों पर, फ्लाईओवरों के नीचे, अपने रिक्शा और ठेले पर रात गुजर कर लिया करते थे। कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते घोषित पूर्णबंदी ने उन्हें दोहरे मार की परेशानी में खड़ा कर दिया है। वे कामबंदी के चलते भूखमरी और जगह न होने के चलते संक्रमित होने के कगार पर जाने की आशंका से पीड़ित हैं।

मंगलवार को इन्हें हनुमान मंदिरों के सामने भी राहत नहीं मिली। इनमें से जिन्हें रैन बसेरों में जगह मिली है वे अपने को थोड़ा बेहतर स्थिति में बता रहें हैं। लेकिन उन्हें मलाल और भय है कि वे लोग भी समाजिक दूरी नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि एक बड़े हॉल के तौर पर उन्हें मुहैया कराए गए तंबू में एक साथ 50 से ज्यादा लोग रहा करते हैं। दिहाड़ी मजदूर और आश्रित गुरुद्वारों में चल रहे स्थायी लंगरों की ओर रुख कर रहे हैं। यहां पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त भीड़ देखी गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसकी पुष्टि की। लंगर में बढ़ती भीड़ का हवाला देते हुए कमेटी के प्रधान ने दावा किया कि ऐसी बढ़ोतरी पहले कभी नहीं दिखी थी। भीड़ ने उन्हें बताया कि वे दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं। आजीविका संकट के चलते यहां आने लगे हैं। कमेटी के प्रधान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से तत्काल सहायता की अपील जारी की है।

रैन बसेरों में खाना पहुंचाने की ली जिम्मेदारी

आश्रय अधिकार अभियान की निदेशक परमजीत कौर ने जनसत्ता से कहा– यह बड़ी चुनौती आ गई है। दिल्ली सरकार के फैसले के तहत रैन बसेरों में अनिवार्य खाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। सात जगहों पर रसोई शुरू कर खाना बनाकर उसे रैन बसेरों तक पहुंचाया जा रहा है। दिहाड़ी और आश्रित और बेघर जन यहां खाना खा सकते हैं। जागरूकता और सफाई पर यहां सत्रों का आयोजन हो रहा है। सेनेटाइजर और मास्क बांटे गए हैं।

शिक्षाविद, बौद्धिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों का खुला पत्र

हाशिए पर रह रहे लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 50 से ज्यादा संगठनों से जुड़े शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक वैज्ञानिक आगे आए हैं।

अर्थशास्त्री जयती घोष, आइआइएम बंगलूर के प्रोफेसर दीपक मलघान और हेमा स्वामीनाथन, आइआइटी दिल्ली के आदितेश्वर सेठ, ऐपवा की कविता कृष्णन, पीयूसीएल की कविता श्रीवास्तव, एनसीपासीआर की पूर्व प्रमुख शांथा सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ताओं में हर्ष मंदर, योगेंद्र यादव, निखिल डे आदि की ओर से हस्ताक्षरित सरकार के नाम जारी पत्र में कोरोना को गंभीर संकट बताते हुए सरकार के सुझाव दिया गया है कि जन वितरण प्रणाली के तहत अप्रैल से जून के लिए एक साथ मुफ्त अनाज, खाद्य तेल, दाल, नमक, मसाला, व साबुन भी दिया जाए। राज्य–वार सामुदायिक रसोई योजनाओं या मध्याह्न भोजन की रसोइयों से कम से कम मई के अंत तक दिन में दो बार पका भोजन सबके लिए उपलब्ध कराया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों को अप्रैल से जून तक की पेंशन राशि इसी महीने भेज दी जाए। बंदी के समय सब मनरेगा मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी मिले।

गुरुद्वारे में बनाया 20 बिस्तरों का अस्पताल

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संभावित रोगियों के इलाज के लिए ढांचागत सुविधाओं वाला गुरुद्वारा मजनूं का टीला में 20 बिस्तरों के सराय (भवन) को आइसोलेशन वार्ड में बदलने की पेशकश की है। समिति अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुख्यमंत्री से यह पेशकश करते हुए कहा है कि बीस बिस्तरों की सराय में प्रत्येक कमरे में अलग से शौचालय, स्नानागार जुड़े हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित एवं चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। इसमें सेवा करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों के लिए गुरुद्वारा समिति अलग से आवासीय सुविधाएं प्रदान करेगी।

(This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement)

COSPOWER ENGINEERING LIMITED

(CIN: U31908MH2010PLC208016)

Our Company was originally incorporated as Cospower Engineering Private Limited at Mumbai as Private Limited Company under the provisions of Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated September 22, 2010, bearing Corporate Identification Number U31908MH2010PTC208016, issued by the Registrar of Companies, Mumbai and Maharashtra for the purpose of acquiring the Partnership business of M/s. Cospower Corporation, which was in existence since 2004. Subsequently, our Company was converted into Public Limited Company pursuant to a special resolution passed by members in Extra-Ordinary General Meeting of Company held on January 23, 2020 and the name of our company was changed to Cospower Engineering Limited vide a fresh Certificate of Incorporation dated February 19, 2020, issued by the Registrar of Companies, Mumbai and Maharashtra. The Corporate Identification Number of our Company is U31908MH2010PLC208016.

Registered Office: Flat No.203, 2nd Floor, Kesarinath Apartments, S.V. Road, Opp. Vijay Sales, Goregaon West, Mumbai, Maharashtra - 400062.
Tel: +91 22–40129990; **E-mail:** accounts@cospowerindia.com; **Website:** www.cospowerindia.com
Company Secretary and Compliance Officer: Ms. Garima Garg; **E-Mail:** cs@cel.net.in

PROMOTERS: MR. OSWALD ROSARIO DSOUZA AND MR. FELIX SHRIDHAR KADAM

BASIS OF ALLOTMENT

PUBLIC ISSUE UPTO 4,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF COSPOWER ENGINEERING LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 51.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 41.00 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 204.00 LACS ("THE ISSUE"), OF WHICH UPTO 24,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 51.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 41.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 12.24 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE UPTO 3,76,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT A PRICE OF ₹ 51.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 191.76 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.67 % AND 25.07% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated March 09, 2020 from BSE Limited for using its name in this offer document for listing of our shares on the BSE SME. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the BSE Limited.

All Applicants were allowed to participate in the issue either through **Applications supported by Blocked Amount("ASBA")** process by providing the details of their respective bank accounts in which the corresponding applications amount were blocked by Self Certified Syndicate Banks(the "SCSBs") or through UPI mechanism.

ISSUE **OPENED ON: MARCH 17, 2020 and CLOSED ON: MARCH 19, 2020, PROPOSED DATE OF LISTING: MARCH 30, 2020*.**

* Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE SME Platform

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue Received 98 applications for 5,54,000 shares and was subscribed to the extent of 1.44 times before technical rejection but after bids not banked. After considering Technical Rejections cases, the Issue was subscribed 1.36 times i.e.92 applications for 5,42,000 shares.

Summary of the Valid Applications Received:

Category	Gross Application		Less: Rejections		Valid	
	No. of Application	Equity Share	No. of Application	Equity Share	No. of Application	Equity Share
Retail Individual Applicants	65	1,30,000	6	12,000	59	1,18,000
Non Retail Applicants	32	4,00,000	-	-	32	4,00,000
Market Maker	1	24,000	-	-	1	24,000
Total	**98**	**5,54,000**	**6**	**12,000**	**92**	**5,42,000**

Allocation: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange –BSE SME Platform on March 23, 2020

a. Allocation to Market Maker (After Technical & Multiple rejections and withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹51 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE SME Platform. The category was subscribed by 1.00 times. The total number of shares allotted in this category is 24,000 Equity shares.

Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
24,000	1	100	24,000	100	24,000	1:1	24,000
Total	**1**	**100**	**24,000**	**100**			**24,000**

b. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical & Multiple rejections and withdrawal): The Basis of Allotment to the retail individual investors, at the issue price of ₹51 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE SME Platform. The category was subscribed by 0.627 times. The total number of shares allotted in this category is 1,18,000 Equity shares to 59 successful applicants.

Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
2,000	59	100	1,18,000	100	2,000	1:1	1,18,000
Total	**59**	**100**	**1,18,000**	**100**			**1,18,000**

*The under subscribed portion of 70,000 Equity shares from Retail Investors Category have been spilled over to Other Investors Category.

c. Allocation to Other than Retail Individual Investors (After Technical & Multiple rejections and withdrawal): The Basis of Allotment to the other than retail individual investors, at the issue price of ₹51 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE SME Platform. The category was subscribed by 1.550 times. The total number of shares allotted in this category is 2,58,000 Equity shares to 32 successful applicants.

Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
4,000	13	40.63	52,000	13.00	2,000	1:1	26,000
		0.00		0.00	2,000	4:13	8,000
6,000	4	12.50	24,000	6.00	4,000	1:1	16,000
8,000	2	6.25	16,000	4.00	4,000	1:1	8,000
		0.00		0.00	2,000	1:2	2,000
10,000	5	15.63	50,000	12.50	6,000	1:1	30,000
		0.00		0.00	2,000	1:5	2,000
18,000	2	6.25	36,000	9.00	12,000	1:1	24,000
20,000	1	3.13	20,000	5.00	12,000	1:1	12,000
24,000	2	6.25	48,000	12.00	14,000	1:1	28,000
		0.00		0.00	2,000	1:2	2,000
34,000	1	3.13	34,000	8.50	22,000	1:1	22,000
60,000	2	6.25	1,20,000	30.00	38,000	1:1	76,000
		0.00		0.00	2,000	1:2	2,000
Total	**32**	**100.00**	**4,00,000**	**100.00**			**2,58,000**

The Board of Directors of the company at its meeting held on **March 23, 2020** has approved the Basis of Allotment of Equity shares as approved by the Designated stock Exchange viz. BSE SME Platform and at a meeting held on **March 23, 2020** has authorized the corporate action for the transfer and allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

In terms of the Prospectus dated March 11, 2020 and as per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 where in a minimum of 50% of the net offer of shares to the Public shall initially be made available for allotment to retail individual investors as the case may be. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to a) individual applicants other than retail investors and b)other investors, including Corporate Bodies/Institutions irrespective of number of shares applied for. The unsubscribed portion of the net offer to any one of the categories specified in(a) or (b) shall be made available for allocation in the other category, if so required. "For the purpose of sub-regulation(2) of regulations 253, if the retail individual investor category is entitled to more than fifty percent on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage".

The CAN-cum-Refund advices and allotment advice and/or notices will be forwarded to the address/email id of the Applicants as registered with the depositories as filled in the application form on or before **March 24, 2020**. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will be processed on or prior to **March 23, 2020**. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSE SME Platform within six working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated March 11, 2020 ("Prospectus")

INVESTORS PLEASE NOTE The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issuer, BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED at www.bigshareonline.com . All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

Bigshare Services Pvt. Ltd.
1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri East,Mumbai,Maharashtra,400059, India. Telephone: +91 22 62638200; Facsimile: +91 2262638280
Email: investor@bigshareonline.com, ipo@bigshareonline.com;
Contact Person: Mr. Swapnil Kate; Website: www.bigshareonline.com
SEBI Registration Number: INR000001385; CIN No: U99999MH1994PTC076534

For **COSPOWER ENGINEERINGLIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-

Place: Mumbai
Date: March 23, 2020

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF COSPOWER ENGINEERINGLIMITED.

Raka

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	33.0 डि.से.	33.0 डि.से.	31.5 डि.से.	32.5 डि.से.
न्यूनतम	18.6 डि.से.	18.6 डि.से.	17.0 डि.से.	18.0 डि.से.

गौतम बुद्ध नगर में कोरोना विषाणु के तीन नए मामलों के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 11 हुई

लंदन से आए शख्स से दंपति को कोरोना

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 24 मार्च।

शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मंगलवार सुबह सेक्टर 137 स्थित ब्लोसम हाउसिंग सोसायटी में एक महिला में कोरोना विषाणु की पुष्टि हुई है। उससे ही उसके पति में भी कोरोना विषाणु पाया गया है। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। इनकी बेटी की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसे अलावा ग्रेटर नोएडा में भी एक व्यक्ति में कोरोना विषाणु की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 11 पर पहुंच गई है।

26 मार्च तक सोसायटी को किया गया सील

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि सेक्टर 137 स्थित हाउसिंग सोसायटी को 26 मार्च की रात 10 बजे तक बंद किया गया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम सोसायटी में सर्वे कर रही है। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

पांच अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था

गौतमबुद्ध नगर में पांच अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखने की व्यवस्था है। पहला व दूसरा सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआइ, तीसरा नया जिला अस्पताल, जिसमें 400 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। इसके अलावा एक आइसोलेशन वार्ड सेक्टर 40 स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सेक्टर 35 स्थित मित्रा अस्पताल में है।

इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने ब्लासम सोसायटी में अगले तीन दिनों लोगों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि सेक्टर 137 स्थित हाउसिंग सोसायटी में एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। जानकारी के मुताबिक, जिस कंपनी में महिला काम करती है वहां के लंदन से आए प्रोजेक्ट हेड के संपर्क में महिला आई थी जिसके बाद उसे लक्षण दिखे। उन्हें 14 दिनों के लिए इसे पृथक ऱखा गया है। महिला से ही उसके पति को भी यह बीमारी हो गई है। परिवार में छोटी बेटी है, उसे भी आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं, एक अन्य पुरुष में भी कोरोना विषाणु की पुष्टि हो गई है। उसकी पूरी जानकारी अभी नहीं है। सभी मरीज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (जिम्स) में भर्ती किया गया है।

नोएडा में कोरोना का असर

सुबह-शाम टहलने वालों पर प्राधिकरण की सख्ती

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 24 मार्च।

लोगों के सुबह-शाम घूमने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाते हुए मंगलवार को नोएडा स्टेडियम, पार्क और सेक्टर-गांव के सभी बारात घरों पर ताले लगा दिए गए हैं। जिन पार्क में ताला लगाने का सिस्टम नहीं है वहां पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है।

इसके अलावा ओपन जिम पहले से ही बंद किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सभी पार्कों में लोगों के प्रवेश लगाने का आदेश जारी किया था। इसके बाद मंगलवार सुबह से नोएडा प्राधिकरण ने आदेश का पालन करवाना शुरू कर दिया। नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक राजीव त्यागी ने बताया कि शहर में करीब 726 पार्क है।

बंदी के समर्थन में उतरी नोएडा की कई सोसाइटी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉक डाउन के निर्णय का सम्मान करते हुए नोएडा की भी सोसाइटीज ने अपना समर्थन दिया है। एबीए कॉर्प के डायरेक्टर और क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के प्रेजिडेंट अमित मोदी ने बताया वर्तमान समय में व्यवसाय या आर्थिक नुकसान का विश्लेषण या गणना करने का नहीं है। हमें सबसे पहले इस वायरस से लड़ने और श्रृंखला को तोड़ना सबसे जरूरी है। इसके साथ-साथ कंपनी की देखरेख में सभी हाउसिग प्रोजेक्ट्स के सभी हाउसकीपिग, सेक्योरिटी, मैनेटेंस की टीम को निर्देश दिया गया है कि लॉक डाउन के समय आने-जाने वालों को रोका जाए। शहर के सेक्टर-12,22,39,36,35,49,5०,51 के अलावा तमाम कई सेक्टर है जहा सप्लाई में बाधा आ रही है। दुकाने बंद है।

सुविधाओं में नहीं आएगी कमी

नगरीय सुविधाआएं निरंतर रूप से चलती रहे इसके लिए प्राधिकरण ने आला अधिकारियों की एक टीम को अलग-अलग कार्यो के लिए बांट दिया है। कार्य पूर्ण होने पर इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दोनी होगी। इस क्रम में विशेषाकार्यधिकारी आरके सिंह, संतोष कुमार उपाध्याय, नवीन सिंह प्रत्येक 8-8 घंटे के अंतराल पर आने वाली शिकायत पर समीक्षा करेंगे। विशेष रूप से साफ-सफाई, जल सीवर, बिजली आपूर्ति , स्ट्रीट लाईट , भोजन संबंधित शिकायत। वहीं, शेषाकार्यधिकारी इंदू प्रकाश सिंह को जिम्मेदारी दी गई कि वह सामान्य प्रशासन के कर्मियों के साथ सेक्टरवार फल और सब्जी के सभी ऐसे वैंडर्स की सूची तैयार कर अग्रिम कार्यवाही के लिए तैयार रहे। लोग न आए और एक जगह एकत्रित न हो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाप्रबंधक राजीव त्यागी को दी गई है।

यहां खुलेंगे सार्वजनिक शौचालय

15 स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय खुले रहेंगे। इसमे एक्सप्रेस-वे सेक्टर-94 की तरफ, एक्सरप्रेस-वे पर सेक्टर-44, एक्सप्रेस-वे पर सेक्टर-150, सेक्टर-38ए बस स्टैंड, कंचन जंगा मार्केट, सेक्टर-62 डी पार्क बंगाली बाजार, सेक्टर-18 गार्डन गलेरिया, स्टेडियम गेट नंबर 04, सन बर्ड बनालिका प्रोजेक्ट सेक्टर-107 , सेक्टर-08 नर्सरी, एमपी-02 रोड सेक्टर-16ए टी प्वाइंट, सेक्टर-121 होम-121, सेक्टर-05 झुग्गी, लेबर चौक सेक्टर-62 व सेक्टर-18 मेकडानल्ड।

बंद उल्लंघन पर 209 वाहन जब्त

गौतमबुद्ध नगर में 112 जगहों पर बैरियर और नाके लगाकर वाहनों की सघन चेकिंग में आज 9122 वाहनों की चेकिंग कर 1556 वाहनों का चालान किया गया और 209 वाहन जब्त किये गए। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने जन सामान्य से बंद का पालन करने का अनुरोध किया है।

बंद कोरोना विषाणु की वजह से बंद के चलते दिल्ली और यूपी के गाजीपुर सीमा पर वाहनों को रोका गया, जिससे वहां वाहन कुछ इस तरह जमा हो गए।

दिल्ली-नोएडा सीमा पर आपात वाहनों के लिए अलग रास्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 मार्च।

कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर दिल्ली में पूर्ण बंदी की स्थिति को कारगर बनाने के लिए सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहने के दौरान मंगलवार को सीमावर्ती नोएडा को जोड़ने वाले मार्गों पर दिल्ली पुलिस आपात वाहनों के लिए पृथक लेन चिन्हित की गई हैं ताकि आपात सेवाओं से जुड़े लोगों के वाहन पृथक लेन से आवागमन कर सकें।

पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त जसमीत सिंह ने ट्वीट कर बताया कि आपात सेवार्किमयों के वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पृथक लेन बनाई गई है। पुलिस ने पूर्ण बंदी के पिछले 24 घंटों के दौरान लोगों को हुई परेशानी के मद्देनजर यह कदम उठाया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोमवार से पूर्ण बंदी घोषित होने के बाद दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले मार्गों पर पुलिस से वाहनों के आवागमन को रोकने के दौरान आपात सेवाकर्मियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली नोएडा संपर्क मार्गों पर इस आशय की सूचना भी चस्पा कर दी गयी है। इसमें डॉक्टर, मीडिया, एंबुलेंस, पुलिस और अन्य आपात सेवाओं से जुड़े कर्मियों के वाहनों को पृथक लेन से आने जाने की छूट देने की जानकारी दी गयी है।

टैक्सी चालकों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख बताई समस्या

कैसे देंगे किस्त और किराया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 मार्च।

दिल्ली बंद के बाद ऑटो टैक्सी चालकों के सामने बड़ा आर्थिक संटक खड़ा हो गया है। इस संकट से उबरने के लिए चालकों ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। इस बाबत दिल्ली टैक्सी, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और राहत पैकेज की मांग की है।

संजय सम्राट ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए दिल्ली के ऑटो टैक्सी वाले और टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर पूरी तरह भारत सरकार का साथ दे रहे है। इसलिए 22 मार्च के जनता बंद में हमने पूरा सहयोग किया और अपनी एक भी टैक्सी बस को सड़क पर नहीं आने दिया। हमारी टूरिस्ट टैक्सी बसें लगभग एक महीने से खड़ी हैं। करोना की वजह से पहले ही पर्यटक कम हो गया था।

फिर सरकार ने पर्यटक स्थलों को बंद कर-के पूरी तरह रोक लगा दी। अब 31 मार्च तक बंद है। ऑटो टैक्सी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं और वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर से हर महीने की किस्ते भी चालक को देनी पड़ती है। हमारी मांग है कि टैक्सी, बस की मासिक किश्त को 6 महीने तक न लें। जीएसटी में भी राहत दी जाए। यह ज्ञापन वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर को भी भेजा गया है ।

परिवहन कर्मचारियों को मिले दस्ताने मास्क : मजदूर संघ

कोरोना संक्रमण में परिवहन सेवाए दे रहे कर्मचारियों को दस्ताने, मास्क व हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध कराने की मांग दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने सरकार से की है।

बंद में मददगार बनी दिल्ली

किराया माफ किया, सहायिकाओं को वेतन भेजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 मार्च।

कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली बंद में मददगार भी आगे आएं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील के बाद लोगों ने अपने किराएदारों की मदद की घोषणा की है और पड़ोस में भी मदद का आश्वासन दिया है। दिल्ली वालों के इस जज्बे को मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सलाम किया है और उनको रीट्वीट किए हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना को फैलने से रोकने की लड़ाई में कई लोग सामने आ रहे हैं जो आर्थिक मदद करना चाहते हैं। मैं आप सबके देशभक्ति के जुनून को सलाम करता हूं। अगर लोग चाहे तो सहयोग के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में भी अपना योगदान दे सकते हैं। दरअसल बंद की स्थिति के देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि अगर आपके किराएदारों के पास तुरंत किराया देने के पैसे न हो तो अगले एक या दो महीने का किराया बाद में किस्तों में ले लें। इस महामारी के दौरान किसी गरीब को हम बेसहारा और भूखा नहीं छोड़ सकते। ये सबकी जिम्मेदारी है। इसके बाद राज बैंसला ने अपने किरायेदारों का किराया माफ करने का फैसला था। इसका मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये कदम बेहद सराहनीय है। इस समय हम सबको एक दूसरे के काम आना है। एक दूसरे की मदद करनी है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इनकी की तारीफ

मैं अपने सभी किरायेदारों की जिम्मेदारी लेता हूं उनका किराया माफ करता हूं और जब तक दिल्ली में किरोना जैसी महामारी से हालात सामान्य नही हो जाते तब तक उनकी खाने एवं जरूरत के समान की जिम्मेदारी मेरी है। -विजय कुमार

जनता कर्फ्यू और इस महामारी को देखते हुए मैं अपने किराएदारों से मार्च का किराया नहीं लूंगा और कामवाली को अवकाश देने के बावजूद भी उसका पूरा वेतन दूंगा और जितना होगा सहायता भी करूंगा। जय हिंद। -सनी गुप्ता

माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझाव पर अमल करते हुए मैंने प्रण लिया है कि किरायदारों की हालत ठीक होने तक पूरा सहयोग करूंगा। ज्यादातर वो दूसरे राज्य से आए हुए लोग है उन्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो उसका भी पूरा धयान रखूंगा। -रोमी भाटी

सेवा में जुटी आरडब्लूए

एबी ब्लॉक की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने शालीमार बाग में सामुदायिक सेवा शुरू की है। वह ब्लॉक में प्रवेश करने वालों का हाथ धुलवा रहे हैं और घरों से कूड़ा उठवा रहे हैं। एसोसिएशन के गिरीश अग्रवाल के मुताबिक लोगों में जागरूकता आ रही है।

बंदी से कई डॉक्टर व नर्स नहीं पहुंचे अस्पताल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 मार्च।

दिल्ली और आसपास में चल रहे पूर्ण बंद के चलते डॉक्टरों व दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों को अस्पताल पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामाना करना पड़ रहा है। किसी तरह कुछ कर्मचारी बंद के पहले दिन अस्पताल पहुंचे लेकिन काफी कर्मचारी पहुंचने में असमर्थ रहे। अब अस्पतालों ने एक समिति बना कर इसका समाधान करने की मांग केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय से की है।

इसके साथ ही यह भी कोशिश की जा रही है कि अस्पतालों के नजदीक ही किसी जगह डॉक्टरों व कर्मचारियों को ठहराया जा सके। जबकि दिल्ली सरकार के कुछ अस्पतालों में काम पर लगे डाक्टरों व नर्सों ने अस्पताल में ही रहने का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली के डॉ रमामनोहर लोहिया अस्पताल में कुल करीब 1200 डाक्टर हैं जिनमें से मुश्किल से 100 से 150 डाक्टरों को छात्रावास या पास के मकानों में रहने की सुविधा मिली हुई है। जबकि ज्यादातर डॉक्टर दिल्ली के दूरदराज के इलाकों से आते हैं। आरएमएल के कई डॉक्टर नोएडा या गुरूग्राम जैसी जगहों से भी आते हैं। कई डॉक्टरों व नर्सों के पास तो अपने स्वयं की वाहन सुविधा भी नहीं है। लिहाजा अस्पताल प्रशासन ने सोमवार को एक समिति गठित की।

यूरोलाजी विभाग के मुखिया डॉ राजीव सूद की अगुवाई में गठित इस समिति में तीन अन्य सदस्य शामिल हैं। इनमें उपनिदेशक (प्रशासनिक) रजिस्टार व नर्सिंग इंचार्ज शामिल हैं। समित ने इसका ब्यौरा तैयार कर कर्मचारियों के रहने व वाहन सुविधा का इंतजाम किया है। ताकि कर्मचारी व डॉक्टरों को असुविधा न हो। यही हाल सफदरगंज अस्पताल के डाक्टरों व अन्य कर्मचारियों का है। यहा करीब 200 डॉक्टर है लेकिन उनके हिसाब से यहां छात्रावासों की सुविधा न के बराबर है। संकाय सदस्यों के पास तो फर भी गाड़ी है लेकिन सभी रेजीडेंट डाक्टरों के पास यह सुविधा नहीं हैं। अस्पताल में एक चिक्तसक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मास्क की भी कमी हो रही है। एक एन95 मास्क से एक हफ्ते काम करना पड़ रहा है।

लेडी हार्डिंग अस्पताल के एक चिकित्सक डॉ महापात्रा ने प्रधानमंत्री के नाम खुला पत्र लिख कर मांग की है कि मास्क जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें समय पर मुहैया कराई जाएं। यहां के डाक्टरों व कर्मचारियों को भी अस्पताल पहुचने में दिक्कत आ रही है। फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ सुनील अरोड़ा ने कहा कि आदेश आ गए हैं कि केंद्र के तीनो अस्पतालों आरएमएल, लेडीहार्डिंग व सफदरजंग के स्वास्थ्य कर्मचारियों को बसें अस्पताल की ओर से मुहैया कराई जाएगी।

नवरात्र पर कलश स्थापना में लिए नहीं मिल रहे मिट्टी के कलश

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 24 मार्च।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बुधवार से वासंतीय नवरात्र आंरभ हो रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लोगों को पूजन सामग्रियों नहीं मिल रही है। कलश स्थापना के लिए लोगों को मिट्टी के कलश भी इस बार नहीं मिल रहे है। भक्त घरों में कलश स्थापना कर मां दुर्गा का नौ दिनों तक व्रत रखते है। कोरोना संक्रमण के कारण शहर के गांवों में बने बाजार ममूरा, हरौला, छिज्जासी, बरौला, भंगेल, सलारपुर समेत अनेक बजारों में गिनी चुनी अस्थाई दुकानों पर कलश बिक रहे थे। यहां आम दिनों में 20 से 30 रुपये में बिकने वाला कलश 40 से से 70 रुपये में बिक रहा था।

मजदूरों के लिए राहत सामग्री दी जाए : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 मार्च।

अखिल भारतीय प्रांतीय प्रवासी एवं दलित विकास मंच ने कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो मजदूरी करते हैं उनके लिए सरकार को तुरंत आर्थिक व्यवस्था करनी चाहिए। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी बुराड़ी के पूर्व विधायक प्रत्याशी गोपाल झा ने मंगलवार को इस बाबत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत दिल्ली के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। ऐसे प्रांतीय प्रवासी मजदूर देश भर के हैं जिनके पास न राशन कार्ड है, न मजदूर कार्ड और न ही कोई पेंशन व्यवस्था है। वे जहां तहां फंसे हुए हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नोडल एजंसी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से उचित मदद की सख्त जरूरत है। क्योंकि महीने के अंतिम सप्ताह में कोरोना विषाणु के बाबत पूर्ण बंदी और कर्फ्यू लगाया गया है।

जरूरी चीजों की आपूर्ति रेल से जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 मार्च ।

देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भारतीय रेलवे 24 घंटे कार्यरत है। मालगाड़ियों का परिचालन निरंतर जारी है, जबकि कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए यात्री ट्रेन सेवाएं अभी बंद हैं। खाद्यान्न, नमक, चीनी, दूध, खाद्य तेल, प्याज, फल-सब्जियां, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और उर्वरक जैसे सामान रेलवे टर्मिनलों पर लोड किए जा रहे हैं। रेलवे निर्बाध माल ढुलाई सेवाओं के जरिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल में ही गुजार रहे दिन और रात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 मार्च।

लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में कोरोना विषाणु पीड़ित और संदिग्ध मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टर व नर्सों ने भी खुद को आइसोलेट (पृथक) कर रखा है। अस्पताल में कोरोना के मरीजों की ड्यूटी में लगे नर्सिंग आफीसर दयाराम ने बताया कि वह अभी तक घर से आकर मरीजों की देखभाल का काम कर रहे थे।

पूरी तरह सुरक्षा किट पहनकर काम कर रहे हैं लेकिन संक्रमण कहीं हमसे होकर समुदाय या परिवार में न पहुंचे इसलिए हमने सरकार से लिखित में यह मांग की थी कि हमें भी अस्पताल में ही पृथक रहने का इंतजाम दिया जाय ताकि हम मरीजों की देखभाल और समाज व परिवार का बचाव और अच्छे से कर सकें। इसके बाद दिल्ली सरकार ने उनके साथ इलाज में लगे तमाम अन्य नर्सों व डॉक्टरों के रुकने का इंतजाम किया है। अब से वे अस्पताल में ही रुककर मरीजों का इलाज करेंगे रात को यहां एक कमरे में सोएंगे। सरकार ने इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया है। दयाराम ने एक वीडियो के जरिए अन्य स्वास्थ्यकर्मियों से अपील की है कि परिवार व समुदाय को संक्रमण से बचाने के लिए उनसे मिलना जुलना न करें। संभव हो तो अस्पताल में ही रुके रहें।

उधर, सफदरसंज अस्पताल में सबसे अधिक कोरोना संदिग्ध भर्ती हैं। हालांकि यहां के डॉक्टर व नर्स इलाज की ड्यूटी खत्म कर-के अपने सुरक्षा किट उतार व खुद को विसंक्रमित करके अपने छात्रावास चले जाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास तौर पर परामर्श जारी किया गया है।

लेकिन कई अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सकों की न केवल अस्पताल में ड्यूटी लगाई गई है बल्कि कुछ जगहों पर तो वरिष्ठ चिकित्सकों को कोरोना वार्ड का इंचार्ज भी बनाया गया है। इनमें से कुछ चिकित्सक तो मधुमेह या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से भी पीड़ित हैं। गौरतलब है कि बुजुर्ग लोगों व बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को यह बीमारी घातक साबित हो सकती है। इसी बात को लेकर वरिष्ठ चिकित्सकों के परिजनों को चिंता सता रही है। एक डॉक्टर के परिजन खाना लेकर उनके कक्ष में इंतजार कर रहे थे उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बीमारी को थोड़ी पता है कि अमुक बुजुर्ग को मत पकड़ो यह तो डॉक्टर है। अगर बीमारी का संक्रमण हो गया तो जान का जोखिम हो सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि इमरजेंसी है लेकिन जब तक चिकित्सा में मानव संसाधन की कमी नही आती तब तक तो वरिष्ठ चिकित्सकों को इससे अलग रखा जा सकता है। इस लिए ऐसे डॉक्टरों की वीडियो या टेलीमेडिसिन से इनकी सेवाएं ली जानी चाहिए।

एम्स के डॉक्टरों को मकान खाली करने को कहा

एक तरफ तो लोग कोरोना से लड़ने में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए ताली बजा रहे हैं दूसरी तरफ एम्स के डॉक्टरों को मकान मालिक घर खाली करने को कह रहे हैं। एम्स रेजीडेंट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने इसकी शिकायत गृह मंत्री अमित शाह से की है। शाह को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने कहा है कि उनके पास छात्रावास में रहने की सुविधा नहीं है। एसोसिएशन के डॉ राजकुमार ने कहा है कि उनकी मंत्रालय से उनकी बात हो गई है और उन्हें भरोसा दिया गया है कि ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राहत सामग्री का किया जाए वितरण : केवाइएस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 मार्च।

क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाइएस) ने कोरोना के प्रकोप से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लिए जा रहे कदमों की आलोचना की। बंद के अलावा इस दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया जिससे हालात सुधरें। संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के प्रकोप के बीच पूर्वोत्तर के लोगों पर नस्लवादी हमले किए जा रहे हैं। आज न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त हैं, बल्कि कामकाजी जनता भी भारी दबाव में है। पूर्ण बंद के कारण लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। खासकर कमजोर वर्ग पर ज्यादा दबाव है।

www.readwhere.com

संपर्क में आए लोगों की जानकारी नहीं देने वाले कोरोना मरीजों पर मामला

अमदाबाद, 24 मार्च (भाषा)।

गुजरात के गांधीनगर में कोरोना वायरस से संक्रमित एक दंपति और उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने उन दो लोगों के नाम नहीं बताए जो उनके संपर्क में आए और बाद में घातक संक्रमण से संक्रमित हो गए।

एक अधिकारी ने बताया कि दंपति के चाचा उन दो लोगों में शामिल हैं जो बाद में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उनके खिलाफ भी इस आरोप में मामला दर्ज किया गया है कि उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं दी कि वह दुबई से लौटे अपने भतीजे के संपर्क में आए हैं।

दंपति 16 मार्च को दुबई से लौटे थे। 20 मार्च को 28 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई और इसके अगले दिन उसकी पत्नी भी संक्रमित पाई गईं। उन दोनों और उनके परिवार को उन सभी लोगों के बारे में जानकारी देनी थी, जो उनसे दुबई से लौटने के बाद मिले थे।

इसके बाद, 54 लोगों की सूची बनाई गई लेकिन उसमें उनके चाचा और चाची का नाम नहीं था। वे दोनों सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। गांधीनगर के कलेक्टर कुलदीप आर्य ने कहा कि प्रशासन ने 28 वर्षीय व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 54 लोगों की सूची बनाई थी और उनकी स्क्रीनिंग की। मगर हमारे संज्ञान में आया कि इस सूची में उसके चाचा और चाची का नाम नहीं था। इसके बाद हमने स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना का उल्लंघन करने के आरोप में व्यक्ति और उसकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया।

पुरी ने एअरलाइन कर्मियों को सुरक्षा दिए जाने का आग्रह किया

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को एअरलाइन कर्मियों को पड़ोसियों द्वारा परेशान करने की शिकायतों के मद्देनजर संबंधित प्राधिकारियों से चालक दल के कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को हर संभव मदद एवं सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया।

पुरी ने यह आग्रह कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच भारत के दो प्रमुख एअरलाइन इंडिगो और एअर इंडिया की ओर से उनके चालक दल के कर्मियों को पड़ोसियों द्वारा परेशान करने की घटना के मद्देनजर की। इंडगो ने सोमवार को कहा था कि कोरोना के मद्देनजर विमानन क्षेत्र में बड़ी रुकावट आई है और अपनी ड्यूटी करने के बीच कर्मचारियों को समुदाय के बहिष्कार का सामना करना पड़ा।

एअर इंडिया ने रविवार को कहा था कि ड्यूटी के मद्देनजर विदेश जाने वाले चालक दल के कर्मियों को कुछ रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएसन और पड़ोसियों के बहिष्कार का सामना करना पड़ा।

पुरी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में कहा, कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के प्रयासों एवं नागरिकों को बचा कर लाने के कार्यों में अग्रिम मोर्चे पर रहने वाले विमानन क्षेत्र के पेशेवरों के बारे जानकर काफी दुखी हूं कि उन्हें पड़ोसियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएसन द्वारा परेशान किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वह अपने पेशेवरों की निःस्वार्थ प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं और संबंधित प्राधिकार से हर संभवन सहयोग और इन्हें एवं परिवार की सुरक्षा सुनिश्वित करने का आग्रह करते हैं। बहरहाल, सोमवार को प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, एअर इंडिया की टीम पर काफी गर्व है जिन्होंने मानवता के आह्वान पर आगे बढ़कर अपूर्व साहस का परिचय दिया। उन्होंने कहा था कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूरे भारत से इनके अभूतपूर्व योगदान की काफी लोगों ने सराहना की।

'बंदी के नियमों का पालन करें'

मुंबई, 24 मार्च (भाषा)।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को कहा कि राज्य के लोगों के हितों में लॉकडाउन लागू किया गया है और सरकार को कड़े प्रावधान लागू करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए।

कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को महाराष्ट्र में लॉकडाउन करने की घोषणा की और कर्फ्यू लगा दिया। पवार ने ट्विटर पर कहा, 'कृपया घरों में रहिए। राज्य के हितों में लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इसमें कोई निजी इरादे नहीं हैं। राज्य सरकार को कठोर प्रावधान के लिए विवश नहीं करें।'

IRCON INTERNATIONAL LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
Regd. Off.: C-4, District Centre, Saket, New Delhi- 110017, INDIA
Tel. No.: +91-11-29565566 Fax: +91-11-26854000,
Web: www.ircon.org, E-mail: info@ircon.org CIN: L45203DL1976GOI008171

Notice of Record Date

Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Regulations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company has fixed **Tuesday, 7th April, 2020** as **"Record Date"** to ascertain the name of the shareholders entitled for Sub-division of equity shares of ₹ 10/- each into five(5) equity shares of face value of ₹ 2/- each.

For Ircon International Limited
Sd/-
(Ritu Arora)
Company Secretary & Compliance Officer

Place : New Delhi
Date : 24.03.2020

नांदेड के छह छात्र मॉरीशस में फंसे : चव्हाण

मुंबई, 24 मार्च (भाषा)।

महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने मंगलवार को कहा कि इंटर्नशिप के लिए मॉरीशस गए नांदेड के होटल प्रबंधन के छह छात्र कोरोना वायरस महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद होने की वजह से अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं।

चव्हाण ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर कहा है कि वह केंद्र से बात करें और फंसे हुए छात्रों की वीजा अवधि बढ़वाएं जिससे उनकी मुश्किलें और न बढ़ें। ठाकरे को लिखे एक पत्र में नांदेड जिले से आने वाले चव्हाण ने कहा कि इन छात्रों को चार महीने की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद मंगलवार को भारत लौटना था। यह इंटर्नशिप उनके होटल प्रबंधन पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। मंत्री ने कहा, 'उनके मॉरीशस के वीजा की अवधि कल (बुधवार को) खत्म हो रही है।'

चव्हाण ने कहा कि छात्रों ने उस द्वीपीय राष्ट्र में भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेसी मंत्री ने ठाकरे से अनुरोध किया कि वे केंद्र से बात कर इन छात्रों के वीजा की अवधि बढ़वाएं। उन्होंने कहा, 'अगर यह नहीं होता है तो छात्र कानूनी मुश्किल में घिर सकते हैं क्योंकि उनका वहां का प्रवास अवैध हो जाएगा। भारतीय दूतावास को उनकी वहां रहने में भी मदद करनी चाहिए।'

गुजरात : बगैर परीक्षाओं के छात्र अगली कक्षा में प्रोन्नत किए

अमदाबाद, 24 मार्च (भाषा)।

गुजरात सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखने और राज्य बोर्ड की कक्षा एक से नौ व 11वीं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेजने का फैसला किया है, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस के कारण वार्षिक परीक्षाएं नहीं होंगी।

गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस महीने पहले ही 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं करा चुका है। हालांकि, अन्य कक्षाओं के लिए परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर 15 मार्च से स्कूलों को बंद कर दिया है।

'ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों को रद्द न करें'

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) ने लोगों से कहा है कि वे उन ट्रेनों के लिए ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों को रद्द न करें, जिन्हें रद्द कर दिया गया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें खुद ही पूरा पैसा मिल जाएगा। इससे पूर्व रेलवे ने काउंटर टिकट रद्द करने के लिए 21 जून तक का समय तीन महीने बढ़ा दिया था।

आइआरसीटीसी ने एक बयान में कहा कि रेलवे यात्री ट्रेनों को बंद किए जाने के बाद ई-टिकट रद्द करने को लेकर संदेह जताया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि यात्री की ओर से कोई टिकट रद्द करने की आवश्यकता नहीं है।

केनरा बैंक Canara Bank

गुड़गांव मुख्य शाखा (1723) 298/7 ईस्सकेय टॉवर, पुराना रेलवे रोड़, नजदीक शिव मंदिर, गुड़गांव (हरियाणा)-122001
टेलीफोन- 0124-2322884, 2325004, ई-मेल आईडी: cb1723@canarabank.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि केनरा बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूत ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर मांग सूचना में वर्णित राशि की अदायगी करने के लिए आमंत्रित करते हुए इसमें वर्णित तिथियों पर कर्जदार/ गारंटरों को मांग सूचना जारी की गई।

कर्जदार राशि की अदायगी करने में असफल रहे हैं, कर्जदार व सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने निम्न वर्णित तिथि को कथित नियम के नियम 8 व 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसने/ अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें निम्न वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

कर्जदारों का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को मुक्त करवाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार व सामान्य रूप से जनता को इस संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करने के लिए एतद्द्वारा सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई लेन-देन खाते में वर्णित इसमें निम्न वर्णित राशि के अलावा आगामी ब्याज एवं अन्य प्रभार/ खर्चों के लिए केनरा बैंक, शाखा कार्यालयः ईस्स केय टॉवर पुराना रेलवे रोड़, गुरुग्राम-122001 (गुड़गांव-मैन) के प्रभार अधीन होगा।

खाता/कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि	कब्जा तिथि	मांग सूचना अनुसार राशि	अंच संपत्ति विवरण
मैसर्स प्रीडोमिनेंट इंजीनियर एंड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	14.05.2019	21.03.2020,	3,13,25,184.11 कम वसूल के साथ 05.05.2019 से लागू ब्याज	पंजीकरण जिला गुड़गांव के अन्दर मैसर्स प्रीडोमिनेंट इंजीनियर एंड कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के नाम

पर दर्ज मकान सं. 40 सुखचैन मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेज-1, गुड़गांव से ढ़का क्षेत्र 7500 वर्ग फुट रकबा 420 वर्ग मीटर में शामिल संपत्ति के सभी भाग व खंड। चारदीवारी: उत्तर: सड़क, दक्षिण: प्लाट नं. सी-12/5, पूर्व: प्लाट नं. एससीएम-41, पश्चिम: प्लाट नं. एससीएम-39

दिनांक: 24.03.2020 स्थान: गुरुग्राम प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

दिल्ली जोनल शाखा
15, एमबीसीसी टावर्स, तीसरा तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

फोन (011) 26164817/26197769 फैक्स (011) 26171554 ई-मेल: legal_del@mahabank.co.in
हेड ऑफिस : लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना दिनांकित 02-01-2020 जारी की थी, जिसमें 1. मैसर्स टीटू ट्रांसपोर्ट (कर्जदार) (स्वामी टीटू). 2. टीटू पुत्र श्री राजकुमार 3. श्रीमती कमलेश पत्नी श्री राजकुमार से बकाया राशि रु.9,30,586.00 (रूपए नौ लाख तीस हजार पांच सौ छियासी मात्र) + 02-01-2019 की प्रभावी तिथि से लागू नहीं किया गया संविदात्मक दर पर ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार एवं गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा 21 मार्च, 2020 को प्राप्त कर लिया है।

जबकि विशेष रूप से कर्जदार को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को संपत्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बकाया राशि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्यागूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बैंक को बंधक दी गई तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्तियां का विवरण निम्नानुसार है : प्रॉपर्टी स्थित है हाउस नं. 733, वार्ड नं. 4 मोहन नगर पलवल-121102 कुल क्षेत्रफल 92 वर्ग मीटर जो की श्रीमती कमलेश पत्नी श्री राज कुमार के नाम पर है।

मुख्य प्रबंधक एवं
तिथि : 21-03-2020 प्राधिकृत अधिकारी (सरफासी ऐक्ट, 2002)

POST OFFER ADVERTISEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

ALAN SCOTT INDUSTRIESS LIMITED

(CIN: L99999MH1994PLC076732)
("ASIL" / TARGET COMPANY"/"TC")
Registered Office: 39, Apurva Industrial Estate, Makwana Road, Off. Andheri Kurla Road, Mumbai-400 059 Phone No. +91-96532 38501
Email: alanscottindustrieslimited@gmail.com; Website: www.alanscottind.com

Open offer for acquisition of 1,78,199 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00 % of the total equity and voting share capital of the Target Company by Mr. Sureshkumar Pukhraj Jain (Acquirer) along with Mr. Pranav Dangi (PAC)

This Post offer Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, The Manager to the offer, on behalf of the Acquirer and PAC, in connection with the offer made by the Acquirer and PAC in compliance with regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 and subsequent amendments thereto **("SEBI (SAST) Regulation, 2011").**

The Detailed public statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer and PAC has appeared in Financial Express-English Daily-All editions, Financial Express-Hindi Daily-All editions, and Mumbai Lakshadeep, Marathi Daily Mumbai edition on 30.12.2019.

1. Name of the Target Company : Alan Scott Industriess Limited
2. Name of the Acquirers : Mr. Sureshkumar Pukhraj Jain
3. Name of the Manager to the offer : Navigant Corporate Advisors Limited
4. Name of the Register to the offer : Link Intime India Private Limited
5. Offer details
   a) Date of Opening of the Offer : Friday, 05.03.2020
   b) Date of the Closing of the offer : Monday, 19.03.2020
6. Date of Payment of Consideration : Friday, 03.04.2020
7. Details of the Acquisition :

S.No.	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actual
7.1	Offer Price	Rs. 25 per Equity Share	Rs. 25 per Equity Share
7.2	Aggregate number of Shares tendered	1,78,199	38,879
7.3	Aggregate number of Shares accepted	1,78,199	38,879
7.4	Size of the offer (Numbers of shares multiplied by Offer price per share)	Rs. 44,54,975.00	Rs. 9,71,975.00
7.5	Shareholding of the Acquirer and PAC before Share Purchase Agreements (SPAs) and Public Announcement (No.& %)	1,60,000 (23.34%)	1,60,000 (23.34%)
7.6	Shares Acquired by way of Share Purchase Agreements (SPA) • Number • % Fully Diluted Equity Share Capital	23,993 (3.50%)	23,993 (3.50%)
7.7	Shares Acquired by way of Open offer • Number • % Fully Diluted Equity Share Capital	1,78,199 (26.00%)	38,879 (5.67%)
7.8	Shares Acquired after detailed Public Statement • Number of Shares acquired • Price of the shares acquired • % of the shares acquired	Not Applicable	Not Applicable
7.9	Post offer Shareholding of Acquirer and PAC • Number • % Fully Diluted Equity Share Capital	3,62,199 (52.85%)	2,22,872 (32.52%)
7.10	Pre and Post Offer Shareholding of Public Shareholders	Pre Offer / Post Offer	Pre Offer / Post Offer
	• Number	5,01,384* / 3,23,185*	5,01,384* / 4,62,505*
	• % Fully Diluted Equity Share Capital	(73.15%) / (47.15%)	(73.15%) / (67.48%)
	*On Post Preferential Paid Up Capital		

*Including 10,000 Equity Shares held by Concord Capitals Private Limited, which will be classified as public category under Regulation 31A of SEBI (LODR) Regulations, 2015

8. The Acquirer and PAC accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the fulfillment of his obligations as laid down by SEBI (SAST) Regulations, 2011.
9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI.
10. Capitalized terms used in this advertisement and not define herein, shall have same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 18.02.2020

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirer and PAC :
MANAGER TO THE OFFER:

Navigant
NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
423, A Wing, Bonanza, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East),Mumbai-400-059. **Tel No.** +91 22 4120 4837 / 4973 5078
Email Id: navigant@navigantcorp.com,
Website : www.navigantcorp.com
SEBI Registration No: INM000012243
Contact person : Mr. Vikas Chhangani

Place : Mumbai
Date : 24.03.2020

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated February 12, 2020 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") ("NSE" and together with BSE, "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") followed by addendum thereto on February 20, 2020 ("Addendum").

ARROW

ARROW GREENTECH LIMITED

(CIN- L21010MH1992PLC069281)

Our Company was originally incorporated as "Arrow Coated Products Limited" as a public limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated October 30, 1992 issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Subsequently, pursuant to a special resolution of the shareholders dated 9thFebruary, 2016, the name of our Company was changed to "Arrow Greentech Limited" pursuant to which a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated 26thFebruary, 2016 was issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. For further details in relation to the changes to the name of our Company, please refer to the section titled "History and Other Corporate Matters" beginning on page 103 of the Letter of offer.

Registered Office: Solitaire Corporate Park Bldg No 3, 7th Floor, Unit No 372 Guru Hargovindji Marg Chakala, Andheri (East) Mumbai - 400093 **Tel:** +91 -22- 4074 9000 **Company Secretary & Compliance Officer:** Mrs. Poonam Bansal **Email:**poonam@arrowgreentech.com; **Website:**www.arrowgreentech.com

PROMOTER OF THE COMPANY : MR. SHILPAN PATEL

ISSUE OF 23,47,990 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF ARROW GREENTECH LIMITED ("ARROW" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 36 (INCLUDING SHARE PREMIUM OF RS. 26) PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. 845.28 LAKHS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 1 (ONE) EQUITY SHARE FOR EVERY 5 (FIVE) EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. THURSDAY, FEBRUARY 13, 2020 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS 3.60 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 281 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Arrow Greentech Limited wishes to thank all its members and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on February 28, 2020 and closed on March 13, 2020. Out of a total of 200 Composite Application Forms ("CAFs") (including 197 ASBA Applications), 19 applications were rejected on technical grounds. The total numbers of valid CAFs received were 181 for 24,86,543 Equity Shares, which was 1.05 times of the total Issue size. The Basis of allotment was approved in consultation with BSE, the Designated Stock Exchange on 18th March, 2020. The Capital Raising Committee, at its meeting held on 19th March, 2020, approved the issue and allotment of 23,47,990 Equity Shares. All valid CAFs (including ASBA applications) have been considered for allotment.

1. Basis of Allotment:

Category	No. of Valid CAFs (Including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional Equity Shares Applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Shareholders	178	12,14,555	7,33,270	19,47,825
Renouncees	3	4,00,165	Nil	4,00,165
Total	181	16,14,720	7,33,270	23,47,990

2. Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for			Equity Shares Allotted		
	Number	%	Number	Value (In Rs.)	%	Number	Value (In Rs.)	%
Shareholders	197	98.50%	20,86,880	7,51,27,680.00	83.91%	19,47,825	7,01,21,700.00	82.96%
Renouncees	3	1.50%	4,00,165	1,44,05,940.00	16.09%	4,00,165	1,44,05,940.00	17.04%
Total	200	100.00%	24,87,045	8,95,33,620.00	100.00%	23,47,990	8,45,27,640.00	100.00%

DISPATCH / REFUND ORDERS: The dispatch of allotment advice cum refund orders and allotment advice cum refund intimation to the Allottes, as applicable, have been completed on March 20, 2020. The refund instructions to HDFC Bank Limited (Escrow Collection Bank) for electronic credit cases and to the Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds was given by March 18, 2020. The listing application was filed with BSE and NSE on March 19, 2020. The credit in respect of allotment of Equity Shares offered pursuant to the Issue in dematerialized form in National Securities Depository Limited & Central Depository Services (India) Limited, as applicable was completed on March 23, 2020, to the respective demat accounts. The Equity Shares offered pursuant to the Issue are expected to commence trading on BSE and NSE with effect from March 26, 2020, pursuant to their listing and trading approvals and shall be traded under the same ISIN INE570D01018, as the existing Equity Shares.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

NO OFFER IN THE UNITED STATES

The Rights Entitlements and Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"), or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferredwithin the United States of America or the territories or possessions thereof (the "United States" or "U.S."), except in a transaction exempt from the registration requirements of the US Securities Act. The Rights Entitlements and Equity Shares referred toin the LOF arebeing offered and sold outside the United States in offshore transaction in reliance with Regulation S of US Securities Act. The offering to which the LOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Equity Shares or rights for sale in the United Statesor as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities. Accordingly, the LOF should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time. For further details, please see chapter titles "Notice to Overseas Shareholders" on page 10 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 270 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 273 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer clause of NSE" on page 274 of the LOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Navigant **NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED** 423, A Wing, Bonanza, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400 059 **Tel No.** +91-22-4120 4837 **Email Id-**navigant@navigantcorp.com **Investor Grievance Email:** info@navigantcorp.com **Website:**www.navigantcorp.com **SEBI Registration Number:** INM000012243 **Contact Person:** Mr. Vikas Chhangani	LINK Intime **LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED** C-101, 1st Floor, 247 Park Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Mumbai – 400 083 Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 4918 6200 **Facsimile:** +91 22 4918 6195 **Email:** arrowgreentech.rights@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Contact Person:** Mr. Sumeet Deshpande **SEBI Registration No:**INR000004058	**MRS. POONAM BANSAL** Arrow Greentech Limited Solitaire Corporate Park,Bldg No 3, 7th Floor, Unit No 372,Guru Hargovindji Marg,Chakala, Andhen (East),Mumbai - 400093 E-mail:poonam@arrowgreentech.com Website:www.arrowgreentech.com Tel: +91-22-4074 9000 Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and ComplianceOfficer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amountblocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

The LOF and Addendum are available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, theStock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, BSE Limited atwww.bseindia.com and the website of the Lead Manager to the Issue, i.e., Navigant Corporate Advisors Limited at www.navigantcorp.com. Investors should note that investment in equity shares involves adegree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 20 of the LOF.

For Arrow Greentech Limited
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mrs. Poonam Bansal
Company Secretary

Date: 23rd March, 2020
Place: Mumbai

जनसत्ता

मध्यप्रदेश की कुर्सी

लंबी राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की कमान संभाल ली है। करीब पंद्रह महीने तक वहां कांग्रेस की सरकार रही, पर कुछ विधायकों के असंतोष और फिर इस्तीफे के बाद वह अल्पमत में आ गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेसी विधायकों के पार्टी छोड़ने की वजह से भाजपा की संख्या सरकार बनाने के लायक हो गई और फिर शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ले ली। इस नाटकीय घटनाक्रम की मुख्य कड़ी बने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस आला कमान और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर भाजपा में शामिल हो गए। उनके पीछे-पीछे उनके समर्थक बाईस विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी। वे कई दिनों तक बंगलुरू के एक रिसॉर्ट में सुरक्षा घेरे के भीतर डेरा जमाए रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे संपर्क साधने, उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर वे अपने फैसले पर अडिग रहे। उन विधायकों का आरोप था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ उनके निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने, खासकर किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के मामले में अपेक्षित कदम नहीं उठा रही। अब वे विधायक भी भाजपा के पाले में चले गए हैं।

लोकतंत्र में सरकारें सदन में संख्याबल के आधार पर बनती और टिकी रहती हैं। इस दृष्टि से शिवराज सिंह चौहान का सत्ता में आना संविधान सम्मत है। पर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि इस तरह जनमत के विरुद्ध बनी सरकारें कहां तक जनतांत्रिक कही जा सकती हैं। चुनाव में लोग जिन प्रतिनिधियों को चुन कर भेजते हैं, उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वे उनके हितों का ध्यान रखेंगे। मगर जब वे निहित स्वार्थों के चलते पाला बदल कर ऐसे दल के साथ खड़े हो जाते हैं, जिसे लोगों ने नकार दिया है, तो वह उम्मीद धूमिल पड़ जाती है। मध्यप्रदेश में जनमत कांग्रेस के पक्ष में था, एक तरह से लोगों ने भाजपा को नकार दिया था। पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सीटों का फासला बहुत कम होने की वजह से कांग्रेस में टूट का लाभ भाजपा को मिला और वह फिर से सत्ता में आ गई। यह अकेला और नया उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी कई राज्यों में बहुमत हासिल करने वाले दल में फूट पैदा करके कम सीटें पाने वाले दल सत्ता पर काबिज हो जाते रहे हैं। इस प्रवृत्ति के चलते एक तरह से जनता को छला और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मखौल ही उड़ाया जाता है। इस तरह मध्यप्रदेश की नई सरकार भी सवालों से परे नहीं है।

शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्यप्रदेश की कमान संभाली है। उनकी छवि एक सौम्य नेता की रही है। प्रदेश में उनकी काफी लोकप्रियता है। पर व्यापमं घोटाले और किसानों के हितों की अनदेखी जैसे मुद्दों के चलते उन्हें ज्यादातर लोगों ने पिछले विधानसभा चुनावों में सत्ता से दूर कर दिया था। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में किसानों, व्यापारियों और युवाओं के लिए कुछ ठोस योजनाएं पेश की थी। उन्हें लेकर लोगों में कुछ उम्मीद जगी थी। सरकार बनने के बाद उनमें से कुछ पर उसने कदम भी उठाए थे। अब शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनौती यह होगी कि जिन मुद्दों पर सरकार की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी विधायक अलग हुए थे, उन मुद्दों पर वे कैसे और कितना व्यावहारिक कदम उठाते हैं।

संकट और राहत

देश में कोरोना महामारी के बीच मंगलवार को वित्तमंत्री ने जो कुछ घोषणाएं की, उनसे कारोबारियों और बैंक खाताधारकों को थोड़ी तो राहत मिलेगी। वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है और कंपनियों को अपने कर समय से चुकाने हैं। लेकिन पूर्ण बंदी के कारण सारे काम ठप हैं। ऐसे में कारोबारी चिंतित हैं। अब कारोबारी मार्च-मई की जीएसटी रिटर्न 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे। जिन कंपनियों का कारोबार पांच करोड़ रुपए तक है, उन्हें रिटर्न दाखिल करने में देरी हो जाने पर कोई विलंब शुल्क, जुर्माना या ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जिन कंपनियों का कारोबार पांच करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें पंद्रह दिन की छूट मिलेगी और इस अवधि में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर कोई विलंब शुल्क या जुर्माना नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अगर देरी हुई तो बारह के बजाय नौ फीसद की दर से ब्याज लिया जाएगा। इसी तरह टीडीएस जमा करने में देरी पर अठारह की जगह नौ फीसद ब्याज लिया जाएगा। कारोबारियों पर नियत अवधि में कर जमा करने का जो दबाव रहता है, उसमें यह थोड़ी राहत जरूर है। इसी तरह बैंक खाताधारकों के लिए न्यूनतम शेष राशि और डेबिट कार्ड तथा एटीएम पर लगने वाले शुल्क भी फिलहाल खत्म कर दिए गए हैं।

भारत में कोरोना महामारी जिस तेजी से फैल रही है, उसका अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ना स्वाभाविक है। इसे रोकने के लिए देशभर में पूर्ण बंदी लागू कर दी गई है। औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन बंद है। दवा और किराना दुकानों को छोड़ कर बाजार पूरी तरह से बंद हैं। जाहिर है, अर्थतंत्र के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अभी कारोबारियों की सबसे बड़ी चिंता यह बनी हुई है कि कब हालात सुधरेंगे और काम-धंधा शुरू होगा। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए सरकार को पूर्ण बंदी जैसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा असर उन छोटे और मझोले कारोबार पर पड़ा है, जो छोटी पूंजी से चलते हैं और अचानक काम बंद होने से उन्हें अगले महीने अपने कर्मचारियों को वेतन देने का संकट खड़ा हो गया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि इस बंदी के दौरान कोई भी संस्थान किसी भी कर्मचारी का वेतन और छुट्टी न काटे और उसे काम पर माना जाए। ऐसे में उद्योगों का संकट अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है।

छोटे और बड़े उद्योगों के सामने संकट कर्मचारियों को बंदी के दौरान वेतन देने का तो है ही, इसके साथ ही बैंक कर्ज की मासिक किस्तें चुकाने का भी है। उद्योगों के समक्ष वैसे ही कई तरह के दबाव हैं, जिनसे वे जूझ रहे हैं। हालांकि कोरोना संकट के दौरान उद्योगों को राहत के मुद्दे पर प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से बात कर चुके हैं। इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों के लिए घोषणाएं कर सकती है। रियल एस्टेट जैसे कुछ क्षेत्र, जो लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे हैं, अब कोरोना संकट के कारण और ज्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा कंपनियों में उत्पादन बंद होने से चौथी तिमाही के नतीजे भी निराशाजनक रहेंगे और इसका असर जीडीपी की वृद्धि पर पड़ेगा, जो पहले से ही काफी कम है। इस वक्त पहली प्राथमिकता कोरोना से निपटने की है, लेकिन अचानक बंदी से जो संकट खड़ा होगा, वह भी कम गंभीर नहीं है।

कल्पमेधा

अधिकार के कारण जो श्रद्धा-भक्ति होती है, वह सच्ची नहीं होती।

-एमर्सन

महिला सुरक्षा और समाज

भारत डोगरा

देश व समाज का अधिक ध्यान राजनीतिक और आर्थिक बदलावों पर केंद्रित रहता है। इसकी तुलना में सामाजिक बदलाव से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। कौन से बदलाव अच्छे हैं और कौन से बुरे, कहां हस्तक्षेप की जरूरत है, कहां नहीं, इस बारे में बहुत कम बहस होती है। इसी का नतीजा है कि भारतीय समाज में कई बुराइयां तेजी से बढ़ती चली गईं और समाज चुपचाप देखता रहा।

महिला विरोधी हिंसा, विशेषकर यौन हिंसा असहनीय हद तक क्रूर रूप में बार-बार सामने आ रही है। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न सरकारें कई कदम उठाने का दावा करती रही हैं, पर उनका अपेक्षित असर नजर नहीं आ रहा है। इस स्थिति में यह विमर्श बहुत जरूरी है कि क्या कमी रह गई है और किस दिशा में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है।

पहली जरूरत यह है कि समाज के बढ़ते अपराधीकरण को समग्र रूप से कम किया जाए। एक ओर गिरोहों के रूप में बड़े और छोटे अपराधी बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर प्रतिष्ठा प्राप्त सफेदपोश अपराधियों की तादाद में इजाफा चिंताजनक है। ऐसे लोग विभिन्न क्षेत्रों में बहुत शक्तिशाली हैं। जब तक विभिन्न स्तरों पर अपराधीकरण होता रहेगा और उसे संरक्षण देने की घातक प्रवृत्ति हर स्तर बनी रहेगी, तब तक यौन हिंसा भी खुले व छिपे रूप में इससे जुड़ कर बढ़ती रहेगी। कभी-कभी किसी बड़ी घटना के रूप में सामने आएगी, लेकिन अधिकतर मामलों में यह छिपी रहेगी। और ऐसा तब ज्यादा होगा जब हर तरह से संपन्न लोग इसे अंजाम देंगे, क्योंकि उन्हें किसी का भी खौफ नहीं रहेगा और संरक्षण मिलता रहेगा। अगर समाज का अपराधीकरण तेजी से हो रहा है, जहां राजनीतिक जगत और यहां तक कि आध्यत्मिक जगत सब जगह ऊंचे स्तर पर अपराधी तत्त्व पहुंच रहे हैं, वहां यौन हिंसा को कम करना कठिन ही नहीं, असंभव है। अतः समाज के अपराधीकरण को कम करना एक बड़ी जरूरत है।

महिलाओं के प्रति हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए दूसरी बड़ी जरूरत शराब और अन्य तरह के नशों पर लगाम लगाने की है। विश्व में विभिन्न स्तरों पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि आश्चर्यजनक हद तक यौन अपराध नशे के कारण होते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों के अध्ययनों से यह सच्चाई बार-बार सामने आई है। यदि हम अपने ही देश में हाल के यौन हिंसा के बड़े मामलों पर नजर डालें तो इनमें शराब की भूमिका स्पष्ट नजर आती है। शराब के नशे से भले और बुरे के फर्क को समझने में कमी आती है, अक्सर विवेकहीनता हावी हो जाती है जो गलत कार्यों के लिए प्रेरित करती है। बुरा काम करने में स्वाभाविक रूप से जो रोक मनुष्य के दिल-दिमाग में रहती है, वह रोक नशे के दौरान हटती है। बुरे काम का बाद में क्या असर होगा, उसके शिकार बने व्यक्ति पर क्या असर होगा, यह सब तरह की सोच जो होश-हवास में दिल-दिमाग में आती है, वह नशे के दौरान खत्म हो जाती है। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने से पहले अपराधी शराब पी लेते हैं और इस तरह अपने को अनैतिक कार्य के लिए तैयार करते हैं।

यह स्पष्ट है कि शराब या अन्य नशे से महिला विरोधी हिंसा और विशेषकर अधिक क्रूर किस्म की यौन हिंसा बढ़ती है। जहां यौन हिंसा का माहौल बनाया जाता है, वहां प्रायः शराब व अन्य नशे का सेवन होता है। हालांकि इस तरह के अनेक अध्ययन दुनिया में उपलब्ध हैं, पर हमारे देश में जब यौन हिंसा पर बहस होती है तो प्रायः इस संबंध की अवहेलना होती है। दूसरी ओर अधिकांश सरकारें शराब का तेज प्रसार करने में जुटी हैं। जिन गांवों में पहले शराब उपलब्ध नहीं थी, वहां सरकारों ने तेजी से ठेके खोल दिए हैं। इसका एक असर यह हुआ है कि इन गांवों में महिला-विरोधी हिंसा बढ़ गई है। शराब सरकारों के लिए राजस्व का बड़ा जरिया है।

तीसरी बड़ी जरूरत यह है कि पोर्नोग्राफी यानी अश्लीलता के प्रसार को कम किया जाए। इस विषय पर भी अनेक अध्ययन उपलब्ध हैं कि अश्लील साहित्य और फिल्में, विशेषकर हिंसक अश्लील फिल्मों के प्रसार से यौन अपराध बढ़ते हैं। पर इन अध्ययनों से सही स्थिति सामने आने के बावजूद भारत सहित दुनियाभर में पोर्नोग्राफी का प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि अब तो दूर-दूर के गांवों तक में यह इसका जाल फैल चुका है। कुछ गांवों में इस बारे में पूछताछ करने पर ये तथ्य सामने आए कि समाज में कितनी तेजी से अश्लीलता का असर बढ़ा है और इसके प्रतिकूल परिणाम महिलाओं को झेलने पड़ रहे हैं। यह एक ऐसा बदलाव है जो काफी हद तक चोरी-छिपे आया है और इसके व्यापक असर पर गंभीर सामाजिक

विमर्श हुआ ही नहीं है। फिलहाल विभिन्न अध्ययनों के आधार पर इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अश्लील फिल्मों, वीडियो और साहित्य के अनियंत्रित प्रसार को कम करना जरूरी है।

चौथी जरूरी बात यह है कि समाज में लैंगिक संवेदनशीलता और नैतिकता बढ़ाने के प्रयास हों और ये प्रयास समाज में व्यापक संवेदनशीलता और नैतिकता का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हों। यदि लैंगिक संवदेनशीलता और नैतिकता के प्रयास अलगाव में किए जाएंगे, तो इनका सीमित असर ही हो सकेगा। पर यदि सार्थक सामाजिक बदलाव की एक व्यापक समझ के अंतर्गत इनका प्रसार होगा तो इनका अधिक मजबूत और दूरगामी असर होगा। इस समय यह प्रयास बहुत कम हैं। इसके अतिरिक्त लैंगिक संवदेनशीलता व नैतिकता के प्रयासों को स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति के अनुरूप बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं हो पा रहा है और जो सीमित प्रयास हो रहे हैं, उन पर पश्चिमी असर अधिक है। अतः इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है।

महिला हिंसा रोकने के लिए अधिक व्यापक जरूरत तेज सामाजिक बदलाव की स्थिति को समझने और संभालने पर ध्यान देने की है। इस पर अधिक नियोजित ढंग से कार्य होना चाहिए। हाल के वर्षों में हमारे देश और समाज में आश्चर्यजनक स्तर पर तेजी से अनेक बदलाव आए हैं। पर इन बदलावों को समझने के प्रयास बहुत कम हुए हैं। देश व समाज का अधिक ध्यान राजनीतिक और आर्थिक बदलावों पर केंद्रित रहता है। इसकी तुलना में सामाजिक बदलाव से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। कौन से बदलाव अच्छे हैं और कौन से बुरे, कहां हस्तक्षेप की जरूरत है, कहां नहीं, इस बारे में बहुत कम बहस होती है। इसी का नतीजा है कि भारतीय समाज में कई बुराइयां तेजी से बढ़ती चली गईं और समाज चुपचाप देखता रहा। हालांकि इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि परंपरा अच्छी थी और आधुनिकता बुरी है। परंपरागत समाज में महिलाओं पर जो बिना वजह की रोक-टोक थी, वह बहुत अनुचित थी और उनकी प्रगति में बाधक थी। इस तरह की रोक-टोक को दूर करना चाहिए। खुले माहौल में युवक-युवतियों को मिलना चाहिए, साथ पढ़ना चाहिए, जिम्मेदारियां एक साथ संभालनी चाहिए। सभी तरह के संकीर्ण बंधनों से मुक्त विवाह होने चाहिए। यह सब तो आधुनिकता के सार्थक पक्ष हैं, लेकिन साथ ही अनेक हानिकारक पक्ष भी हैं और उनके प्रति सावधानी अपनाना जरूरी है। परंपरागत समाज की कुछ मर्यादाएं थीं, तो आधुनिक समाज की भी कुछ नई मर्यादाएं बनानी पड़ेंगी, उन्हें प्रतिष्ठित करना होगा। लेकिन हमने इस कार्य की उपेक्षा की है।

यदि इन पांच स्तरों पर निष्ठा और सूझ-बूझ से कार्य किया जाए तो महिला हिंसा और यौन हिंसा में निश्चय ही बहुत कमी आएगी। यदि बड़ा अभियान चला कर शराब के उपभोग को कम किया जाता है तो इससे महिला हिंसा कम करने में तो मदद मिलेगी ही, इसके साथ समाज को जो लाभ प्राप्त होंगे, वे अलग हैं। महिला हिंसा को टिकाऊ तौर पर कम करने वाले अधिकांश कदम ऐसे ही हैं जो अनेक अन्य लाभ भी साथ ही देते हैं।

डर का मुकाबला

योगिता यादव

दुनिया भर में इस वक्त कोरोना सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। इसमें तेरह मार्च की तारीख खास है, जब कोरोना से हुई भारत में दो मौतों के बाद से इस पर तनाव और ज्यादा बढ़ने लगा। कोरोना यानी 'कोविड-19' के कारण अर्थव्यवस्था की सांस पहले ही फूलने लगी है। सेंसेक्स लुढ़कने से होने वाला नुकसान मास्क और सेनिटाइजर भी नहीं बचा पाएंगे। शुक्रवार को ही इस वायरस के कारण सबसे पहले कर्नाटक के एक छिहत्तर वर्षीय शख्स की मौत की खबर आई तो दिल्ली की एक उनहत्तर वर्षीय महिला की भी कोरोना के कारण मौत हो गई। पहले मामले में जहां शख्स खुद सउदी अरब से लौटा था, वहीं दूसरे मामले में महिला का बेटा विदेश यात्रा से लौटा था।

कोरोना पर बढ़ते तनाव के बीच हवाईअड्डे पहले ही अतिसंवेदनशील हो गए थे। अब आलम यह है कि स्कूल, मॉल, बाजार, सिनेमाघर सहित सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद किया जाने लगा है। इसके साथ ही कोरोना से बचने में कारगर बहुत जरूरी चीजों में मास्क, सेनिटाइजर आदि की जमाखोरी भी शुरू हो गई है। भारत में भी एहतियात की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मास्क, गाउन, सेनिटाइजर जैसी चीजों की कमी बताई और दुनिया के सभी देशों से इसका उत्पादन बढ़ाने की अपील की है। ताकि बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके। सब्जियों की खरीद भी चिकेन से ज्यादा बढ़ गई है। अब मोबाइल पर वे वाट्सएप स्टीकर ईजाद कर लिए गए हैं जो कोरोना से बचाव के तरीके सिखा रहे हैं। एक स्वामी ने कोरोना वायरस से बचने का दावा करते हुए 'गौमूत्र पार्टी' आयोजित करने की घोषणा भी कर दी। कहीं शिवलिंग तक को मास्क पहनाने की खबर आई।

दुनिया मेरे आगे

यह एक वायरसजनित बीमारी के 'मास हीस्टिरिया' यानी एक आम उन्माद में बदलने के संकेत हो सकते हैं जिन पर बहुत एहतियात से काबू पाना जरूरी है। हालांकि इससे पहले स्पेनिश फ्लू जैसा खतरनाक वायरस 1918 में भारी तादाद में लोगों की जान ले चुका है। रशियन फ्लू, एशियन फ्लू और हॉन्गकॉन्ग फ्लू ऐसे वायरस रहे हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया था। इस सबसे जानमाल का तो नुकसान हुआ था, पर भौकाल इतना नहीं मचा, जितना इस बार मच रहा है। पिछले कुछ सालों के इसी मौसम पर गौर करें तो जीका, निपाह जैसे कई वायरस इन्हीं दिनों में फैलते हैं। यही मौसम सर्दी-जुकाम जैसे मौसमी बुखार के फैलने का भी वक्त होता है जिस दौरान सूर्य की रोशनी कम मिल पाती है। गरमी बढ़ने के साथ ही धीरे-धीरे ये नियंत्रण में आने लगते हैं। लेकिन कोरोना के जो लक्षण सामने आए हैं, उसमें हर स्तर पर एहतियात बरतना जरूरी है, लेकिन साधारण सर्दी-जुकाम के प्रति भी कोरोना जैसा तनाव होना बेमानी है।

बेहद तनावपूर्ण माहौल में कई देशों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी मसले पर आम उन्माद यानी 'मास हीस्टीरिया' में लोगों के एक बहुत बड़े समूह को एक जैसी भावनाओं की अनुभूति होने लगती है। इसमें भावनात्मक डर और असुरक्षा ही नहीं, बल्कि तेज सिर दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ, घुटन आदि भी शामिल है। यही वजह है कि 'मास हीस्टिरिया' को सिर्फ मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं कहा जाता, बल्कि इसे 'मास साइकोजेनिक इलनेस' यानी मनोवैज्ञानिक रूप से व्यापक स्तर पर फैली बीमारी के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारी के कारण शारीरिक समस्याएं भी पेश आने लगती हैं। कोरोना के कारण जिस तरह से दुनिया भर में बनने वाले 'मास हीस्टिरिया' के संकेतों को समझते हुए दुनिया के कुछ देशों की ओर से इसे रोकने की अपील की गई है और सही जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इससे माहौल को तनावपूर्ण होने से बचाया जा सकता है।

कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसके आसपास उभरे हुए तिकोने जैसे हैं, जिसके कारण वे मुकुट यानी क्राउन की सी झलक देते हैं। यही इसे अन्य वायरस से संरचना और आकार में अलग करता है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इससे बचाव में किसी भी तरह का मास्क सुरक्षित हो सकता है। साधारण रूमाल से भी अपने मुंह को ढक कर इससे बचाव किया जा सकता है। अफवाहों और गलत उदाहरणों के चक्कर में पड़ने के बजाय यह जरूरी है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचा जाए जहां अजनबी लोगों की भीड़ होती है। कोरोना के कारण हुई मौतों पर गौर करें तो इसमें मरने वाले ज्यादातर लोग उम्रदराज थे। इस उम्र में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि निजी स्वच्छता के साथ ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी खास खयाल रखा जाए। इसे बढ़ाने में विटामिन सी से भरपूर सिट्रस फल कारगर सिद्ध होते हैं। जिस तत्परता, समझदारी और तैयारी से चीन ने इसे नियंत्रित किया है, वह हम सबके लिए एक सबक है।

महामारी से जंग

अब समय आ गया है कुछ कर दिखाने का। स्वयं को सुरक्षित रखते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र को सुरक्षित रखने का। कृतसंकल्पित होकर उस वैश्विक महामारी से लड़ने का जो भारत में भी पैर पसार चुकी है, सरकार द्वारा जारी किए जा रहे दिशा-निर्देशों का गंभीरता के साथ पालन करने का। संकट काल गहरा है और कितने समय बना रहेगा, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। सब कुछ हम स्वयं पर, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि हम कितने गंभीर और सजग हैं कोरोना को हराने के लिए।

अभी और इसी समय से ही अगर हम नहीं जागे तो पूर्व में किए गए प्रयास बेकार चले जाएंगे। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई इस महाआपदा की गंभीरता को देखते हुए लापरवाही बरतने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रविवार को 'जनता कर्फ्यू' काफी हद तक सफल माना जा सकता है, लेकिन उसके बाद से जनता द्वारा लापरवाही के लक्षण सामने आने लगे हैं। यदि आपको लगता है कि मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है या हमारे यहां तो कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया है, तो आपका यह सोचना गलत है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।

अब प्रश्न यह उठता है कि जनता कर्फ्यू में क्या हमारा धैर्य चंद घंटों के लिए ही था? क्या हमारी इच्छाशक्ति इतनी कमजोर है कि हम अपने आप को संयमित नहीं रख पा रहे हैं, घर से बाहर निकलने को उतावले हो रहे हैं, क्या हमारे उपदेश सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने, शेयर और लाईक तक ही सीमित है? आचरण में आत्मसात करने के लिए नहीं। जबकि आवश्यकता है कोरोना को हराने के लिए कई दिनों तक धैर्य और संयमित बने रह कर अपना श्रेष्ठ नागरिक कर्त्तव्य निभाने की।

ज्ञात रहे कोरोना वायरस से निपटने और संक्रमण फैलने से रोकने के लिए राजस्थान सरकार सहित देश की अनेक राज्य सरकारों ने संपूर्ण बंदी (लॉक डाउन) लागू कर दी है। शासन-प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, हमें भी उनके आदेशों का अक्षरशः पालन कर-के अपनी नैतिक जिम्मेदारी और कर्त्तव्य को निभाना है। पूर्ण बंदी एक आपदा व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त सरकारी तौर पर लागू की जाती है। इसलिए जरूरी है कि सरकार द्वारा घोषित लॉक डाउन के नियमों का पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा से पालन करें तथा कोरोना के विरूद्ध युद्ध में सुरक्षा वीर बनें। सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, हमें शासन-प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला कर साथ देना है, तभी हम कोरोना को मात दे सकेंगे।

● *विवेक मित्तल, बीकानेर*

गरीब और रोटी

जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पूरे भारत में पूर्ण बंद लागू किया जा चुका है। पंजाब, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में कर्फ्यू भी लगा हुआ है। ऐसे में भारत की अधिकांश गरीब जनमानस जो रोजाना मजदूरी करके, रिक्शा चला कर और अन्य माध्यमों से अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, वह आज अपने घरों में कैद है। यह भारत का वह तबका है जो रोजाना कुआं खोदता था, तब जाकर प्रत्पिानी मिलता था। लेकिन अब बंदी में इस तबके के पास आय का कोई साधन नहीं है। इनके जनधन खाते में भी मुश्किल से 500 रुपए होंगे। जो हालात हैं उसमें तो लग रहा है कि इस महामारी से लड़ने के लिए भारत को दो-तीन महीने लग सकते हैं। ऐसे में भारत का यह गरीब तबका कोरोना के बजाय भूख से ही मरने लगेगा, जो बहुत ही दुखद होगा। ऐसे में भारत सरकार से अनुरोध है कि वो इनके लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज जारी करे, जिससे कम से कम जनहानि हो सके। भविष्य में आने वाली इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को प्रदान किए गए जीवन के अधिकार में आने वाले भोजन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए तत्काल इन तबकों के लिए मुफ़्त संतुलित आहार की व्यवस्था करे।

● *आकाश सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय*

नक्सलियों की चुनौती

छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले से सीआरपीएफ के 17 जवान शहीद हो गए। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें नक्सलवादियों ने घात लगा कर सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं। सरकारों ने कई बार नक्सलवादियों से संवाद के जरिए हल खोजने का प्रयास किया, हालांकि इसमें नाकामी हाथ लगी। जहां आज समूचा विश्व कोरोना वायरस से लड़ने में व्यस्त है और हमारी केंद्र व राज्यों की सरकारें कोरोना वायरस से निपटने के लिए सख्ती के साथ असाधारण प्रयासों में जुटी है, वहीं पर नकस्ली मौकापरस्ती में जुटे हैं। इसी का ही परिणाम है कि एक बार फिर हिंसक घटना को अंजाम देकर वे अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। अब वह समय आ गया है जब नक्सलियों का खात्मा जरूरी हो गया है, अन्यथा यह देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकते है । सरकार को कुछ विशेष प्रयास करने होंगे जिससे यह नक्सली नासूर को खत्म हो।

● *अली खान, जैसलमेर*

सबक की जरूरत

कहावत है 'एक सेहत हजार नियामत'। सेहतमंद इंसान अगर फकीर भी हो तो उसका जैसा धनवान दुनिया में कोई नहीं। देश दुनिया इन दिनों कोविड 19 विषाणु से युद्धरत है। हमेशा के भांति जीत तो इंसानों की ही होगी, भले थोड़ा समय लगे। चीन का हुबेई प्रांत के बाद, इस समय यूरोप इस वायरस का केंद्र बना हुआ है। काश विश्व का उन्नत महाद्वीप, चीन से शिक्षा लेता। शहरों घरों को लॉक डाउन किया होता तो इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का वैसा हाल नहीं होता जो आज हो रहा है। हालांकि भारत ने इस वायरस का फैलाव रोकने में सफलता पा ली है। इसके लिए सरकार की कड़ी निति और जनता का सहयोग को श्रेय दिया जाना चाहिए। यह वही भारत है जहां 1918 में स्पेनिश फ्लू के कारण एक करोड़ बीस लाख लोग मारे गए थे। 1974 में चेचक महामारी ने पंद्रह हजार लोगों की जान ले ली थी।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी (जमशेदपुर)*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

दिल्ली में समारोह की बुकिंग रद्द

कोरोना संक्रमण की वजह से आम लोगों ने अपने कार्यक्रमों में भी बदलाव किया है। इस वजह से पूजा समारोह, गोद भराई, सगाई जैसे कार्यक्रमों को टाला जा रहा है। बरदेव पुरी में भगवती टेंट हाउस के मालिक अजय भारद्वाज बताते हैं कि उनके नवरात्र के दिनों के लिए कई बुकिंग थी। 16 -17 अप्रैल से शादियों का सीजन है। इसके लिए अभी से विभिन्न आयोजन की शुरुआत होती है। लेकिन अब तक की सभी बुकिंग रद्द हुई हैं। लोगों ने अपने कार्यक्रम टाल दिए हैं।

बंदी तो ठीक पर ऐसा खौफ, सन्नाटा कभी नहीं देखा

ओमप्रकाश ठाकुर
शिमला

कोरोना विषाणु ने देवभूमि में जिंदगी की रफ्तार ठप कर दी है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के तीन मरीज आए हैं जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये सभी विदेश से आए थे। इन तीन मामलों से प्रदेश में हड़कंप मच गया है और सहमी सरकार ने पूर्ण बंदी कर दी है। प्रदेश के आज तक के इतिहास में ऐसी बंदी पहली बार हुई है। प्रदेश के सभी शक्तिपीठ पहली बार बंद हुए। नवरात्रों के लिए शक्तिपीठों के किवाड़ पहली दफा बंद हुए हैं। ऐसा पहली बार है कि आनन-फानन में बजट कुछ मिनटों में पास हुआ है।

बंदी से लोग घरों में दुबक गए हैं। लोगों में खौफ है। ऐसा पहली बार है कि शहरों से गांवों की ओर पलायन हुआ है। शिमला में परिवार संग रह रहे महेंद्र वर्मा कहते हैं कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। वे अपने दो छोटे बच्चों और पत्नी को लेकर अपने गांव सुन्नी चले गए हैं। परिवहन निगम के चालक व परिचालक भी अपने गांवों को चले गए हैं।

पूर्ण बंदी के कारण जो लोग घर नहीं आ पा रहे हैं वे अपने कार्यस्थलों पर ही रुक गए हैं। पांवटा में निजी कंपनी में कार्यरत ललित कहते हैं कि वे घर जाना चाहते थे लेकिन बसें नहीं चल रही हैं। ऐसे में वे किराए के ही मकान में रह गए हैं। वे घर जाने के लिए जुगाड़ की तलाश कर रहे हैं। घर में अभिभावक चिंता में है।

सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना उन अभिभावकों को करना पड़ रहा है जिनके बच्चे छोटे हैं। उन्हें बच्चों के लिए दूध जुटाने की चिंता हो गई। राजधानी में रह रहे अनूप हांडा कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ। उनके चार साल व डेढ साल की दो बेटियां हैं। वे गांव नहीं जा पाए हैं। वे कहते हैं कि दो दिनों तक का दूध तो खरीदा हुआ है। लेकिन आगे मुश्किल होगी। इसी तरह सब्जी भाजी को लेकर भी चिंता है। वे कहते हैं कि राशन तो एक सप्ताह पहले ही खरीद लिया था। राजधानी के बाजार सूने पड़े हैं। कुछ ही दुकानें खुली हैं, वहां भी ज्यादा भीड़ नहीं है। ऐतिहासिक रिज व माल रोड पर भी नाम की ही चहल-पहल है।अधिकांश लोग घरों में दुबके हैं। सड़कें पूरी तरह से सूनी है। कहीं-कहीं छोटे वाहन चल रहे हैं। चूंकि निजी व सरकारी कार्यालय बंद हो गए हैं तो लोग गांवों में आकर खेतों व दूसरे लंबित काम निपटाने में लगे हैं। चूंकि बंदी का पहला ही दिन है तो ज्यादातर लोग घरों में आराम कर रहे हैं।

साहित्यकार व शिक्षक दिनेश कंवर कहते हैं कि उन्हें पढ़ने-लिखने का मौका मिल गया है। लेकिन दहशत तो है ही। प्रवासी मजदूर काम की तलाश में हैं। चूंकि सब कुछ बंद पडा है तो वे भी आराम फरमा रहे हैं लेकिन उन्हें चिंता इस बात की है कि अगर ये बंदी लंबी चली तो उन्हें मुश्किल होगी। नेपाली मजदूरों के ठेकेदार दिलबाग बहादुर कहते हैं कि एक सप्ताह तक तो वे बिना काम के चला लेंगे लेकिन उसके बाद उन्हें काम पर निकलना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा मुश्किलें इसी मजदूर वर्ग की है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर जरूरी चीजों की दुकानें कहीं-कहीं खुली हैं। पुलिस ने जगह-जगह नाके लगा दिए है। वाहनों को प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। कहीं-कहीं पुलिस के वाहन जरूर नजर आ रहे हैं।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े

कोराना विषाणु देशों से लौटे कुल लोग :	1491
28 दिन तक एकांत पूरा करने वाले लोग :	474
घरों में पृथक रखे गए लोग : 800	
पाजिटिव पाए गए लोग : 3	मौत : 1

हिमाचल प्रदेश

> “ आपातकाल के दिनों में भी ऐसा ही हुआ था लेकिन यह लंबा नहीं चला था। उस समय कोरोना विषाणु जैसी खौफनाक बीमारी का खौफ भी नहीं था। लोग एक-दूसरे से दूरी नहीं रखते थे। इस बार तो घरों में सदस्यों के बीच अजीब सा व खामोश सा खिंचाव व तनाव सा है। वह अलग दौर था लेकिन बाजार तब भी बंद हुए थे। आपात काल के समय गांवों में तब कोई भी असर नहीं पड़ा था। धामी के रहने वाले 84 वर्षीय हरी राम ठाकुर कहते है कि उनके जीवन में ऐसा खौफ पहली बार है व ऐसा सन्नाटा पहले कभी नहीं रहा।
> **- बलदेव शर्मा, 51 वर्षीय शिमला निवासी**

ऐसी दहशत तो भूकम्प में भी नहीं दिखी

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

उत्तराखंड में कोरोना के डर ने मैदान से लेकर पहाड़ तक सब जगह जनजीवन ठप कर दिया है। मानों जिंदगी ठहर सी गई है। कोरोना का डर और पुलिस की सख्ती ने लोगों को घरों में दुबके रहने के लिए विवश कर दिया है। उत्तराखंड में बसों और कारों के पहिए ठहर से गए हैं। जहां राज्य के मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बाजारों और होटलों में देर रात तक चहलकदमी होती थी, वहीं अब भरी दोपहरी में ही सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, मसूरी, रानीखेत में आम दिनों में शाम जिंदगी ठहर सी जाती थी, अब सुबह से शाम तक लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं।

उत्तराखंड

उत्तरकाशी के समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि 20 अक्तूबर 1991 में उत्तरकाशी में आए भीषण भूकम्प की दहशत भी कोराना वायरस के दहशत के आगे नही ठहरती है। जिस भूकम्प में सैंकड़ों लोगों की जानें चली गई थी और दर्जनों गांवों में मकान मलबे में तब्दील हो गए थे। पहाड़ों में उस भूकम्प की इतनी ज्यादा दहशत नहीं थी, जितनी कोरोना वायरस की है। उस समय तो हम लोगों की जान बचाने के लिए और काम करने के लिए घरों से बाहर निकल जाते थे, परंतु आज कोरोना वायरस के डर से घरों में दुबके हुए हैं।

सभी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं पर लगी रोग

हरिद्वार के मंसादेवी, चंड़ी देवी, दक्षेश्वर महादेव, बिल्केश्वर महादेव, निलेश्वर महादेव, गौरी शंकर महादेव, दरिद्रभंजन, दुखभंजन महादेव, भारत माता मंदिर समेत सभी मंदिर और आश्रम, होटल, धर्मशालाएं, मॉल बंद कर दिए गए हैं। वहीं ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम, वीरभद्र महादेव मंदिर, स्वर्गाश्रम, देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर, उत्तरकाशी में विश्वनाथ महादेव मंदिर, कुमाऊं में जागेश्वर महादेव मंदिर, श्रीनगर गढ़वाल में धारीदेवी मंदिर, पौड़ी गढ़वाल के कोटलार का सिद्धबली मंदिर समेत उत्तराखंड के पवतीय क्षेत्रों के पौराणिक मंदिर और आश्रम तीथर्यात्रियों और स्थानीय लोगों के दर्शन के लिए बंद कर दिए गए हैं। जिससे इन मंदिरों और आश्रमों की आमदनी बिल्कुल ठप हो गई है।

हरकी पैड़ी गंगा आरती देखने वाले श्रद्धालुओं पर लगी रोक

हरिद्वार में हरकी पैड़ी पूरी तरह सील कर दी गई है और हरकी पैड़ी पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने वाले श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिस कारण दूसरे राज्यों से गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी गई है। गंगा सभा के अध्यक्ष पंडित प्रदीप झा ने बताया कि हरकी पैड़ी पर केवल गंगासभा के चुनिंदा पुजारी ही शाम में आरती करते हैं। उन्होंने कहा कि 103 साल के गंगा सभा के इतिहास में पहली बार किसी महामारी के कारण गंगा आरती देखने वाले श्रद्धालुओं पर पाबंदी लगाई गई है। हरिलार के गंगा घाट सूने पड़े हैं। गंगा घाटों पर न तो पंडे दिखाई दे रहे हैं और न ही तीर्थयात्री।

राष्ट्रीय राजधानी ने कभी नहीं देखे ऐसे हालात

पंकज रोहिला
नई दिल्ली।

कोरोना संक्रमण की वजह से देश व दिल्ली ने अब तक का सबसे बड़ा बंद देख लिया है। 1975 का आपातकाल हो या 1984 के दंगे ऐसे बंद के हालात दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखे। लोगों का कहना है कि बंद ने 70 साल पुरानी यादों को भी पीछे छोड़ दिया है।

बंद का असर छोटे बाजारों पर भी साफ नजर आ रहा है। पूर्वी दिल्ली के नत्थू कॉलोनी क्षेत्र में एक किराना स्टोर पर लोग को एक- एक फुट का अंतर बनाकर रखने की अपील की जा रही थी। जरूरी सामान की वजह से लाइनों में लगकर सामान की खरीदारी हुई। लोग दूर रहे इसके लिए विशेष तौर पर एक मेज लगा दी गई थी। नवरात्र की शुरुआत किसी भी नए काम के लिए शुभ मानी जाती है। इस बार नवरात्र में कोरोना संक्रमण का खतरा कपड़ा बाजार पर भारी पड़ा है। कपड़ा कारोबारी महेश शर्मा ने बताया कि तीन दिन से दुकानें बंद है। बंद तो बहुत हुए पर पहले कभी ऐसा बंद नहीं देखा। पहले बंद होता था लेकिन दुकानें ही बंद हो जाए तो उसे बंद मान लिया जाता था। लेकिन इस बार सभी कामकाज ठप है। नोटबंदी के समय ही सरकार को समर्थन के हालात नजर आए थे या अब बंद ने ऐसा माहौल दिखाया है।

-विजय कुमार मल्होत्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता

सत्तर साल बाद दिल्ली में ऐसा बंद हुआ है। मुझे याद है कि पुरानी दिल्ली में हिंदू मुसलिम झगड़े हुए थे। चांदनी चौक में हर तरफ तनाव था। पर यह भी विशेष मोहल्ले व क्षेत्र तक सीमित था। देश में लगे आपात काल में भी ऐसे हालात नहीं थे।

-जय प्रकाश अग्रवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

पूरी दिल्ली में ऐसा बंद कभी नहीं देखा। अबतक जब भी बंद देखने को मिला है, वह भी किसी क्षेत्र विशेष में ही नजर आता था। महामारी की वजह से पहली बार यह बंद है। केवल 84 के दंगों में ही लोग कई दिनों तक घरों में बंद रहे। केंद्र व दिल्ली सरकार इसके लिए काम कर रही हैं।

-एनडी गुप्ता, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी

दिल्ली

बंदी से थमी जिंदगी की रफ्तार

तमन्ना अख्तर
उधमपुर।

कोरोना विषाणु की लगातार बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर प्रशासन हर तरह से सावधानी बरतने के साथ-साथ लोगों को जागरूक करने के लिए भी कई कदम उठा रहा है। सरकार की ओर से लगाई पूर्ण बंदी के कारण प्रदेश के उधमपुर जिले में जहां बाजारों में सन्नाटा है, वहीं लोग तेज रफ्तार जिंदगी से थोड़ा थम कर अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए नजर आए।

जम्मू कश्मीर

हालांकि, जिले में अबतक कोरोना विषाणु का कोई मामला नहीं मिला है लेकिन उपायुक्त डॉ. पीयूष सिंगला ने एहतियातन जिले में 22 मार्च से पूर्ण बंदी लगा दी थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए यह जरूरी है पर इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है।

स्थानीय निवासी शमी खान की बेटी शहनाज की शादी अगले महीने 20 तारीख को तय है। बकौल शमी खान, यह उनके घर की पहली शादी है। लिहाजा वे इसे बड़े जोश-ओ खरोश से करना चाहते थे। लेकिन शादी की तैयारियां शुरू करने से पहले ही बाजार बंद हो गए।

बंदी में कर्फ्यू जैसे हालात, सभी शहरों में सन्नाटा

राजीव जैन
जयपुर।

देश में सबसे पहले कोरोना वायरस को लेकर पूर्ण बंदा का एलान करने वाले राजस्थान में इसके पहले दिन सोमवार को दोपहर तक मिले-जुले हालात रहे। प्रदेश के बड़े शहरों में लोगों की आवाजाही बढ़ती देख प्रशासन ने दोपहर बाद सख्ती बरती तो हालात कर्फ्यू जैसे हो गए और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार रात को एक उच्च स्तरीय बैठक में ही सोमवार से प्रदेश में 31 मार्च तक पूर्ण बंदी करने का एलान कर दिया। प्रदेश में कोरोना के अब तक 29 मरीज सामने आए हैं। इसके कारण आने वाले दिनों में हालात और खराब नहीं हो इस मकसद से सरकार ने ऐसा सख्त कदम उठाया है। इ

जयपुर में सोमवार को सवेरे छह बजे से लाक डाउन शुरू होने के बाद लोगों की चहल कदमी पर रोक लग गई। इसके बावजूद बडी संख्या में लोगों के अपने निजी वाहनों में घूमने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस ने सती दिखानी शुरू की। इसके कारण पुलिस ने गैरजरूरी तौर पर सड़कों पर निकलने वाले वाहन चालकों के वाहनों को जब्त करना शुरू कर दिया।

जयपुर के कलेक्टर जोगा राम ने बताया कि कोरोना विषाणु के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए ही सरकार ने लाक डाउन किया है और एक साथ पांच लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाई गई। जयपुर जिले में अन्य करबों के अस्पतालों में 10 हजार से ज्यादा बिस्तर तैयार किए जा रहे हैं।

राजस्थान

प्रदेश के भीलवाड़ा और झुंझनूं में तो कोरोना के ज्यादा मरीज मिलने के बाद इन शहरों में तो तीन दिन से ही कर्फ्यू चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि राजस्थान सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने भी राजस्थान के प्रयासों की सराहना की है। लाक डाउन के लिए सबसे पहले घोषणा करने पर तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह को सरकार की सराहना की जानकारी भी दी।

रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा में तीन डॉक्टरों समेत 13 चिकित्साकर्मी पाजिटिव हैं। इन डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के संपर्क में हजारों लोग आए थे। इसके कारण कर्फ्यू लगा कर सभी घरों की स्क्रीनिंग की गई है।

भीलवाड़ा में करीब 500 लोगों को पृथक रखा गया है। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह का कहना है कि प्रदेश को चरण 3 में जाने से बचाने के लिए ही तमाम उपाय किए जा रहे हैं। राजस्थान व्यापार महासंघ के सुरेश सैनी का कहना है कि कोरोना वायरस के लिए सरकार के उठाए गए सभी कदमों के साथ हैं।

महासंघ ने तमाम तरह के कारोबार बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंदों के लिए भोजन सामग्री की भी व्यवस्था की जा रही है। फुटपाथ पर जीवन बसर करने वालों को खाद्य सामग्री पुलिस के सहयोग से वितरीत की जा रही है। इसके साथ महासंघ से जुड़े सदस्यों से अपील की गई है कि लाक डाउन के दौरान घरों पर ही रहे और आम जनता को भी कुछ दिनों के लिए घरों पर रहने के लिए प्रेरित करें।

कोई दिनभर देखता रहा टीवी तो किसी ने खेला शतरंज

सुमन भटनागर
अंबाला।

कामकाजी व्यक्ति के लिए एक घंटा भी खाली बैठना मुश्किल हो जाता है लेकिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का असर यह रहा कि 14 घंटे तक लोग घरों में दुबके बैठे रहे। सोमवार को भी जिला प्रशासन ने हालांकि, अपने स्तर पर कोरोना पूर्णबंदी की घोषणा कर दी थी लेकिन आज सुबह कुछ बाजारों में दुकानें खुली थीं जिन्हें बाद में पुलिस ने पहुंचकर उन्हें बंद करवाया। शहर के बड़े बाजारों यानी सर्राफा बाजार, थोक कपड़ा बाजार, अनाज मंडी, पूजा काम्प्लेक्स, जग्गी सिटी सेंटर तो 26 मार्च तक पहले ही बंद रखने का फैसला कर चुके हैं, जबकि दवा और किराना आदि की दुकानों को खुला रखने की अनुमति दी गई है।

जो भी हो, बीते रविवार को किसी ने घर में परिजनों के साथ बैठकर अरदास की तो किसी का अधिकतर समय टीवी देखने में ही गुजरा। कोई दिनभर गपशप करता रहा तो कोई लजीज नाश्ते और स्वादिष्ट लंच का आनंद लेता रहा। कुछ लोगों ने दोस्तों-रिश्तेदारों के साथ मोबाइल फोन पर लंबी-लंबी बातें कर उनका गिला शिकवा दूर किया तो कुछ कामकाजी महिलाओं ने आज घरों में साफ सफाई का अभियान चलाया। जिला अधिकारी पूरा दिन जनता कर्फ्यू को कामयाब करने में जूझते रहे तो उपायुक्त अशोक शर्मा का दिनभर बैठकों का दौर चलता रहा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए 50 हजार लीटर कोरोना विषाणु रोधी रसायन खरीदा गया है जिसका छिड़काव शहरों व गांवों में किया जाना है। उन्होंने बताया कि जो भी बड़ा व्यावसायिक संस्थान अपने परिसर में कीटाणु मुक्त कराना चाहे तो उसे प्रशासन छिड़काव के लिए मुफ्त दवा उपलब्ध कराएगा।

हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रविवार पूरा दिन घर में ही परिवार के बीच रहे। वे आमतौर पर हर रोज शाम तक जनता के बीच घिरे रहते हैं लेकिन कई वर्षों बाद यह पहला मौका है जब वह पूरा दिन घर पर ही रहे। उन्होंने अपना अधिक समय अपनी नन्हीं नातिन को ही दिया जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। विज का कहना है, पूरी ताकत से हम कोरोना से लड़ेंगे और उसे भगाकर ही दम लेंगे।' उन्होंने कहा कि वैसे भी हरियाणावासी योद्धाओं सा दमखम रखते हैं, उनका कोरोना क्या बिगाड़ेगा।

अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल ने भी रविवार का दिन घर में ही गुजारा। उन्होंने सुबह पूरी दुनिया से कोरोना की समाप्ति के लिए पूजा-अर्चना की और फिर अपनी माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पहले कुछ देर उन्होंने अखबार भी पढ़ा और फिर कुछ धार्मिक किताबें भी। काफी दिनों बाद यह पहला मौका था जब उन्होंने आधे से अधिक समय इकलौती बेटी अंशिका गोयल को दिया।

अंबाला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित जैन ने भी अधिक समय परिवार के लोगों से साथ गपशप में गुजारा। उनकी माता भी हाईकोर्ट में वकील हैं, इसलिए बहुत कम बार ऐसा मौका मिलता है कि जब घर में सभी परिजन एक साथ कई घंटे बैठ पाएं। उनका कहना है कि लोग सोशल मीडिया पर कोरोना की रोकथाम के लिए झोलाछाप व स्वयंभू डाक्टरों की राय पर भरोसा करने की बजाए योग्य डॉक्टरों के सुझाव पर ही अमल करें।

हरियाणा

हरियाणा अकाली दल के प्रवक्ता संत सिंह कंधारी (80) के दिन की शुरुआत श्रीसुखमनी साहिब के पाठ से हुई और फिर परिजनों ने मिलकर कोरोना के जल्द खात्मे के लिए अरदास की। उनका कहना है कि अपने जीवन में उन्होंने कभी ऐसा पूर्ण बंद नहीं देखा। राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हैं, तब कहीं दोपहर तक 40-50 फीसद ही बंद हो पाता है लेकिन मोदी की एक आवाज पर सभी लोग घर में डटे रहे।

पीकेआर जैन कालेज ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य मुदिता भटनागर ने पूरा दिन घर के काम में गुजारा। उन्होंने घर पर ही पूजा-अर्चना कर देश के स्वास्थ्य की कामना की। यहां के एक पब्लिक स्कूल की अध्यापिका पारखी मेहरा ने पूरा दिन अपने घर के सफाई और उसकी सफाई में गुजारा। उनका मानना है कि डाक्टरी परामर्श से ही कोरोना का प्रसार रोका जा सकता है। भारतीय लोगों की क्षमता अधिक है, वे इस विश्वव्यापी महामारी से निपट लेंगे। महिला वकील मनीषा ने अधिक समय कंप्यूटर पर और अपनी बेटी को पढ़ाने पर लगाया और दोपहर बाद परिजनों के साथ टीवी पर खबरें आदि देखीं। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के अध्यक्ष अशोक मेहता का पूरा दिन घर में ही गुजरा। उन्होंने कहा कि करोना एक बहुत बड़ी आपदा है जिसका मुकाबला मिलजुल कर संभव है।

कोरोना से लड़ाई में सरकार प्रतिबद्ध : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 मार्च।

जनता में संघर्ष की भावना को बनाए रखने को जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना विषाणु के खिलाफ लड़ाई में निराशावाद, नकारात्मकता और अफवाहों से निपटना महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोगों को भरोसा दिलाए जाने की जरूरत है कि सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।

मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के प्रिंट मीडिया के बीस से अधिक पत्रकारों और हितधारकों के साथ बातचीत में मीडिया से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय- दोनों स्तरों पर सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करने और निरंतर फीडबैक उपलब्ध कराने को कहा।

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, मोदी ने सामाजिक दूरी के महत्त्व पर बल देते हुए मीडिया से इस बारे में जागरुकता फैलाने, राज्यों द्वारा लिए गए लॉक डाउन के फैसले से जनता को अवगत कराने और साथ ही अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के समावेशन, अखबारों में अन्य देशों की केस स्टडीज के माध्यम से विषाणु के प्रसार के प्रभाव को रेखांकित करने को कहा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि समाचार पत्र जबर्दस्त विश्वसनीयता रखते हैं और किसी क्षेत्र का स्थानीय पृष्ठ लोग विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इस पृष्ठ में प्रकाशित लेखों के माध्यम से कोरोना विषाणु के बारे में जागरुकता फैलाई जाए। मोदी ने कहा, 'यह जरूरी है कि लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए कि परीक्षण केंद्र कहां हैं, परीक्षण कराने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए और घर में आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन कैसे करना चाहिए।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जानकारी समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों में साझा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता के स्थान जैसी जानकारी भी क्षेत्रीय पृष्ठों में साझा की जा सकती है।

रेलवे की निर्माण इकाइयों में बनेंगे अस्पताल के सामान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 मार्च।

रेलवे बोर्ड ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए अपनी सभी निर्माण इकाइयों को निर्देश जारी कर अस्पताल के सामान्य बेड, मेडिकल ट्रॉली और पृथक सुविधाएं व आइवी स्टैंड जैसे सामान के निर्माण की संभावना का पता लगाने को कहा है।

चित्तरंजन स्थित लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू), इंटिग्रल कोच फैक्टरी (चेन्नई), रेल कोच फैक्टरी (कपूरथला), डीजल लोको वर्क्स (वाराणसी) और रेल पहिया कारखाना (येलेहंका) में निर्माण इकाइयों के सभी महाप्रबंधकों को आदेश जारी कर जरूरी सामान के निर्माण के लिए कहा है, जिसका इस्तेमाल इस महामारी के प्रभावित लोगों के उपचार के लिए किया जा सके।

आदेश में कहा गया, 'रेलवे बोर्ड ने इन निर्माण इकाइयों के महाप्रबंधकों को जरूरी निर्देश जारी कर अस्पताल के बेड (बिना गद्दे का), मेडिकल टॉली और पृथक सुविधाएं, आइवी स्टैंड, स्ट्रैचर, अस्पताल फुटस्टेप, बेडसाइड लॉकर, स्टैंड के साथ वॉश बेसिन, वेंटिलेटर, मास्क, सेनेटाइजर, वाटर टैंक जैसे सामान के निर्माण की संभावना का पता लगाने को कहा है।'

आदेश में कहा गया, 'रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधकों को जोन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ परामर्श कर इसकी संभावना का पता लगाने और बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन के लिए कहा है।'

दूसरी ओर, रेलवे ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से सभी यात्री सेवाओं को निलंबित करने के लिए बाध्य होने के बावजूद वह देश में जरूरी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है।

रेलवे ने बताया कि 23 मार्च को अनाज, नमक, खाद्य तेल, चीनी, दूध, फल और सब्जियों, प्याज, कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों के 474 रैक तैयार किए गए।

कुल 891 रैक तैयार किए गए, जिनमें अन्य आयातित सामग्री जैसे लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, खाद और अन्य सामग्री शामिल हैं।

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रेलवे ने देश भर में यात्री ट्रेन सेवाओं का संचालन 31 मार्च तक बंद कर दिया है। मंत्रालय ने कहा, 'रेलवे फिलहाल देश भर में सिर्फ माल गाड़ियों का संचालन कर रहा है। रेलवे कोशिश कर रहा है कि जरूरी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। विभिन्न राज्यों में बंद की स्थिति के दौरान विभिन्न माल गोदामों, नियंत्रण कार्यालयों में तैनात रेलवे कर्मचारी हफ्ते में सातों दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं, ताकि देश में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बनी रहे।'

कोरोना के भय से राज्यसभा चुनाव स्थगित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 मार्च।

निर्वाचन आयोग ने अप्रैल में राज्यसभा की रिक्त हो रही 55 सीटों पर होने वाले चुनाव को कोरोना विषाणु के संक्रमण से उपजे संकट को देखते हुए स्थगित कर दिया है। आयोग द्वारा मंगलवार को जारी बयान में इस आशय के फैसले की जानकारी देते हुए बताया गया है कि जल्द ही चुनाव की नई तारीख की घोषणा की जाएगी। 25 फरवरी को आयोग द्वारा 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव कराने की घोषणा की गई थी।

आयोग ने बताया कि पूर्व निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के तहत 18 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि के बाद दस राज्यों की 37 सीटों के लिए एक-एक उम्मीदवार के नामांकन दर्ज होने के कारण इन सीटों पर बिना चुनाव कराए उक्त उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। शेष 18 सीटों के लिए 26 मार्च को मतदान होना था। आयोग ने बताया कि कोरोना विषाणु के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11 मार्च को वैश्विक महामारी की स्थिति घोषित किए जाने के बाद भारत सरकार ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय सहित अन्य संबद्ध मंत्रालयों के माध्यम से इस विषाणु के संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि यातायात सहित अन्य सेवाओं पर अस्थायी रोक को देखते हुए राज्यसभा की सीटों पर होने वाले द्विवार्षिक चुनाव को स्थगित करने का फैसला किया गया है। आयोग जल्द ही चुनाव की नई तारीख की घोषणा करेगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान की 18 सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होना था।

राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय बंद :

कोरोना विषाणु के खतरे के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और किसी को भी कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्यसभा सचिवालय को शुक्रवार तक बंद किया गया है जबकि लोकसभा सचिवालय 31 मार्च तक बंद रहेगा। सूत्रों ने बताया कि कोरोना विषाणु के खतरे के कारण राज्यसभा सचिवालय को शुक्रवार तक बंद कर दिया गया है और इस अवधि में किसी को भी कार्यालय आने की अनुमति नहीं होगी। राज्यसभा में अधिकारियों सहित कर्मचारियों की संख्या 1400 से अधिक है।

बहरहाल, लोकसभा सचिवालय से जारी एक संवाद में कहा गया है कि कार्यालय 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगा लेकिन जरूरी काम होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए जा सकते हैं। लोकसभा महासचिव के आदेश में कहा गया है कि यह सूचित किया जाता है कि लोकसभा सचिवालय तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगा। हालांकि अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव जरूरत पड़ने पर अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय आने का निर्देश दे सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा को वित्त विधेयक पारित करने के बाद सोमवार को निर्धारित समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

देश में रेल सेवाएं अब 14 अप्रैल तक बंद

पेज 1 का बाकी

हैं। इस बीच, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) ने लोगों से कहा है कि वे ट्रेनों की ऑनलाइन बुक की गई टिकटों को रद्द न करें और उन्हें खुद ही पूरा पैसा मिल जाएगा।

भारत में कोरोना विषाणु के संक्रमण की स्थिति गंभीर होने के साथ ही पूरे देश में पूर्ण बंदी लागू कर दी गई है। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रभाव से कर्फ्यू लगाने को कहा है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि देश के अनेक हिस्सों में लोग पूर्ण बंदी का उल्लंघन कर रहे हैं। इस कारण प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराया जाए। हालात पर 24 घंटे नजर रखी जाए। कैबिनेट सचिव ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी फोन पर इस बारे में बातचीत की।

महामारी से निपटने के लिए 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 31 मार्च तक पूर्ण बंदी की घोषणा की गई है। इसके बावजूद लोगों के बाहर घूमने की खबरें सामने आई हैं। इस कारण मंगलवार को राज्यों को निर्देश जारी किए गए। कैबिनेट सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि विषाणु संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आगामी दिन और सप्ताह अत्यंत महत्त्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इस कारण सख्ती जरूरी है।

32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 560 जिलों में अब पूर्ण बंदी है। मंगलवार को बचे तीन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने यहां के कुछ इलाकों में बंद लागू किया, जिसके दायरे में 58 जिले हैं। दो राज्य पंजाब और महाराष्ट्र व एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पहले ही अपने इलाके में कर्फ्यू की घोषणा कर चुके हैं।

विषाणु संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ पूरे देश में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई और सड़क, रेल व हवाई यातायात को अभूतपूर्व कदमों के तहत बंद कर दिया गया है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को सलाह दी गई है कि जहां जरूरी हो, वे कर्फ्यू लगाएं क्योंकि विषाणु के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लॉकडाउन का आदेश दिए जाने के बावजूद लोग लगातार घरों से बाहर घूम रहे हैं।

दो राज्य-पंजाब और महाराष्ट्र व एक केंद्रशासित प्रदेश-पुडुचेरी ने पहले ही अपने यहां कर्फ्यू लगा दिया है। उत्तर प्रदेश ने मंगलवार को पूरे राज्य में पूर्ण बंदी करने का ऐलान किया।

केरल में पूर्ण बंदी किए जाने के बाद बसें सड़कों से नदारद रहीं, जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहीं। कुछ जगहों पर लोग पूर्ण बंदी का उल्लंघन करते दिखे, जिस पर पुलिस को दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ा।

दिल्ली में दूसरी मौत, देश में संक्रमित लोगों की संख्या 500 पार

पेज 1 का बाकी

मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार पौने छह बजे तक 470 लोगों का इलाज चल रहा था। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक-एक मौत हुई, जबकि पूर्व में हुई सात मौत- महाराष्ट्र में दो, बिहार, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात और पंजाब में एक-एक मौत हुई थी। मंगलवार तक 39 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके थे। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना विषाणु संक्रमण के सबसे ज्यादा 95 मामले केरल से सामने आए हैं, जिनमें आठ विदेशी नागरिक शामिल हैं। इसके बाद महाराष्ट्र से तीन विदेशी नागरिकों समेत 89 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना विषाणु के 37 मरीज हैं, जबकि राजस्थान में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इनमें दो विदेशी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में एक विदेशी नागरिक समेत 32 लोग संक्रमित हैं। तेलंगाना में 10 विदेशियों समेत अब तक 35 मामले सामने आए हैं। वहीं, दिल्ली में संक्रमण के मामले 30 हैं, जिनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है, जबकि गुजरात में 33 मामले सामने आए हैं, जिनमें एक विदेशी शामिल है।

हरियाणा में 14 विदेशी नागरिकों समेत 28 मामले हैं, जबकि पंजाब से 29 मामले सामने आए हैं। लद्दाख में 13, जबकि तमिलनाडु में दो विदेशी नागरिकों समेत 15 मामले हैं। पश्चिम बंगाल में नौ, जबकि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में सात-सात मामले सामने आए हैं। जम्मू-कश्मीर में चार संक्रमित लोगों की पहचान हुई है। उत्तराखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश में तीन-तीन मामले, जबकि ओड़ीशा में दो लोग संक्रमण की चपेट में हैं। छत्तीसगढ़, पुडुचेरी और मणिपुर से एक-एक मामला सामने आया है।

मोदी ने खींची लक्ष्मण रेखा

पेज 1 का बाकी

में हैं कि सामाजिक दूरी बनाना केवल बीमार लोगों के लिए आवश्यक है। ये सोचना सही नहीं। लोगों से सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील करते हुए मोदी ने कहा, 'आने वाले तीन सप्ताह, यानी 21 दिन हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो कोरोना विषाणु के संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है।' उन्होंने लोगों से अपील की कि चाहे जो हो जाए, घर में रहें और एक ही काम करें कि अपने घर में रहें। यह धैर्य और अनुशासन का समय है और जब तक देश में पूर्ण बंदी की स्थिति है, हमें अपना संकल्प और वचन निभाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक दूरी हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है। उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच, आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देगी।' मोदी ने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का जो संकल्प हमने लिया था, एक राष्ट्र के नाते उसकी सिद्धि के लिए हर भारतवासी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ,पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया। बच्चे-बुजुर्ग, छोटे-बड़े, गरीब-मध्यम वर्ग-उच्च वर्ग, हर कोई परीक्षा की इस घड़ी में साथ आया।

भारत के पास संक्रमण पर काबू पाने की क्षमता : डब्लूएचओ

पेज 1 का बाकी

मात दी और दुनिया को इस तरह एक बड़ा उपहार दिया। भारत ने पोलियो को भी जड़ से उखाड़ फेंका।' रेयान ने कहा, 'यह खास तौर पर महत्त्वपूर्ण है कि भारत जैसे देश अपने अनुभव के आधार पर दुनिया को बताएं कि क्या किया जा सकता है।' रेयान ने कहा, 'भारत ने दो 'साइलेंट किलर' चेचक और पोलियो का उन्मूलन करने में दुनिया की अगुआई की, इसलिए उसमें जबर्दस्त क्षमता है।' उन्होंने कहा, 'इसका आसान जवाब नहीं है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि भारत जैसे देश दुनिया को रास्ता दिखाएं, जैसा उन्होंने पहले भी किया है।' कई लोगों की जान लेने वाली बीमारियों यथा पोलियो और चेचक से भारत ने लक्षित सार्वजनिक हस्तक्षेप के जरिये पार पा लिया गया। भारत ने चेचक से जहां 1977 में छुटकारा पा लिया था, वहीं 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश का दर्जा मिला।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेडरोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि चीन में इसके पता लगने के बाद प्रभावितों की संख्या एक लाख पहुंचने में 67 दिन लगे थे।

शिवराज चौहान सरकार ने विश्वास मत हासिल किया

पेज 1 का बाकी

अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति व उपाध्यक्ष हिना कांवरे द्वारा इस्तीफा देने के कारण भाजपा के वरिष्ठ विधायक जगदीश देवड़ा ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने दावा किया कि सदन में कुल 112 सदस्यों ने ध्वनिमत से चौहान का समर्थन किया। इनमें भाजपा के सदस्यों के अलावा बसपा, सपा व निर्दलीय विधायक शामिल थे। उन्होंने इसके बाद सदन की कार्यवाही को 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 27 मार्च को लेखानुदान पेश किया जाएगा।

विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद बसपा के दो, सपा के एक और दो निर्दलीय विधायकों सुरेंद्र सिंह शेरा (बुरहानपुर) और विक्रम सिंह राणा (सुसनेर) ने प्रदेश में नई भाजपा सरकार के विश्वास मत का समर्थन किया। प्रदेश विधानसभा में चार निर्दलीय विधायक हैं। इनमें से मंगलवार को दो निर्दलीय विधायक सदन में उपस्थित नहीं थे।

विश्वास मत हासिल करने के बाद चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने जो किया, वह अलोकतांत्रिक है। उसके विधायक सदन में अनुपस्थित रहे। दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि इस विश्वास मत का कोई मतलब नहीं है। भाजपा सरकार को खाली पड़ी 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद विश्वास मत मांगना चाहिए था।

इससे पहले, सोमवार रात को 9 बजे राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस के 22 विधायकों के त्यागपत्र देने के कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार बहुमत से पीछे रह गई और मुख्यमंत्री कमलनाथ को पिछले हफ्ते इस्तीफा देना। प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में भाजपा के 107 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के 22 विधायकों के त्यागपत्र देने के बाद उसकी संख्या घटकर 92 पर आ गई है। वर्तमान में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं। इस समय की प्रभावी संख्या 206 है और वर्तमान में सदन में बहुमत का आंकड़ा 104 है।

अब कोरोना का अमेरिका पर धावा, चीन में काबू

पेज 1 का बाकी

चीनी मुख्यभूमि पर सोमवार तक कुल 81,171 लोग संक्रमित थे। इनमें बीमारी से मरने वाले 3,277 लोग, अभी भी इलाज करा रहे 4,735 मरीज और सेहत में सुधार होने के बाद अस्पताल से जाने दिए गए 73,159 मरीज शामिल हैं।

अमेरिका में ताजा आंकड़ें सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्त्वपूर्ण चिकित्सा सामान की आपूर्ति और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की जमाखोरी रोकने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी सरकार महत्वपूर्ण चिकित्सा और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की जमाखोरी और अत्यधिक मूल्य निर्धारण करने वालों पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, 'हम किसी को भी अमेरिकी नागरिकों की पीड़ा का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे।' उन्होंने चेतावनी दी कि न्याय विभाग दुनिया भर में 15,000 से अधिक लोगों की जान लेने वाली इस महामारी से संबंधित धोखाधड़ी की योजनाओं पर आक्रामक रूप से अभियोजन चलाएगा।

न्यूयॉर्क प्रांत, विशेष रूप से न्यूयॉर्क सिटी हाल के कुछ समय में अमेरिका में सबसे खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में से एक का केंद्र बन गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित हर दो अमेरिकियों में से लगभग एक न्यूयॉर्क शहर से है। न्यूयॉर्क के अभी तक 157 निवासियों की कोरोना वायरस से मृत्यु हो चुकी है। शहर में अब तक हुई कुल मौतों में से 43 मौतें सोमवार को हुई।

राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि न्यूयॉर्क के साथ ही वाशिंगटन प्रांत और कैलिफोर्निया जैसे अन्य कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र उनके प्रशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा, जरूरी चिकित्सा आपूर्ति और आपातकालीन उपकरणों को न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजंसी देश भर में 80 लाख एन -95 मास्क और 1.33 करोड़ सर्जिकल मास्क वितरित कर रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मौजूदा दवाओं के लिए नैदानिक परीक्षण न्यूयॉर्क में शुरू होंगे जो इस वायरस के खिलाफ प्रभावी साबित हो सकती हैं।

दूसरी ओर, चीन में चीन में बेजिंग और शंघाई की स्थानीय सरकारों ने विदेशों से आने वाले सभी लोगों का न्यूक्लिक एसिड परीक्षण कराने की घोषणा की है, ताकि उचित जांच हो सके। अधिकारियों ने प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है। विषाणु के प्रसार को रोकने के प्रयासों में समन्वय कर रही प्रधानमंत्री ली क्विंग के अध्यक्षता वाले सेंट्रल लीडिंग ग्रुप (सीएलपी) ने कहा कि वुहान समेत पूरे देश में विषाणु के प्रसार को नियंत्रित कर लिया गया है। चीन ने मंगलवार को घोषणा की कि वह घातक कोरोना वायरस के केंद्र बने ह्युवेई प्रांत में पांच करोड़ से ज्यादा आबादी पर लागू लॉकडाउन को बुधवार को खत्म करेगा। ह्युवेई की राजधानी वुहान में चल रहा लॉकडाउन आठ अप्रैल को खत्म होगा। इससे 1.1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले शहर में लोगों पर लगी पाबंदी खत्म हो जाएगी। ह्युवेई प्रांत और वुहान शहर की कुल 5.6 करोड़ की आबादी को 23 जनवरी से कड़े लॉकडाउन में रखा गया है। अखबार पीपुल्स डेली के मुताबिक एक सरकारी नोटिस में कहा गया है कि ह्युवेई प्रांत के अन्य हिस्से में रह रहे लोग बुधवार से 'ग्रीन हेल्थ कोड' के साथ यात्रा कर सकेंगे। वुहान के लोग आठ अप्रैल से शहर के बाहर यात्रा कर सकेंगे।

उमर अब्दुल्ला आठ महीने बाद हिरासत से रिहा

पेज 1 का बाकी

गया कि सरकार ने उमर की हिरासत तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी। उमर की रिहाई की खबर मिलने के बाद अस्थायी हिरासत केंद्र में सबसे पहले पहुंचने वालों में उनकी मां थी। उमर को उनके आधिकारिक आवास से थोड़ी दूर स्थित सरकारी अतिथि निवास हरि निवास में रखा गया था। उनके पिता को 221 दिन की हिरासत में रखने के बाद 13 मार्च को रिहा कर दिया गया था।

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नेकां नेता उमर को रिहा करने का स्वागत किया। जन सुरक्षा कानून के तहत इल्तिजा की मां महबूबा मुफ्ती अब भी हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी मां के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया- वे भले ही नारी शक्ति और महिला उद्धार की बात करते हों लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र को सबसे ज्यादा डर भी महिलाओं से ही लगता है। उनका इशारा अपनी मां की ओर था जो अब भी हिरासत में हैं।

जम्मू-कश्मीर में माकपा के वरिष्ठ नेता एमवाइ तारीगामी ने भी उमर की रिहाई का स्वागत किया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में 4-जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी संसाधन मुहैया करवाने की भी मांग की।

अगले साल गर्मियों तक के लिए स्थगित

पेज 1 का बाकी

बातचीत के बाद ओलंपिक को पहली बार शांतिकाल में भी स्थगित करने का ऐतिहासिक फैसला किया गया।

आबे ने इससे पहले कहा था कि जापान ने आइओसी से खेलों को एक साल के लिए स्थगित करने के लिये कहा जिस पर बाक ने शत प्रतिशत सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में इन दोनों ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की नवीनतम जानकारी के आधार पर तोक्यो खेलों का कार्यक्रम 2020 से आगे की तारीख में तय करना होगा लेकिन यह 2021 की गर्मियों से आगे नहीं होगा। ऐसा खिलाड़ियों, ओलंपिक खेलों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है।

बयान में कहा गया है, 'इन दोनों ने सहमति व्यक्त की कि तोक्यो में ओलंपिक खेल इस मुश्किल घड़ी में दुनिया के लिए आशा की किरण बन सकते हैं और दुनिया अभी खुद को जिस अंधेरे में पा रही है उसमें ओलंपिक मशाल प्रकाशपुंज का काम कर सकती है।'

इसके अनुसार, 'इसलिए इस पर सहमति बनी है कि ओलंपिक मशाल जापान में ही रहेगी। यह भी सहमति बनी है कि खेलों को पहले की तरह ओलंपिक और पैरालंपिक खेल तोक्यो 2020 के नाम से ही जाना जाएगा।

यह तोक्यो शहर के लिए बड़ा झटका है जिसकी ओलंपिक खेलों की तैयारियों के लिए अब तक काफी सराहना हुई है। खेलों के लिए स्टेडियम काफी पहले तैयार हो गए थे और बड़ी संख्या में टिकट भी बिक गए थे।

ओलंपिक को अब तक बहिष्कार, आतंकी हमले और विरोधों का सामना करना पड़ा है लेकिन 1948 के बाद इन्हें हर चार साल में आयोजित किया जाता रहा है। यह दुनिया भर में हजारों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस से प्रभावित सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता होगी। इस महामारी के कारण दुनिया भर की खेल प्रतियोगिताएं ठप्प पड़ी हुई हैं।

आइओसी पर 24 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों को स्थगित करने का दबाव लगातार बढ़ रहा था क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में एक अरब 70 करोड़ लोग घरों में बंद हैं। अधिकतर खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक की तैयारियां करना मुश्किल हो गया था क्योंकि इससे उनके बीमारी से संक्रमित होने का खतरा था। विभिन्न प्रतियोगिताएं और क्वालीफायर्स रद्द कर दी गई थीं और अंतरराष्ट्रीय यात्रा सीमित कर दी गई हैं।

रविवार को आइओसी ने पहले खेलों को स्थगित करने के प्रस्ताव पर फैसला करने के लिए खुद के लिए चार सप्ताह की समयसीमा तय की थी। लेकिन कनाडा और आस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने भी इन्हें स्थगित करने की मांग की जिसके बाद आइओसी पर दबाव बढ़ गया था।

तोक्यो ने खेलों की मेजबानी पर 12 अरब 60 करोड़ डॉलर खर्च किया है और इसके ताजा बजट को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि खेलों को स्थगित करने से छह अरब डॉलर का अतिरिक्त खर्चा होगा। यह प्रायोजकों और प्रमुख प्रसारकों के लिए भी करारा झटका है जो कि विज्ञापन से होने वाले राजस्व के लिए हर चार साल में होने वाले खेल महाकुंभ का इंतजार करते हैं।

यह पहला अवसर नहीं है जबकि तोक्यो खेलों के कार्यक्रम में बदलाव देख रहा है। इससे पहले उसे 1940 में भी मेजबानी मिली थी लेकिन चीन के साथ जापान के युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय दबाव में उसे इससे हटना पड़ा था। यूरोपीय फुटबाल चैंपियनशिप और कई अन्य प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने के बाद आइओसी को फैसला करने में देरी के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन तोक्यो के आयोजकों ने खेलों को बदले कार्यक्रम में आयोजित करने की जटिलताओं की तरफ भी इशारा किया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि स्टेडियम उपलब्ध होंगे या नहीं। इसके अलावा होटल के हजारों कमरों की बुकिंग को रद्द करना होगा। आइओसी के पूर्व विपणन प्रमुख माइकल पायने ने कहा, 'दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए सात साल की तैयारी के बाद अचानक बदलाव करना आसान नहीं है।

आयकर और जीएसटी रिटर्न भरने का समय बढ़ाया गया

पेज 1 का बाकी

तिथि को भी 31 मार्च से आगे बढ़ाकर जून 2020 के अंतिम सप्ताह तक कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों द्वारा कर्ज की किस्त नहीं लौटाए जाने और उसे चूककर्ता घोषित किए जाने की सीमा को मौजूदा एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया गया है। यदि मौजूदा स्थिति 30 अप्रैल 2020 के बाद भी जारी रहती है तो सरकार दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून (आइबीसी) 2016 की धारा सात, नौ और 10 को छह माह के लिए निलंबित भी कर सकती है, ताकि बड़ी संख्या में कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया के तहत जाने से रोका जा सके। सीतारमण ने कहा कि व्यापार वित्त उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल ट्रेड लेनदेन पर लगने वाले बैंक शुल्कों को भी कम कर दिया गया है। इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कंपनियों के मामले में निदेशक मंडल की बैठक करने के अनिवार्य नियम में 60 दिन के लिए राहत दी गई है। इसके साथ ही रोक की अवधि के दौरान विलंब से फाइलिंग करने पर शुल्क को भी हटा लिया गया है।

सरकार आर्थिक राहत पैकेज भी काम कर रही है और इसकी घोषणा भी जल्द की जायेगी। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आर्थिक कार्य बल की घोषणा की है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के उप- समूहों को मिलाकर कई स्तरों वाला यह कार्यबल पहले से ही काम कर रहा है। कार्य बल के उपसमूहों से मिले सुझावों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि कर विवाद निपटान योजना 'विवाद से विश्वास' की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसके साथ ही पांच करोड़ रुपए से कम कारोबार करने वाली औद्योगिकी इकाइयों के लिए मार्च से मई के तीन महीने के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा भी बिना किसी विलंब शुल्क, जुर्माने और बयाज के जून के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दी गई है। इससे छोटे और मझौले उद्यमों को काफी राहत मिलेगी। पांच करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियां भी मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न जून के आखरी सप्ताह तक भर सकती हैं, लेकिन उन्हें तय तिथि के 15 दिन के बाद नौ फीसद की घटी दर से ब्याज चुकाना होगा। अग्रिम कर, स्वः आकलन कर, नियमित कर, टीडीएस, टीसीएस और एसटीटी का देरी से भुगतान करने पर 30 जून तक 12 अथवा 18 प्रतिशत के स्थान पर नौ फीसद की घटी दर से ब्याज लिया जाएगा।

www.readwhere.com

पाक में बंदी बंदी के कारण रावलपिंडी में मंगलवार को सड़कों पर चलते इक्का-दुक्का वाहन।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने नकदी का खजाना खोला

वाशिंगटन, 24 मार्च (एपी)।

फेडरल रिजर्व ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाने के लिए बैंकों को असीमित मात्रा में नकद धन उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक अधिक से अधिक बांड की खरीद करेगा और इस संकट से पार पाने में मदद के लिए छोटी एवं बड़ी कंपनियों तथा स्थानीय सरकारों को कर्ज देना शुरू करेगा।

फेडरल रिजर्व की सोमवार की घोषणा में बांड खरीद की कोई सीमा तय नहीं की गई है। इस पहल का मकसद अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रवाह को बनाए रखना है जो कारोनो महामारी के कारण संकट में है। केंद्रीय बैंक का यह कदम 2008 में आर्थिक संकट के दौरान किए गए उपायों से भी व्यापक है। फेडरल रिजर्व ने एक बयान में कहा, कोरोना महामारी से अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में संकट गहरा गया है।

इसमें कहा गया है, हमारे देश की प्राथमिकता उन क्षेत्रों की मदद करना है जो इससे प्रभावित हैं तथा विषाणु को फैलने से रोकना है। अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, यह साफ है कि अर्थव्यवस्था के समक्ष गंभीर बाधाएं आएंगी। सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में आक्रामक कदम उठाने की जरूरत होगी ताकि नौकरी से निकाले जाने और आय में कमी को रोका जा सके तथा संकट टलने पर तेजी से चीजों को पटरी पर लाई जा सके।

दुनिया के बाजारों का हौसला बढ़ा

फेडरल रिजर्व की इस घोषणा का वित्तीय बाजारों पर अच्छा प्रभाव पड़ा।

डो जोंस सोमवार देर शाम बाजार खुलने के बाद करीब 500 अंक चढ़ा। हालांकि उसके बाद इसमें गिरावट आई।

फेडरल रिजर्व की घोषणा के अनुसार वह तीन नई कर्ज सुविधाएं स्थापित करेगा। इसके जरिये कॉरपोरेट बांड, नगर निगम बांड और वाहन तथा रीयल एस्टेट कर्ज से जुड़ी प्रतिभूतियां खरीद कर 300 अरब डॉलर उपलब्ध कराए जाएंगे।

साथ ही वह ब्याज को थामे रखने के लिए असीमित राशि के ट्रेजरी बांड और गिरवी रखी प्रतिभूतियों को खरीदेगा।

परीक्षण के दौरान गलतियों के कारण अमेरिका में आईं मुश्किलें

वाशिंगटन, 24 मार्च (एपी)।

एसोसिएट प्रेस की समीक्षा में पाया गया कि देश की शीर्ष स्वास्थ्य एजंसी में एक के बाद एक कई गलत कदमों की वजह से कोरोना वायरस के विश्वसनीय प्रयोगशाला परीक्षणों की कमी आई जिससे समूचे अमेरिका में इस महामारी के प्रसार को रोकने के संघीय प्रयासों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने के शुरू में अमेरिकी लोगों को आश्वस्त किया था कि रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) द्वारा विकसित कोविड-19 टेस्ट बिल्कुल सही है और कोई भी जो जांच करना चाहता है करा सकता है। हकीकत यह है कि अमेरिका में इस बीमारी का पहला मामला सामने आने के दो महीने से ज्यादा बीतने के बाद भी कई लोगों की जांच अब भी नहीं हो सकी है।

फरवरी के महीने में जब कोरोना ने अमेरिकी जनसंख्या में जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं तब सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी प्रयोगशालाओं ने कोविड-19 के 352 परीक्षण ही किए थे- यानी औसतन रोजाना 12 परीक्षण।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एधोनोम घेब्रेयेसस ने हाल में कहा था, आप आंख पर पट्टी बांध कर आग बुझाने का काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, अगर हमें यह नहीं पता कि इस बीमारी से कौन संक्रमित है तो हम इस महामारी को नहीं रोक सकते। स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के तहत ही सीडीसी आता है और अब विभाग ने अपनी गलतियों के आकलन के लिए आंतरिक समीक्षा शुरू कर दी है।

बाहरी पर्यवेक्षकों और संघीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने हालांकि चार प्राथमिक मुद्दे बताएं हैं जिन्होंने मिल कर राष्ट्रीय प्रक्रिया को बाधित किया- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनाए गए परीक्षण को स्वीकार नहीं करना, सीडीसी द्वारा विकसित और जटिल टेस्ट की कमियां, किसका परीक्षण किया जा सकता है इसे सीमित करने वाले सरकारी दिशानिर्देश और जांच की सुविधा को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को इसमें जोड़ने में हुई देरी।

हॉवर्ड के ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. आशीष के झा ने एपी को बताया, कई मौके थे, जिनकी वजह से आज की स्थिति से बच सकते थे।

उन्होंने कहा, असल में उन्होंने इसे सामान्य तौर पर लिया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाइट हाउस से संदेश था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह फ्लू से बुरा नहीं है। इस संदेश ने वास्तव में एफडीए और सीडीसी के अंदर ऐसा माहौल बनाया कि इसके इलाज में अत्यावश्यक जैसी कोई चीज नहीं है।

निजी प्रयोगशालाओं को भी दो हफ्ते पहले ही सरकारी नियामकों से मंजूरी मिली है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि देश में अब भी जांच की पर्याप्त क्षमता नहीं है जिससे इस बेहद संक्रामक विषाणु से आगे निपटा जा सके।

कोरोना को रोकने के लिए ब्रिटेन में तीन हफ्ते का बंद

लंदन, 24 मार्च (भाषा)।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों की आवाजाही पर कम से कम तीन हफ्ते के लिए सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। वायरस के चलते देश में मृतकों की संख्या 335 पर पहुंच गई है।

सोमवार शाम को टेलीविजन पर प्रसारित देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने लोगों पर इस तरह का दबाव नहीं बनाना चाहता लेकिन हालात इस तरह के हैं कि उन्हें लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और दो से अधिक लोगों के जुटने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ा है।

लोगों को अपने घर से केवल बहुत जरूरी सामानों के लिए बाहर निकलने का संदेश देते हुए जॉनसन ने कहा, आज शाम से मैं ब्रिटेन के लोगों को बहुत साधारण निर्देश दे रहा हूं - आप घर पर ही रहें।

लोगों को केवल जरूरी सामान खरीदने, किसी चिकित्सीय जरूरत, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की देखभाल या मदद के लिए और काम के सिलसिले में आने-जाने की इजाजत होगी लेकिन उसी सूरत में जब काम घर से नहीं हो सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा, आपको दोस्तों से मुलाकात नहीं करनी है। अगर आपके दोस्त आपको मिलने के लिए बुलाते हैं तो आपको न कहना होगा। जो परिवार के सदस्य आपके घर में नहीं रहते हैं उनसे आपको मुलाकात नहीं करनी है।

न्यूयॉर्क की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा जाएगी : क्योमो

न्यूयार्क, 24 मार्च (भाषा)।

न्यूयार्क के गवर्नर एंड्रयू क्योमो ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस मामलों की सुनामी के कारण अगले दो से तीन सप्ताह में राज्य की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली चरमरा जाएगी। अमेरिका में कोविड-19 के सर्वाधिक मामले न्यूयॉर्क से सामने आए हैं जहां इस संक्रमण के कारण 157 लोगों की मौत हो चुकी है। क्योमो ने कहा, न्यूयार्क शहर में हर ढाई दिन में संक्रमण के मामलों की संख्या दोगुनी होती जा रही है जो सकते में डालने वाला आंकड़ा है। हमें तेजी से बढ़ते उस वक्राकार ग्राफ को समतल करना होगा, यह वक्र लहर की तरह नहीं बल्कि सुनामी की तरह है।

अफ्रीकी जैज स्टार दिबांगो की कोरोना से मौत

पेरिस, 24 मार्च। वयोवृद्ध अफ्रीकी जैज कलाकार मनु दिबांगों की मंगलवार को कोरोना के संक्रमण से मौत हो गई। वह पहले विश्व प्रसिद्ध सितारे हैं जिनकी मौत कोरोना से हुई है। उनके संगीत प्रकाशक थियेरी दुरुपियरे ने बताया कि अफ्रीकी देश कैमरून निवासी 86 वर्षीय दिबांगों ने मंगलवार को पेरिस के अस्पताल में आखिरी सांस ली। वर्ष 1972 में आई 'सोल मकोस्सा' उनके बेहतरीन गीतों में से एक है। दिबांगो के फेसबुक पेज पर जारी संदेश के जरिये उनकी कोरोना वायरस से मौत होने की पुष्टि की गई। **(एएफपी)**

फार्म NO.URC • 2

भाग I of अध्याय XXI के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन [कंपनियों की धारा 374 (ख) के तहत अधिनियम, 2013 और कंपनियों के नियम 4 (1) (प्राधिकृत करने के लिए पंजीकृत) नियम, 2014] इसके द्वारा नोटिस दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) की अनुपस्थिति पंद्रह दिनों के बाद यहां एक आवेदन प्रस्तावित किया जाता है, लेकिन इसके बाद तीस दिनों की समाप्ति से पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा कि **मैसर्स वास्ट फ्रेश डिलाइट्स**, एक साझेदारी फर्म, कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकृत हो सकती है, जैसा कि मैसर्स वास्ट फ्रेश डिलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, (निगमन के तहत) एक कंपनी है जो शेयरों द्वारा सीमित है कंपनी की प्रमुख वस्तुएं स्वस्थ खाद्य उत्पादों और सेवाओं, प्रवचन और व्यावसायिक परामर्श को चलाने और प्रवर्धित करने और स्वस्थ खाद्य प्रसंस्करण और सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवसाय को सीधे या किसी वितरण चैनल के माध्यम से चलाने के लिए है [मसौदा ज्ञापन की एक प्रति और प्रस्तावित कंपनी के संघ के लेखों का कार्यालय प्लॉट नंबर 5435, शॉप न 02,1 वीं मंजिल, प्रगति विहार, डीएलएफ फेज IV, चकरपुर, गुड़गांव * हरियाणा मे कार्यालय मे निरीक्षण किया जा सकता है।- 122001 सूचना यहां दी गई है कि इस आवेदन पर आपत्ति जताने वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (CRC), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (IICA), प्लॉट नंबर 6,7,8, सेक्टर 5, IMT मानेसर में लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करा सकता है।, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड -122050, डेटोफ पब्लिशिंग से इक्कीस दिनों के भीतर यह नोटिस, प्लॉट नं 5435 पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक प्रति के साथ, दुकान नंबर 02,1 वीं मंजिल, प्रगति विहार, डीएलएफ चरण IV, चकरपुर, गुड़गांव * हरियाणा-122001।

वास्ट फ्रेश डिलाइट्स के लिए
नील बत्रा और सपना
दिनांक: 23 जनवरी, 2020 (पार्टनर्स)
प्लेस: गुड़गांव

जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड
CIN: L26922HR1980PLC010901
पंजीकृत कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125 005 (हरियाणा)
फोन नं. (01662) 222471-83, फैक्स नं. (01662) 220499
ई-मेल आईडी : investorcare@jindalstainless.com, वेबसाइट : www.jslstainless.com

कम्पनी सूचना
कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 201 (2) के अनुसरण में सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 201 (2) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, अनुसूची V और इसके अन्य सभी उपबन्धों, यदि कोई हैं तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 7 के अधीन, श्री रतन जिन्दल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक पहचान संख्या (DIN)00054026, को **1 अप्रैल 2019** से **31 मार्च 2022** तक, 3 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्ति और पारिश्रमिक के भुगतान करने हेतु, जैसा की नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल ने **6 फरवरी, 2019** को स्वीकृत किया है तथा अंशधारकों ने **4 सितम्बर 2019** को हुई वार्षिक आम बैठक में विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित किया है, के संबंध में जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड ("कम्पनी") केन्द्रीय सरकार को अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहती है। कम्पनी का कोई भी सदस्य जिसको इस आवेदन के संबंध में कोई आपत्ति है, अपनी आवेदन की सूचना, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर सचिव, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, 5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को तथा कम्पनी को भी इसके उपरोक्त पते स्थित पंजीकृत कार्यालय प्रेषित कर सकता है।

कृते **जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड**
हस्ता/-
(नवनीत रघुवंशी)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 20 मार्च, 2020

केनरा बैंक, एमसीबी फरीदाबाद, 8ए, नेहरू ग्राउण्ड, एनआईटी, फरीदाबाद
Canara Bank

शुद्धिपत्र

यह कर्जदार मैसर्स फ्रेण्ड्स ऑटो इण्डिया लि. तथा मैसर्स मेहर स्टील्स प्रा.लि. के विरुद्ध 22.03.2020 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस + जनसत्ता (दिल्ली) में प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ में है। इसके शीर्षक में कृपया शाखा का नाम रिटेल एसेट हब, फरीदाबाद एससीओ 11, सेक्टर-16, फरीदाबाद-121002 ई-मेल : rahcb3917@canarabank.com के स्थान पर केनरा बैंक, एमसीबी फरीदाबाद, 8ए, नेहरू ग्राउण्ड, एनआईटी, फरीदाबाद पढ़ें। अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

दिनांक : 24.03.2020 स्थान : फरीदाबाद
अधिकृत प्राधिकारी, केनरा बैंक

पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या साढ़े तीन लाख से अधिक

पेरिस, 24 मार्च (एएफपी)।

पूरी दुनिया में कोरोना विषाणु से संक्रमण के मामलों की संख्या तीन लाख 50 हजार से अधिक हो गई है। एएफपी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष के अंत में महामारी के फैलने के बाद से सोमवार तक इतने मामले सामने आए हैं।

पूरी दुनिया में कम से कम तीन लाख 50 हजार 142 संक्रमण, 15,873 मौतें हुई हैं जिनमें अधिकतर मामले चीन (81,093) और इटली (63,927) में सामने आए।

आधिकारिक आंकड़े वास्तविक संख्या का कुछ फीसद ही हो सकते हैं क्योंकि कई देश ऐसे मामलों की ही जांच कर रहे हैं जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि कोविड-19 महामारी स्पष्ट तौर पर ह्यतेज गति से फैल रही है। हालांकि, संगठन ने कहा कि प्रकोप के ह्यइस रूख को बदलना ह्य संभव है। संगठन के प्रमुख टेड्रॉस गेब्रयासस ने पत्रकारों से कहा, महामारी तेज हो रही है।

उन्होंने कहा, पहले मामले से एक लाख मामले तक पहुंचने में 11 दिन लगे, दूसरे एक लाख मामले पहुंचने में भी 11 दिन लगे और तीसरे एक लाख मामले सिर्फ चार दिनों में सामने आए। लेकिन उन्होंने कहा, हम असहाय नहीं हैं। हम इस महामारी पर जीत हासिल कर सकते हैं।

कोविड-19 में बिना परीक्षण की दवाओं के इस्तेमाल पर चेतावनी

जिनेवा, 24 मार्च (एएफपी)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को चेतावनी दी कि कोविड-19 के उपचार में बिना परीक्षण वाली दवाओं का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है और इससे झूठी उम्मीदें जग सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टीए गेब्रेयेसस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, बिना सही साक्ष्य के बिना परीक्षण वाली दवाओं का इस्तेमाल करने से झूठी उम्मीदें जग सकती हैं और यह लाभ के बजाए ज्यादा नुकसान कर सकती हैं और आवश्यक दवाओं की कमी हो सकती है जिनकी जरूरत अन्य बीमारियों के उपचार में होती हैं।

केपीएल इण्टरनेशनल लिमिटेड
सीआईएन: U23209DL1974PLC029068
पंजीकृत कार्यालय: 212A, 216 तथा 222, दूसरी मंजिल, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष: +91 11 43579200, फैक्स: +9111 23321019
ई-मेल: infb@kplintl.com, वेबसाइट: www.kplintl.com

असाधारण आम बैठक दिनांक 27 मार्च, 2020 की सूचना का शुद्धिपत्र

यह सूचना 27 मार्च, 2020 को 03:00 बजे अप. कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 212A, 216 तथा 222, दूसरी मंजिल, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 पर आयोजित होने वाली केपीएल इण्टरनेशनल लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना दिनांक 29.02.2020 के सन्दर्भ में है। यह शुद्धिपत्र कोविड-19 के संक्रमण के कारण राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के कारण निर्गत की जा रही है। तदनुसार उपर्युक्त निर्धारित की गयी कथित ईजीएम को कम्पनी द्वारा भावी सूचना/घोषणा तक स्थगित किया जाता है।

कृते केपीएल इण्टरनेशनल लिमिटेड
ह./-
सुरिन्दर कुमार काक
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन: 00044521

दिनांक: 24.03.2020
स्थान: नई दिल्ली

INVITATION FOR SUBMISSION OF A SCHEME OF COMPROMISE OR ARRANGEMENT FOR CORPORATE DEBTOR: CASE COLD ROLL FORMING LIMITED

(Under Section 230 of Companies Act 2013 (18 of 2013) read with Regulation 2B of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

Name of Corporate Debtor: Case Cold Roll Forming Limited
CIN: U74899DL2000PLC103752
Regd. Office: 74, Hemkunt Colony, Nehru Place, New Delhi-110048
Corporate Office: Plot No 70, Sector-32, Gurgaon, Haryana-122001
Works / Units: Village Khari, Trilokpur Road, Kala Amb, Tehsil Nahan, District Sirmour, Himachal Pradesh- 173030

Take Notice for Invitation of a Scheme of Compromise or Arrangement under Section 230 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 2B of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, from creditor/s or any class of creditors or member/s or any class of members Case Cold Roll Forming Limited.

Please take a careful note that a person, who is not eligible under the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 ("Code") to submit a resolution plan for insolvency resolution of the Corporate Debtor, Case Cold Roll Forming Limited, shall not be a party in any manner to such a scheme of compromise or arrangement.

Interested creditor/s or any class of creditors or member/s or any class of members can visit the websites, namely http://primusresolutions.in/case-cold-roll-forming-limited.html for further details and scheme submission process document. **Last date for submission of Final Scheme shall be 24" April, 2020.** In case of any other query(ies) please reach out to undersigned vide E-mail at casecold@primusresolutions.in or sanjay@sgaindia.in.

Sanjay Gupta
Liquidator-Case Cold Roll Forming Limited
IBBI Regn. No: IBBI/IPA-003/IP-N00047/2017-18/10354
Registered Address with Board: C4E/135, JanakPuri, New Delhi - 110058
Communication Address: C4E/135, JanakPuri, New Delhi - 110058
Email ID: casecold@primusresolutions.in; sanjay@sgaindia.in
Contact No.: 91 98100 41074

Date : 25.03.2020
Place : New Delhi

SOUTH INDIAN Bank

क्षेत्रीय कार्यालय
1-18/20, ह्वाइट हाउस, दूसरी मंजिल, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली-110055,
दूरभाष : 011-23610400, ई-मेल : ro1008@sib.co.in सीआईएन : L65191KL1929PLC0D1017

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) (इसके पश्चात प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम के रूप में सन्दर्भित) के तहत सूचना

सेवा में,

1. **मैसर्स आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,** पंजीकृत कार्यालय बी-97, ऑल हैवन्स बिल्डिंग, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, रिंग रोड, नई दिल्ली-110052 साथ ही गोदाम (अ) 10/12/IV, विष्णु गली, विश्वास नगर, शाहदरा, नई दिल्ली-110032 (ब) प्लॉट सं. एफ-37 (ए) रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर जिला, राजस्थान-301019 (स) ग्राम साई, तालुका पनवेल, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र-410206 तथा फैक्ट्रियाँ (द) खसरा नं. 377/175 एवं 378/175, ग्राम रखराम सिंह रोड, नालागढ़ तहसील, सोलन जिला, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-174101 (य) सं. 84, एचपीएसआईडीसी, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173205.
2. **श्री राजीव गुप्ता** निवासी बी-2/9, मॉडल टाउन-2, ग्लोबल देसी शोरूम, दिल्ली-110009
3. **श्रीमती ममता गुप्ता** निवासी बी-2/9, मॉडल टाउन-2, ग्लोबल देसी शोरूम, दिल्ली-110009
4. **मैसर्स मेटल रॉड प्रा.लि.** पंजीकृत कार्यालय बी-97, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, रिंग रोड, नई दिल्ली-110052
5. **मैसर्स एस मैट्रिक्स सॉल्यूशन्स लिमिटेड** पंजीकृत कार्यालय बी-97, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, रिंग रोड, नई दिल्ली-110052

आप में से प्रमुख कर्जदार के रूप में प्रथम तथा जमानती के रूप में 2 से 5 ने द साउथ इण्डियन बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय "एसआईबी हाउस", टी.बी. रोड, त्रिचूर-1, केरल तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक 1-18/20, ह्वाइट हाउस, दूसरी मंजिल, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली-110055 तथा इसकी एक शाखा डी 28, पीबी #323, निकट एम्बैसी होटल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से 21.12.2017 तथा 12.11.2019 को आवश्यक दस्तावेजों के क्रियान्वयन द्वारा तथा नीचे अनुसूचित आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसके पश्चात प्रतिभूत आस्तियों के रूप में सन्दर्भित) मैसर्स आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के खाते में रु. 15,00,00,000.00 (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र) हेतु विभिन्न साख सीमा ग्रहण की थी।

कथित खाते 15.11.2019 को हमारे खातों में गैर-निष्पादन आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं और हमने 15.03.2020 तक बकाया रु. 15,01,36,060.20 (रुपये पन्द्रह करोड़ एक लाख छत्तीस हजार साठ एवं बीस पैसे मात्र) तथा भावी ब्याज एवं लागतों का सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भुगतान की मांग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 16.03.2020 को सूचना निर्गत की थी। किन्तु अपने कथित सूचना की सेवा की अनदेखी की अतः प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अनुसार यह सार्वजनिक सूचना निर्गत की गयी है। अतः इस सूचना के माध्यम से आपको इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी देयताओं का भुगतान करने को कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर हम बिना किसी अन्य सन्दर्भ के नीचे अनुसूचित आस्तियों के प्रवर्तन करने के लिए कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त सभी या किसी अधिकार का उपयोग करने के लिए बाध्य होंगे।

आप पुनः ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों में से किसी का भी बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से (व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त) उपर्युक्त प्रतिभूतियों का निस्तारण या संव्यवहार करने के लिए प्रतिषिद्ध/निषिद्ध होंगे। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन कानून के अनुसार कर्जदार तथा जमानती/सह-दायित्वधारी के विरुद्ध द साउथ इण्डियन बैंक के पास उपलब्ध ऐसे अधिकारों तथा उपचारों के पूर्वाग्रह के बिना किया गया है।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

प्रतिभूत आस्तियों का विवरण

अनुसूची 'ए'

मद-I : कम्पनी के सम्पूर्ण वर्तमान आस्तियों (वर्तमान तथा भावी), समस्त मूर्त चल सम्पत्तियाँ जैसे स्टॉक-इन-ट्रेड, कच्चे माल का स्टॉक, स्टॉक इन प्रोसेस, तैयार माल, पैकिंग सामग्री तथा कर्जदार के माल, समस्त वर्तमान तथा भावी कार्यवाही योग्य दावे तता अन्य चल सम्पत्ति जो भविष्य में उपस्थित हो सकती हैं या अस्तित्व में आ सकती हैं जिसमें बुक डैट, डिक्री तथा डिक्रीताई ऋण, बकाया प्राप्तियों की राशि, निर्यात आदेश के तहत आहरित माल के स्वामित्व के दस्तावेजों द्वारा समर्थित प्राप्तियाँ/निर्यात आदेश के तहत आहरित विनिमय के स्वीकृत बिल/साख पत्र के तहत आहरित विनिमय के बिल, इनपुट टैक्स क्लेम प्राप्तियाँ, अन्य दावे (काउन्टर दावे तथा जीवन बीमा पॉलिसियों सहित बीमा पॉलिसियों के तहत दावे सहित), जो अब या इसके पश्चात समय-समय पर प्रतिभूति के दौरान भण्डार में लायी जायेगी या होगी या उनके परिसर या गोदाम 12/12/IV विष्णु गली, विश्वास नगर, शाहदरा, नई दिल्ली तथा साथ ही प्लॉट सं. एफ-37 (ए) रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर जिला, राजस्थान, साथ ही ग्राम साई, तालुका पनवेल, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र एवं फैक्ट्रियों खसरा नं. 377/175 एवं 378/175, ग्राम रखराम सिंह रोड, नालागढ़ तहसील, सोलन जिला, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173005 या किसी अन्य गोदाम में भण्डारित की जानी हो या एक गोदाम से अन्य स्थान या एक स्थान से किसी अन्य स्थान या कहीं अन्यत्र हों, का दृष्टिबन्धक।

मद-II : सभी प्रकार की मशीनरी तथा/अथवा अचल आस्तियाँ, इसके/उनके कलपुर्जे, उपकरण आदि, खरीदे गये/खरीदे जाने वाले तथा/अथवा कर्जदार(रों) से सम्बन्धित जो प्रतिभूति के दौरान समय-समय पर अब या इसके पश्चात लायी गयी हो, उनके परिसर अथवा गोदाम 12/12/IV विष्णु गली, विश्वास नगर, शाहदरा, नई दिल्ली तथा साथ ही प्लॉट सं. एफ-37 (ए) रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर जिला, राजस्थान, साथ ही ग्राम साई, तालुका पनवेल, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र एवं फैक्ट्रियों खसरा नं. 377/175 एवं 378/175, ग्राम रखराम सिंह रोड, नालागढ़ तहसील, सोलन जिला, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173005, साथ ही सं. 84, एचपीएसआईडीसी, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173005 या किसी अन्य गोदाम में भण्डारित की जानी हो या एक गोदाम से अन्य स्थान या एक स्थान से किसी अन्य स्थान या कहीं अन्यत्र हों, का दृष्टिबन्धक।

मद-III : मशीनरी तथा/अथवा अवशिष्ट शेष तथा/अथवा अचल आस्ति, इसके/उनके कलपुर्जे, उपकरण आदि, खरीदे गये/खरीदे जाने वाले तथा/अथवा कर्जदार(रों) से सम्बन्धित जो समय-समय पर अब या इसके सावधि ऋण की कार्यवाहियों से अर्जित हो, उनके परिसर/फैक्ट्री/गोदाम प्लॉट सं. 84, एचपीएसआईडीसी, बद्दी, हिमाचल प्रदेश, साथ ही औद्योगिक प्लॉट सं. 85, एचपीएसआईडीसी, बद्दी, हिमाचल प्रदेश साथ ही औद्योगिक प्लॉट सं. 97, ब्लॉक बी, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली या किसी अन्य गोदाम में भण्डारित की जानी हो या एक गोदाम से अन्य स्थान या एक स्थान से किसी अन्य स्थान या कहीं अन्यत्र हों, का दृष्टिबन्धक।

अनुसूची 'बी'

मद-I : औद्योगिक प्लॉट का सम्पूर्ण भाग, जिसका प्लॉट सं. 97, माप 2300 वर्ग गज, ब्लॉक बी, लेआउट प्लान वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली, साथ ही उस पर निर्मित समस्त भवन एवं संरचना/उन्नयन, स्वामित्व मैसर्स मेटल रॉड्स (प्रा.) लि., बेमियादी पट्टा विलेख सं. 409 दिनांक 21.02.1976 तथा एसआरओ VII, नई दिल्ली के कन्वीएंस डीड सं. 345 दिनांक 07.01.2011 के तहत पंजीकृत में अधिक स्पष्ट वर्णित, सीमाएं : उत्तर : प्लॉट सं. 98, दक्षिण : प्लॉट सं. बी-96, पूर्व : सर्विस लेन तथा पश्चिम : मेन रोड।

मद-II : लीज होल्ड औद्योगिक प्लॉट का सम्पूर्ण भाग, जिसका प्लॉट सं. 84, माप 9828 वर्ग गज, एचपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, बद्दी, सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश साथ ही उस पर निर्मित समस्त भवन एवं संरचना/उन्नयन, स्वामित्व मैसर्स आरसीआई स्ट्रिप्स (आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज की एक इकाई), एसआरओ बद्दी, हिमाचल प्रदेश के कन्वीएंस डीड सं. 12 दिनांक 04.01.2017 के तहत पंजीकृत में अधिक स्पष्ट वर्णित, सीमाएं : उत्तर : नाली/डाबर फैक्ट्री, दक्षिण : 30 फीट चौड़ी औद्योगिक क्षेत्र की सड़क, पूर्व : सम्पत्ति सं. 85 तथा पश्चिम : सम्पत्ति सं. 83.

मद-III : लीज होल्ड औद्योगिक प्लॉट का सम्पूर्ण भाग, जिसका प्लॉट सं. 85, माप 7749 वर्ग गज, एचपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, बद्दी, सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश साथ ही उस पर निर्मित समस्त भवन एवं संरचना/उन्नयन, स्वामित्व मैसर्स इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज, एसआरओ बद्दी, हिमाचल प्रदेश के कन्वीएंस डीड सं. 253 दिनांक 02.02.2018 के तहत पंजीकृत में अधिक स्पष्ट वर्णित, सीमाएं : दक्षिण-पूर्व : सड़क/फ्रंट, दक्षिण-पश्चिम : प्लॉट सं. 108, उत्तर-पूर्व : सम्पत्ति सं. 84 तथा उत्तर-पश्चिम : पीछे की ओर (नाला)

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी
(मुख्य प्रबन्धक)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 20.03.2020

EXIDE Life Insurance

Public Notice

We at Exide Life Insurance are deeply disturbed and concerned by the causalities caused due to the recent riots in North East Delhi. In these tough times, as a company we aim to provide extended support to our customers who have been affected by the violence. To speed track the process, and to ensure a hassle-free claims settlement, we have set up the following facilities for the affected families:

1. Appointment of Nodal Officer: A Nodal Officer has been appointed to assist you in addressing all your grievances and issues regarding your claims.
   The details of the Nodal officer are as follows: Name: Hitesh Kumar; Mobile: 9899535542; Email: hitesh.kumar@exidelife.in
2. Dedicated Helpline: You can reach us on any of the following:
   Call us during working hours : 080 49280628 OR 080-67999200
   Extension - 4012, 4016, 4013
   (Monday to Friday, 9.00AM to 7.00PM)
   Email us at : claims@exidelife.in
3. Easy Claims Registration: Reach out to our nodal officer or at the above mentioned numbers for us to help you with claims registration.

Exide Life Insurance Company Limited is a wholly owned subsidiary of Exide Industries Limited. The trademark "Exide" is owned by Exide Industries Limited and licensed to Exide Life Insurance vide Trademark license agreement dated 30th October 2014. Exide Life Insurance Company Limited. IRDAI Registration number: 114, CIN: U66010KA2000PLC028273, Registered Office: 3rd Floor, JP Techno Park, No. 3/1, Millers Road, Bengaluru 560001, India. Toll Free: 1800 419 8228; Visit: exidelife.in

Beware of Spurious/ Fraud Phone Calls: IRDAI is not involved in activities like selling insurance policies, announcing bonus or investment of premiums. Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint.

शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर वित्त मंत्रालय व रिजर्व बैंक की बराबर नजर : सीतारमण

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि शेयर बाजारों के उतार - चढ़ाव और घटनाक्रमों पर बाजार नियामक, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार और दूसरी वित्तीय बाजारों की स्थिति की दिन में तीन बार समीक्षा की जाती है।

सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए किए गए लॉकडाउन से हो रही परेशानियों से निपटने के लिए सरकार एक आर्थिक राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। इसके बारे में जल्द घोषणा की जाएगी।

देश में कोरोना वायरस के फैलने के बाद से शेयर बाजार में लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है। पिछले एक माह में सूचकांक 15,000 अंक से ज्यादा गिर चुका है। इसी समय डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है और अगले कुछ दिन में इसके 77 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंचने की आशंका है। दिन में कारोबार के दौरान मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 76.02 पर आ गया जो 24 फरवरी को 71.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर था। विशेषज्ञों की माने तो विदेशी निवेशकों के बाजार से पूंजी निकालने की वजह से रुपए पर दबाव है।

सीतारमण ने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक सहित दूसरे नियामकों की बाजार की स्थिति पर लगातार नजर है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बाजार की स्थिति को देखते हुये कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा- हम शेयर बाजार के उतार - चढ़ाव और घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए हैं। सेबी ने इस संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। साथ ही लघु अवधि के लेन देन से आ रही अस्थिरता की निगरानी करने के लिए अपनी स्थिति भी स्पष्ट की है ताकि शेयर बाजारों में भारी उथल-पुथल न हो। इसलिए हम हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं और दिन में तीन बार इसकी समीक्षा की जा रही है। यह बात उन्होंने यहां कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की घोषणा के दौरान कही।

उन्होंने कहा- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नियमित परामर्श किया जा रहा है। हम अन्य नियामकों से भी बातचीत कर रहे हैं। इसलिए बाजारों पर भी करीबी नजर रखी जा रही है। इसलिए मैं आपको इस बात का आश्वासन दे सकती हूं कि सभी नियामक और रिजर्व बैंक बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। हमारी हर घटनाक्रम पर नजर है।

साहिबाबाद सब्जी मंडी में मंगलवार को प्याज के भंडार के पास मास्क पहने बैठा थोक विक्रेता

रुपया 26 पैसे उछल कर प्रति डालर 75.94 पर

मुंबई, 24 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस की वजह से उत्पन्न संकटों से निपटने के लिए जल्द आर्थिक पैकेज लाने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मंगलवार की घोषणा के बाद रुपए में पिछले चार दिन से चली आ रही गिरावट थम गई और यह 26 पैसों के लाभ के साथ 75.94 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

सुबह शुरू में डालर के मुकाबले रुपए में मजबूती थी। लेकिन कोरोना वायरस का घरेलू अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों की चिंताओं के बीच इसमें भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। बाद में सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज पर काम हो रहा है। बाद में रुपए में सुधार आया।घरेलू शेयर बाजार में सुधार से भी रुपए को समर्थन मिला।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 76.02 पर खुला। दिन के कारोबार में यह 75.94 के उच्च स्तर और 76.40 रुपए के निम्न स्तर के बीच झूलता रहा। अंत में रुपया 26 पैसे की तेजी के साथ 75.94 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 76.20 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

एन्मी ने सेबी से दो दिन के लिए शेयर बाजार बंद करने को कहा

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)

शेयर ब्रोकरों के संगठन एन्मी ने मंगलवार को बाजार नियामक सेबी से कम से कम दो दिन के लिए शेयर बाजारों को बंद करने के लिए कहा। एन्मी का कहना है कि इससे सभी राज्यों द्वारा शेयर ब्रोकिंग को आवशयक सेवा घोषित नहीं करने की स्थिति में ब्रोकरेज फर्मों को अपनी पूरी बकाया स्थिति को सही करने का समय मिल जाएगा।

इस बीच, केंद्र सरकार ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से सेबी विनियमित शेयर बाजारों की गतिविधियों और उनके कार्यबल को कारोना वायर संक्रमण से बचाव के लिए लागू पाबंदी से छूट देने का अनुरोध किया। यह अपील शेयर बाजारों में ब्रोकरों, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और शेयर बाजारों से संबंधित अन्य कर्मियों को कार्यस्थल तक पहुंचने में हो रही कठिनाइयों की वजह से की गई है। अब तक केवल केवल तीन राज्यों- महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान ने 'शेयर ब्रोकिंग और डिपॉजिटरी सेवाओं' को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया है।

एन्मी ने कहा कि उसके सदस्यों और उनके कर्मचारियों को अपने केंद्रीय सर्वर, बैंक संबंधी कार्यों, जोखिम प्रबंधन और डिपॉजिटरी सेवाओं के संचालन के लिए मुख्य कार्यालय तक पहुंचने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सेबी को लिखे पत्र में एन्मी ने सभी राज्य सरकारों को आवश्यक सलाह जारी करने के लिए कहा है कि वे बंदी या कर्फ्यू के दौरान शेयर ब्रोकिंग और डिपॉजिटरी सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषणा करें।

एन्मी ने आगे कहा- अगर सभी राज्य बंदी या कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं के रूप में शेयर ब्रोकिंग और डिपॉजिटरी सेवाओं को छूट देने की घोषणा नहीं करते हैं तो शेयर ब्रोकरों को समय देने के लिए शेयर बाजारों को दो दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। एन्मी विभिन्न शेयर बाजारों के 900 से अधिक शेयर ब्रोकरों का प्रतिनिधित्व करती है।

कोरोना वायरस से निपटने के उपायों के साथ शेयर बाजारों में तेजी, सूचकांक 693 अंक मजबूत

मुंबई, 24 मार्च (भाषा)।

स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार की एतिहासिक गिरावट के बाद मंगलवार का दिन थोड़ी राहत वाला रहा। कोरोना वायरस के खतरे के बीच भारत सहित बड़े देशों में आर्थिक स्थितियों को सुधाने के प्रयासों के वैश्विक स्तार पर बाजारों में सुधार से संकेत लेकर स्थानीय बाजारों में लिवाल मंगलवार को सक्रिय दिखे। लिवाली के समर्थन से बीएसई सूचकांक और एनएसई निफ्टी में ढाई फीसद से अधिक का सुधार दर्ज किया गया।।

तीस शेयरों वाला सूचकांक 692.79 अंक यानी 2.67 फीसद की बढ़त के साथ 26,674.03 अंक पर बंद हुआ। ऊंचे में यह 27,462.87 तथा नीचे में 25,638.90 अंक तक गया। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 190.80 अंक यानी 2.51 फीसद की बढ़त के साथ 7,801.05 अंक पर बंद हुआ। दोनों सूचकांकों में सोमवार को बड़ी गिरावट आई थी और ये 13 फीसद नीचे आ गए थे। फेडरल रिजर्व के अमेरिकी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए असीमित मात्रा में बांड खरीद कार्यक्रम की घोषणा से एशिया के अन्य बाजारों में सकारात्मक रुख का असर घरेलू बाजारों पर भी पड़ा।

सूचकांक में शामिल लाभ में रहने वाले प्रमुख शेयरों में इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, मारुति, एचयूएल, एचसीएल टेक और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है। वहीं महिन्द्रा एंड महिद्रा, इंडसइंड बैंक, आइटीसी, पावर ग्रिड और एल एंड टी नुकसान में रहे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- बाजार में सोमवार की बड़ी गिरावट के बाद मंगलवार कुछ राहत रही। यह वैश्विक बाजारों के अनुरूप है।

इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सोमवार को बड़े स्तर पर प्रोाहनत्साहन पैकेज से राहत मिलने के साथ सरकार की तरफ से भी वित्तीय प्रोत्साहन की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बाजार बड़ी बढ़त के बाद नीचे आ गया। इसका कारण आर्थिक पैकेज पर अभी काम जारी है। इसके अलावा यूरोपीय संघ और अमेरिका में विनिर्माण गतिविधियों के आंकड़े भी आज आने वाले हैं। इससे कोरोना वायरस का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का संकेत मिल सकता है। इसका कल बाजारों पर असर दिख सकता है।

कोरोना वायरस के कारण 'कफ्यू जैसी पाबंदियों' से उद्योग पर पड़ने वाले असर और रोजगार की कटौती की आशंका के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संकट से पार पाने में मददगार आर्थिक पैकेज की घोषणा जल्द की जाएगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा कि वह असीमित मात्रा में ट्रेजरी बांड की खरीद करेगा। यानी केंद्रीय बैंक अतिरिक्त डॉलर की छपाई करेगा। साथ ही छोटे व मझोले आकार की कंपनियों को सीधे कर्ज देने का नया कदम उठाएगा जो आर्थिक गतिविधियां थमने से काफी प्रभावित हैं।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पहल के बाद दूसरे केंद्रीय बैंक भी आर्थिक संकट से पार पाने के लिए साहसिक कदम उठा सकते हैं। कारोबारियों के अनुसार भारत और दुनिया के अन्य देशों में 'लॉकडाउन' से वैश्विक निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा है। एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग, तोक्यो और सोल में आठ फीसद तक की तेजी आई। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरूआती कारोबार में छह फीसद तक की तेजी दर्ज की गयी।

इस बीच, भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 500 पार कर गई है और एक अन्य व्यक्ति की मौत संक्रमण के कारण हो चुकी है। इस बीच, केंद्र ने मंगलवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। लोगों के बंदी के बाद भी घरों से बाहर निकलने को देखते हुए यह आदेश दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 3,80,000 पहुंच गई है जबकि अब तक 16,500 लोगों की मौत हो चुकी है।

'महामारी में सोना बेहतर विकल्प'

मुंबई, 24 मार्च (भाषा)।

ऐसे समय जब निवेशक कोरोना वायरस के फैलने से बुरी तरह डरे हुए हैं और बाजार भारी उठापटक के दौर से गुजर रहे हैं, 'वर्ल्ड गोल्ड कार्उसिल (डब्लूजीसी) ने कहा है कि सोना ऐसे समय में जरूरी नकदी और तरलता उपलब्ध करा सकता है जिसमें साख का भी कोई जोखिम नहीं है और यह आपके समूचे पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को भी बेहतर बना सकता है।

डब्लूजीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सोना स्पष्ट तौर पर शेयर, बांड और व्यापक आधार वाले पोर्टफोलियो का अनुपूरक हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रणालीगत असफलता, मुद्रा अवमूल्यन और मुद्रास्फीति जोखिमों से बचाव और ढाल बनने की पूरी क्षमता है। डब्लूजीसी की इस रिपोर्ट का नाम 'एक रणनीतिक संपत्ति के तौर पर सोने की उपयोगिताः भारती परिपेक्ष में। रिपोर्ट में कहा गया है कि एतिहासिक रूप से सोना पोटफोलियो से जुड़े रिटर्न जोखिम को समन्वित करने में मदद करता है, सकारात्मक रिटर्न उपलब्ध कराता है और बाजार में दबाव पैदा होने की स्थिति में यह देनदारियों को पूरा करने की क्षमता रखता है।

डब्लूजीसी के प्रबंध निदेशक, भारत, सोमासुंदरम पीआर का कहना है- भारतीय निवेशकों के लिए आज सोना पहले से कहीं अधिक प्रासांगिक है। अनिश्चितता के ऐसे समय में जब वैश्विक बाजारों में उठापटक चल रही है, सोना पोर्टफोलियो के विभिन्न स्तरों पर जोखिम और रिटर्न के बीच समायोजन में सुधार लाने की क्षमता रखता है और यह मुद्रास्फीति के समक्ष आपके लिए बचाव का भी साधन बनता है, हमारे आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि सोने के साथ ही विविध स्टॉक वाले पोर्टफोलियो में बाजार की घटबढ़ पर घबराहटपूर्ण प्रतिक्रिया का जोखिम नहीं रहता है।

निवेशकों की संपत्ति 1.82 लाख करोड़ बढ़ी

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

शेयर बाजारों में मंगलवार को कुछ सुधार आने से निवेशकों की संपत्ति 1,82,769.92 करोड़ रुपए बढ़ गई। शेयर बाजारों में सोमवार को आई बड़ी गिरावट के बाद बाजार मंगलवार को कुछ मजबूत हुए।

वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी के साथ घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती रही। यह उम्मीद की जा रही है कि सरकारें कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन उपायों की घोषणा कर सकती हैं। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक मंगलवार को 692.79 अंक यानी 2.67 फीसद की बढ़त के साथ 26,674.03 अंक पर बंद हुआ। इससे सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1,82,769.92 करोड़ बढ़कर 1,03,69,706.20 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

हीरो साइकिल्स ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बनाई सौ करोड़ की आकस्मिक निधि

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

हीरो साइकिल्स ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अलग से 100 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि बनायी है। इसका उपयोग कंपनी अपने सहयोगियों और व्यापक स्तर पर समाज के लोगों को कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाने में करेगी।

हीरो साइकिल्स के चेयरमैन पंकज एम मुंजाल ने कहा- मानवता को ध्यान में रखकर काम करने वाले एक कारोबारी संगठन के तौर पर हम 100 करोड़ रुपए की अलग से एक आकस्मिक निधि बना रहे हैं। यह राशि हमारे पूरे संगठन के ईद गिर्द के समूचे परिवेश को इस संकट से उबारने में मदद करने के काम आएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी सभी संभव मदद मुहैया कराने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत कर रही है।

हीरो साइकिल्स ने एक आपातकालीन निगरानी प्रकोष्ठ भी बनाया है। मुंजाल इसके अध्यक्ष हैं। यह प्रकोष्ठ कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला पर इस महामारी के प्रभाव और आर्थिक असर पर नजर रखे हुए है।

महिंद्रा सीआइई ने उत्पादन रोका

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव ने कोरोना वायरस महामारी से कर्नाटक को छोड़कर देश भर में अपनी उत्पादन गतिविधियों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

महिंद्रा सीआइई ऑटोमोटिव ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी और उसकी सहायक इकाई औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 23 मार्च से अगले सरकारी आदेश तक सभी विनिर्माण इकाइयों में कामकाज बंद कर दिया है। हालांकि इसमें कर्नाटक की इकाइयां शामिल नहीं हैं। कंपनी ने बताया कि कर्नाटक के संयंत्रों में 25 मार्च से 31 मार्च 2020 तक काम बंद रहेगा।

इटली स्थित उसकी सहायक कंपनी मेटेलकास्टेलो ने भी 23 मार्च से अपना परिचालन बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा कि बंदी छह अप्रैल 2020 तक जारी रहने का अनुमान है।

हिमाचल में कोकाकोला के खिलाफ एफआइआर

शिमला, 24 मार्च (भाषा)।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रकोप से बंदी के आदेश के बावजूद एक अलग इकाई द्वारा संचालित कोका कोला के संयंत्र के खुले रहने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के अलावा सभी इकाइयां लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी।

बद्दी के पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने कहा कि नालागढ़ में कृष फ्लैक्सीपैक्स द्वारा संचालित कोका कोला फैक्टरी को सोमवार रात औचक निरीक्षण के दौरान खुला पाया गया। उन्होंने कहा कि नालागढ़ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 188 (सार्वजनिक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत कारखाने और उसके मालिकों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस कार्रवाई पर कंपनी की आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं मिल सकी है।

सार्वजनिक उपक्रम जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करें : प्रधान

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को अपने मंत्रालयों के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के शीर्ष प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।

यह बैठक कोरोना वायरस महामारी के बीच स्थिति का जायजा लेने के लिए बुलाई गई थी. सूत्रों के अनुसार मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ओएनजीसी, गेल, सेल, आरआइएनएल, एनएमडीसी, मॉयल और केआइओसीएल समेत अन्य उपक्रमों के प्रमुख शामिल हुए। उन्होंने बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, रिफाइनरियों के परिचालन और महत्त्वपूर्ण इस्पात संयंत्रों के कामकाज की समीक्षा की और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। एक सूत्र ने बताया कि मंत्री मंगलवार को घर से काम कर रहे थे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री ने कोरोना वायरस संक्रमण से कर्मचारियों और उनके परिजनों के बचाव के लिये प्रबंधन की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी दी। मंत्री ने सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कर्मचारियों और उनके परिजनों को जरूरी सामानों का उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित नहीं हो। साथ ही उन्होंने कंपनी प्रमुखों को संयंत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है।

कार्यालय नगर निगम कोटा (राज.)

क्रमांकः-ननिको/वि./2020/Sp1-7 दिनांक 24-3-2020

ई-निविदा संशोधन

इस कार्यालय द्वारा जारी ई निविदा सूचना क्रमांक ननिको/वि./2020/2322-29 दिनांक 11/03/2020 नगर निगम उत्तर/दक्षिण के विभिन्न वार्डो में वायरिंग/रिवायरिंग के कार्य का वार्षिक अनुबंध में निविदा डाउनलोड व अपलोड करने की तिथि दिनांक 07.04.2020 को सायं 6:00 बजे तक बढाई जाती है, तथा धरोहर राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस प्राप्त करने की तिथि दिनांक 08.04.2020 को सायं 6:00 तक रहेगी। तकनीकी बिड खोलने की तिथि 09.04.2020 को दोपहर 12:00 बजे तथा वित्तीय बिड तकनीकी बिड परीक्षण पश्चात खोली जावेगी।
शेष यथावत रहेगा।

हस्ता./-
अधीक्षण अभियंता (वि.)
नगर निगम कोटा

कार्यालय, ग्रा.पं.हाशिमपुर खेड़ा, शाहजहाँपुर

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

समस्त पंजीकृत फर्मों/विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हाशिमपुर खेड़ा द्वारा वर्ष 2019–20 की स्वीकृत कार्य योजना में नरेगा के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार निर्माण कार्य कराने हेतु निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्चकोटि की निर्माण सामिग्री तथा सीमेन्ट, रेता, बजरी, बजरफुट, ईंट–प्रथम, चटका ईंट की रोड़ी, इण्टरलाकिंग ईंट, आदि कार्यस्थल पर आपूर्ति हेतु सीलबन्द निविदाएं 26.03.2020 को सायं 3 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। सभी निविदाएं/निविदादाता/उनके समक्ष 26.03.2020 को सायं 5 बजे तक ग्राम पंचायत में खोली जायेंगी।

मनरेगा 2019–20

क्र.	कार्य का नाम	
1.	शिवपाल सिंह के मकान से रम्मू वाल्मीक के मकान तक इण्टर लॉकिंग व नाली निर्माण	
	1. इण्टरलॉकिंग	– 11000 संख्या
	2. ईंट	– ईंट 5000 संख्या
	3. सीमेन्ट	– 50 बोरी
	4. मौरंग	– 100 कु.
	5. रेता	– 150 कु.

उर्मिला देवी–प्रधान राकेश सिंह–टी.ए. गनेश कुमार–सचिव

निर्माण मजदूरों को उपकर कोष से मिले सहायता : गंगवार

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे 3.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को 52,000 करोड़ रुपए के निर्माण श्रमिक उपकर कोष से वित्तीय मदद उपलब्ध कराने को कहा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्माण क्षेत्र पर पड़ रहे असर के बीच उन्होंने यह बात कही है।

गंगवार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस संदर्भ में 24 मार्च को परामर्श जारी किया। पत्र में मंत्री ने कहा है कि इमारत और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्लू) कानून, 1996 की धारा 60 के तहत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे बीओसीडब्लू उपकर कानून के तहत निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा एकत्रित उपकर कोष में से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं।

पत्र में कहा गया है कि करीब 52,000 करोड़ रुपए उपकर कोष में जमा है। यह राशि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने एकत्रित किए हैं। करीब 3.5 करोड़ निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी निर्माण कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं।

मंत्री ने पत्र में कहा है कि यह चुनौतीपूर्ण स्थिति है, यह जरूरी है कि हम समस्या के समाधान को लेकर एक संभावित व्यवस्था बनाएं जिससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मदद दी जा सके। निर्माण क्षेत्र पर उपकर लगाया जाता है और केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार लागत का एक फीसद वसूला जाता है।

बीओसीडब्लू कल्याण उपकर, 1996 के तहतं अधिकतम दो फीसद और कम-से-कम एक फीसद उपकर लगाए जाने और वसूले जाने का प्रावधान है। दर के बारे में अधिसूचना केंद्र सरकार जारी कर सकती है। इस उपकर का उपयोग निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण में किया जाता है।

घरेलू उड़ानों के निलंबित रहने के दौरान कर्मचारियों का नहीं कटेगा वेतन और छुट्टी : इंडिगो

मुंबई, 24 मार्च (भाषा)।

इंडिगो ने अपने कर्मचारियों को घरेलू उड़ानों के निलंबित रहने की अवधि में वेतन और छुट्टी नहीं कटने का भरोसा दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने देश में घरेलू उड़ानों को मंगलवार मध्यरात्रि से 31 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया है।

इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजय दत्ता ने कर्मचारियों को भेजे एक ई-मेल में कहा कि कंपनी के पास अप्रैल के लिए पहले से 'ठीकठाक' अग्रिम बुकिंग है। इंडिगो कम क्षमता के साथ ही फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा-ऐसे में जिन कर्मचारियों को इस अस्थायी निलंबन की अवधि में काम नहीं करना पड़ रहा है। हम उनके वेतन में कोई कटौती नहीं करेंगे और ना ही उनकी छुट्टियां काटेंगे। एजंसी ने यह ई-मेल देखा है। दत्ता ने कहा कि पिछले कुछ दिन विमानन कंपनी के लिए काफी चुनौती भरे रहे हैं और 'निश्चित तौर पर आने वाले कुछ हफ्तों में हमारी आय, हमारी लागत से कम रहेगी। ऐसे में हमें अपनी नकदी और पाई-पाई बचाने के प्रयास करने होंगे।' उन्होंने कहा यह भी कहा कि इस अस्थायी निलंबन की अवधि के दौरान कर्मचारियों का वेतन वगैरह देने के लिए कंपनी अपनी बचत पूंजी का इस्तेमाल करेगी।

एसईसी ने विसलब्लोअर मामले में जांच पूरी की, आगे कार्रवाई का अनुमान नहीं : इन्फोसिस

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

आइटी कंपनी इन्फोसिस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने पिछले साल लगाए गए विसल ब्लोअर आरोपों में जांच पूरी कर ली है और उसे नहीं लगता है कि नियामक इस बारे में आगे कोई कार्रवाई करेगा।

इन्फोसिस ने पिछले साल अक्तूबर में शेयर बाजार को बताया था कि उसे कुछ अज्ञात विसल ब्लोअरों से शिकायतें मिली हैं कि कंपनी के शीर्ष प्रबंधन द्वारा कथित रूप से कुछ अनैतिक प्रथाओं को अपनाया जा रहा है। इसके बाद कंपनी ने मामले की जांच शुरू की और बाहरी जांचकर्ताओं को नियुक्त किया। अमेरिकी बाजार नियामक एसईसी ने भी मामले की जांच शुरू की थी।

इंफोसिस ने मंगलवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे एसईसी से एक अधिसूचना मिली है, जिसमें कहा गया है कि उसकी जांच खत्म हो गई है। इंफोसिस ने कहा- कंपनी को इस मामले पर एसईसी से आगे किसी भी की कार्रवाई का अनुमान नहीं है। बंगलुरु स्थित कंपनी ने कहा कि उसने भारतीय नियामक अधिकारियों से मिले सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और वह अधिकारियों के साथ सहयोग जारी रखेगी।

इस साल जनवरी में इंफोसिस ने कहा था कि उसकी लेखा समिति को वित्तीय गड़बड़ी या कार्यकारियों के गलत आचरण का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके साथ ही सीईओ सलिल पारेख और सीएफओ नीलांजन रॉय को दोषमुक्त माना गया, जिन पर कंपनी के बहीखातों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था।

www.readwhere.com

निर्माण क्षेत्र के कामगारों की मदद करें राज्य : सोनिया

कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 24 मार्च (भाषा)।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर कहा है कि कोरोना संकट के मद्देनजर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को कुछ निश्चित राशि की मदद दी जाए।

सोनिया ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को पत्र लिख कर कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कड़े कदमों का असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर बुरा असर पड़ा है और ऐसे में उनकी मदद की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए बने राज्य बोर्ड के तहत पंजीकृत मजदूरों की मदद के लिए कुछ राशि निर्धारित की जाए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, निर्माण क्षेत्र नोटबंदी और जीएसटी के कदमों से पहले ही कराह रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस की नजह से उत्पन्न हालात के कारण यह संकट और गहराएगा।

सोनिया के मुताबिक, कनाडा समेत कई देशों ने कोरोना संकट के बीच आर्थिक योजना सामने रखी है। ऐसे में कागमारों के हित में कदम उठाने की जरूरत है।

उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह भी कहा कि वो निर्माण क्षेत्र के कामगारों की मदद के संदर्भ में हुई प्रगति के बारे में उन्हें सूचित रखें।

मोदी से भी मदद का आग्रहः कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया कि कोरोना संकट के मद्देनजर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए आपात कदम उठाए जाएं और कुछ निश्चित राशि की मदद उन्हें दी जाए।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सोनिया ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि निर्माण क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए बने राज्य बोर्डों ने उपकर के माध्यम से 31 मार्च, 2019 तक 49,688 करोड़ की राशि का संग्रह किया था और इसमें से सिर्फ 19,380 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

उन्होंने कहा, हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदमों की जरूरत है। इन कदमों से आर्थिक गतिविधियां व्यापक रूप से बाधित हुई हैं जिसका असंगठित क्षेत्र पर काफी बुरा असर पड़ा है। लाखों प्रवासी कामगार बड़े शहरों से अपने कस्बों और गांवों की तरफ कूच कर गए हैं।

बंगलुरु की एक निजी कंपनी के कर्मचारी मंगलवार को ड्रोन के जरिए इलाके को कीटाणुमुक्त करते हुए।

ताली बजाओ अपील के प्रति लोगों का लापरवाह रवैया : शिवसेना

मुंबई, 24 मार्च (भाषा)।

शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के काम में लगे लोगों की सराहना करने के लिए ताली बजाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के कारण लोग इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए लागू पूर्ण बंदी की गंभीरता को समझ नहीं रहे। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि देश के लोग किसी चीज को तभी गंभीरता से लेते हैं, जब उसे लेकर भय या आतंक महसूस हो।

मराठी दैनिक में कहा गया कि जब लोगों में डर बढ़ने लगा था, प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बॉलकनी में निकल कर ताली और थाली बजाने के लिए कहा। इसमें कहा गया कि अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए लोग बड़ी संख्या में बाहर आए और सड़कों पर नाचने लगे, जिससे स्थिति उत्सव जैसी लगने लगी।

उद्धव ठाकरे नीत पार्टी ने कहा कि इस पूरे मुद्दे को किसने गैर-गंभीर नजरिया दिया? राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। हमने निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन किया। यह नागरिकों का कर्तव्य है कि वे बंद के संबंध में राज्य सरकार के आदेश का पालन करें। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अब लोगों से घर में रहने और बंद को गंभीरता से लेने की अपील की है। लेकिन लोगों को ताली बजाने और थाली बजाने की रविवार की घटना के बाद कोरोना वायरस से डर नहीं लग रहा।

इस पूरे मुद्दे को किसने गैर-गंभीर नजरिया दिया? राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। हमने निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन किया। यह नागरिकों का कर्तव्य है कि वे बंद के संबंध में राज्य सरकार के आदेश का पालन करें।

शिवसेना ने पूछा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा चिंता जाहिर करने का क्या फायदा, जब लोग वर्तमान स्थिति के प्रति गंभीर या चिंतित ही नहीं रहेंगे? सामना में कहा गया कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीमाएं सील कर दीं और कहा कि हवाईअड्डा भी बंद रहेगा। लेकिन तब नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि हवाईअड्डे खुले रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें उतरेंगी।

भीलवाड़ा में निजी अस्पताल के 12 कर्मी कोरोना संक्रमित

बड़े स्तर पर की जा रही है जांच

भीलवाड़ा, 24 मार्च (भाषा)।

राजस्थान के टैक्सटाइल कस्बे में एक निजी अस्पताल में तीन चिकित्सकों और नौ नर्सिंग कर्मियों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद महामारी के खतरे को देखते हुए बड़े स्तर पर लोगों की जांच कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने संक्रमण के स्रोत का पता लगाने के लिए जिले में कर्फ्यू लगा दिया है और शहर की सीमाओं को सील कर दिया है।

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि मार्च 19 से 24 तक 1,075 दलों ने लगभग 70,000 निवासियों का सर्वे किया है। शहर और ग्रामीण इलाकों में रह रहे 3.5 लाख लोगों की जांच की गई है। भीलवाड़ा में बिना जांच के प्रवेश और निकास निषेध कर दिया गया है। हम संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा- भीलवाड़ा की तुलना इटली से करना गलत है। कृपया किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से दूर रहें। हमारे पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वेंटीलेटर, मास्क, सेनेटाइजर की कोई कमी नहीं है।

शर्मा ने कहा कि निजी अस्पताल के कर्मियों में संक्रमण अस्पताल की गलती के कारण फैला है। संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई तरह के प्रबंध किए हैं। विभाग बारीकी से निगरानी बनाए हुए है। चिंता की कोई बात नहीं है। राज्य में अब तक 32 कोविड-19 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सभी का स्वास्थ्य स्थिर है। अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार 13 पॉजिटिव मरीजों के सीधे संपर्क में कुल 124 लोग आए हैं, 95 विदेश से वापस लौटे लोगों सहित 2,507 लोग इंफ्लूएंजा जैसी बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं। 123 लोग घरों में पृथक रह रहे हैं, 38 लोग अस्पताल के पृथक वार्ड में हैं जबकि 130 लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किए गए सुविधा केंद्र में पृथक रखा गया है।

भीलवाड़ा के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डा मुश्ताक खान ने बताया कि तीन चरणों में जांच होनी है। पहले चरण की जांच दो दिन में पूरी कर ली जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने उन क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया है, जहां दूसरे चरण की जांच की जानी है। अजमेर जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने हाल में भीलवाड़ा जाने वाले लोगों से सूचना देने की अपील करते हुए उन्हें नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने को कहा है।

राज्य में कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए 32 मरीजों में से 13 भीलवाड़ा में, 6 जयपुर में, 4 झुंझुनूं में, 3 जोधपुर में 2 प्रतापगढ़ में और एक-एक पाली और सीकर में पाया गया है। इसके अलावा इतावली दंपति में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। आधिकारिक संख्या के अनुसार 89 लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है।

बढ़ते मामलों के तहत केरल ने 276 चिकित्सकों की नियुक्ति की

तिरुवनंतपुरम, 24 मार्च (भाषा)।

राज्य में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर और इस संकट से निपटने के लिए केरल की सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 276 चिकित्सकों की नियुक्ति की है।

राज्य लोक सेवा आयोग ने वर्तमान रैंक सूची से चिकित्सकों का चयन किया और नियुक्ति दी। ये नवनियुक्त चिकित्सक स्वास्थ्य मंत्रालय का हिस्सा बनकर कोविड-19 से लड़ाई में सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। केरल में कोविड-19 के 28 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही सोमवार देर रात से लॉकडाउन हो गया था। एक दिन में सामने आए ये सर्वाधिक मामले थे। राज्य में 91 लोगों का इलाज चल रहा है और 64,000 लोगों पर नजर रखी जा रही है।

विजयन ने पोस्ट में लिखा कि 276 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है, जो पीएससी की रैंक सूची में थे। चिकित्सकों की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार योजनाओं को लागू करने और एहतियातन कदम उठाने के लिहाज से की गई है।

गुजरात के सूरत में बंदी के नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करते पुलिसकर्मी ।

मप्र के भोपाल और जबलपुर शहरों में कर्फ्यू

भोपाल, 24 मार्च (भाषा)।

मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना का प्रसार रोकने के प्रयासों के तहत राजधानी भोपाल व जबलपुर शहरों में मंगलवार से कर्फ्यू लगा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कदम कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने लोगों से कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया है।

चौहान सोमवार रात चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राजभवन से सीधे मंत्रालय पहुंचे और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। उन्होंने जबलपुर और भोपाल में कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए पूरी तरह लॉकडाउन करने के निर्देश दिए। इस दौरान सिर्फ जरूरी वस्तुएं और सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि यह कड़ा कदम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से उठाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की स्थिति में दूध, किराना, सब्जी और दवाई जैसे अत्यावश्यक सामान की आपूर्ति श्रृंखला को और ज्यादा सक्षम बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 39 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए घरों से न निकलें। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर 104 और 181 का भी उपयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूरी तरह से लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करें। उन्होंने सभी कलक्टरों को भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में सतर्कता बरतें और लोगों को एक जगह जमा नहीं होने दें। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके फैलाव की चेन को खत्म करें। यह तभी संभव है कि लोग आपस में न मिलें।

चौहान के कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में संसाधन उद्योग को चालू रखें ताकि जरूरी उपकरण जैसे मास्क, सेनेटाइजर आदि की कमी न पड़े। उन्होंने संक्रमण की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए बनाए गए प्रतिक्रिया दल को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अस्पतालों में संक्रमण से संभावित व्यक्तियों को अलग रखने के लिए पर्याप्त बिस्तरों की व्यवस्था करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि अगले तीन माह की तैयारियां रखें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध पांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाते हुए सागर और ग्वालियर में नई प्रयोगशालाएं स्थापित करें और इन्हें 24 घंटे खुला रखें। फिलहाल एम्स भोपाल, आइसीएमआर जबलपुर, डीआरडीओ ग्वालियर, एमवाइ हॉस्पिटल इंदौर, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रयोगशाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों के चिकित्सा कर्मचारियों को कोरोना का प्रसार रोकने के लिए तैनात करें। उन्होंने विदेशों से आ रही उड़ानों पर विशेष नजर रखने और धार्मिक व पर्यटन स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों में आए पर्यटकों की विशेष जांच करने के निर्देश भी दिए।

बांग्लादेश के 2002 मस्जिद विस्फोट मामले में वांछित गिरफ्तार

मुंबई, 24 मार्च (भाषा)।

बांग्लादेश में 2002 में मस्जिद में तीन विस्फोट करने के सिलसिले में वांछित एक व्यक्ति को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि पड़ोस की ठाणे पुलिस की अपराध शाखा ने 42 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया, जो मस्जिद के अंदर एक और बाहर दो विस्फोट करने की घटना में शामिल था। उन्होंने बताया कि इन तीन बम धमाकों में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। ये विस्फोट कोलारुआ पुलिस थाना क्षेत्र के इलिसपुर में हुए थे।अधिकारी ने बताया कि शख्स की पहचान मोफजल हुसैन उर्फ मोफा अली गाजी उर्फ मफीजुल मंडल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बांग्लादेश के खुलना राज्य का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से पड़ोस के नवी मुंबई में तुर्भे में रह रहा था और कुछ फुटकर काम कर रहा था।

पृथक रहने संबंधी नियमों के उल्लंघन पर छात्र के खिलाफ मुकदमा

मुंबई, 24 मार्च (भाषा)।

ब्रिटेन से लौटने पर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अपने दोस्त से मिलने चले गए 24 वर्षीय छात्र पर कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर घर में पृथक रहने के संबंध में जारी परामर्श का उल्लंघन करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि निकाय अधिकारियों को छात्र नवी मुंबई के सीवुड्स इलाके के एनआरआई कॉम्प्लेक्स स्थित अपने घर से सोमवार को नदारद मिला था, जिसके बाद उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि छात्र कुछ दिन पहले ब्रिटेन से लौटा था। घर में पृथक रहने की निकाय अधिकारियों की सलाह के बावजूद वह पड़ोस के ठाणे के डोंबीवली में अपने दोस्त से मिलने चला गया। संक्रमण फैलने की आशंका के चलते नवी मुंबई महानगर पालिका (एनएमएमसी) स्वास्थ्य केंद्र ने एनआरआई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि बाद में पुलिस ने छात्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि एनएमएमसी अधिकारियों ने छात्र की हरकत के बारे में ठाणे पुलिस और कल्याण-डोंबीवली निकाय अधिकारियों को बताया।

जनता कर्फ्यू में जश्न मनाने वाले दो सौ लोगों पर मामले दर्ज

इंदौर (मध्य प्रदेश), 24 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए बुलाए गए जनता कर्फ्यू के दौरान यहां दो दिन पहले अलग-अलग इलाकों में सड़कों पर उतर कर जश्न मनाने वाले करीब दो सौ अज्ञात लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं। इस घातक बीमारी से बचाव के लिए सरकार के जारी परामर्शों की खुलेआम अनदेखी करने वाले इन लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो चुके हैं।

पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ये लोग शहर के राजबाड़ा और पाटनीपुरा इलाकों में रविवार को जनता कर्फ्यू का जश्न मनाने जुलूस की शक्ल में सड़कों पर उतरे थे। तब इन्होंने जोर-जोर से ढोल, थालियां और वाहनों के हॉर्न भी बजाए थे।

बंदी तोड़ने वालों को पुलिस ने 'समाज का दुश्मन' बताया

विवादास्पद इबारत का पर्चा पकड़ा कर खींची फोटो

इंदौर (मध्य प्रदेश), 24 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के कारण जिले में बंदी लागू होने के बावजूद सड़क पर बिना-वजह घूमते मिले कुछ लोगों को शर्मिंदा करने के लिए पुलिस ने मंगलवार को अनोखा तरीका अपनाया।

पुलिस ने बंदी के दौरान बाहर घूम रहे लोगों को एक पर्चा थमाकर फोटो खिंचवाने पर कथित रूप से मजबूर किया जिस पर छपा था-'मैं समाज का दुश्मन हूं। न मैं मास्क लगाऊंगा और न ही घर में रहूंगा।' ऐसा ही दृश्य शहर के रीगल चौराहे पर नजर आया। इस वाकए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में एक वाहन चालक विवादास्पद इबारत वाला पर्चा थामे दिखाई दे रहा है, जबकि मास्क लगाकर ड्यूटी कर रहा एक पुलिस अधिकारी उसके पास खड़े होकर उस पर नाराजगी जता रहा है।

वीडियो में पर्चा थामे खड़े व्यक्ति की ओर उंगली से इशारा करते हुए पुलिस अधिकारी कहता सुनाई दे रहा है, 'ये कार लेकर घूमने निकले हैं फालतू में।' वीडियो में पर्चा थामे खड़े व्यक्ति को ठीक से पोज देने की नसीहत के साथ पुलिस अधिकारी यह भी कहता सुनाई पड़ता है, '(पर्चे को) थोड़ा नीचे करो। नेशनल न्यूज में आओगे आप।'

पुलिस के इस तरीके पर सवाल भी उठ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय मिश्र ने कहा, 'संविधान और कानून के मुताबिक पुलिस आम लोगों को इस तरह के आपत्तिजनक पर्चे कतई नहीं थमा सकती। वह अपने हिसाब से आम लोगों को समाज के दुश्मन की उपमा देकर उन्हें सार्वजनिक रूप से जलील नहीं कर सकती।' मिश्र ने कहा, 'पुलिस द्वारा लोगों को इस तरह के पर्चे थमाकर उन्हें तस्वीरें खिंचवाने पर मजबूर करना नागरिकों की निजता और मानवीय गरिमा के भी खिलाफ है।' इस बीच, लॉकडाउन के दौरान यहां खाकी वर्दी वालों का मानवीय चेहरा भी नजर आया जब कुछ पुलिसकर्मियों ने फुटपाथ पर रहने वाले बेघर लोगों के हाथ सेनेटाइजर से साफ कराए और उन्हें फल भी बांटे।

पुलिस ने बंदी के दौरान बाहर घूम रहे लोगों को एक पर्चा थमाकर फोटो खिंचवाने पर कथित रूप से मजबूर किया जिस पर छपा था-'मैं समाज का दुश्मन हूं। न मैं मास्क लगाऊंगा और न ही घर में रहूंगा।'

कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के कारण प्रशासन ने जिले में सोमवार से तीन दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। हालांकि, अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इसे 31 मार्च तक बढ़ाया जा सकता है।

निजी क्षेत्र के डॉक्टरों ने स्वैच्छिक सेवा देने की अपील पर समर्थन दिया

श्रीनगर, 24 मार्च (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में निजी क्षेत्र के डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों से स्वैच्छिक सेवा देने की अपील की थी, जिस पर मंगलवार को जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली।

श्रीनगर के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने ट्वीट किया कि यकीन नहीं कर सकता कि पांच मिनट में 36 ईमेल। कृपया, नाम, उम्र, योग्यता, मोबाइल नंबर, पता, भेजिए। अगर आवास की जरूरत है (हां/ना) और कोई विशेष जरूरत हो तो वह भी बताइए। हम संपर्क करेंगे। उन्होंने कुछ समय पहले एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या निजी क्षेत्र का कोई डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी स्वेच्छा से कोविड-19 महामारी से लड़ने में सरकार की कोशिश में मदद करने को तैयार है? उन्होंने कहा कि इससे पहले से काम कर रहे हमारे डॉक्टरों की मदद होगी।

www.readwhere.com